The House then adjourned at in ten minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at two of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, let us now proceed with the Motion of Thanks on the President's Address. Shri Amit Anil Chandra Shah to initiate the Motion.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (गुजरात)ः माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाएः-

> "राष्ट्रपति जी ने 29 जनवरी, 2018 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्य सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

माननीय सभापति महोदय, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि आज इस महान और ऐतिहासिक सदन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें मैं भी सम्मिलित होने जा रहा हूं। आज मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं गुजरात के विधान मंडल और गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ चुन कर भेजा, तो मैं इस महान सदन के सदस्य के रूप में आप सबके बीच खड़ा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर हम ध्यान से देखें, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पर इस सरकार की उपलब्धियों को हम सबके सामने रखा है। इस पर आम तौर पर सदन के बाहर भी चर्चा होती है, इन उपलब्धियों पर अनेक प्रकार की टीका-टिप्पणियां होती हैं और कुछ मर्मज्ञ इसका विश्लेषण भी करते हैं। जब मैं उन विश्लेषणों को देखता हूं, तब मुझे लगता है कि विश्लेषण का स्वागत जरूरी है, मगर मैं उसमें एक अलग दृष्टिकोण भी जोड़ना चाहता हूं। महोदय, हमें यह देखना पड़ेगा कि अभी सरकार की ये जो उपलब्धियां हैं, इस सरकार को विरासत में क्या मिला, सरकार ने जब कामकाज संभाला, तब सरकार के पास विरासत में क्या था। जिस प्रकार का गड्ढा था, वह गड्ढा भरने में ही सरकार का बहुत सारा समय गया है और गड्ढा भरने के बाद इन उपलब्धियों को हमें एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... अब थोड़ा सुनिए न। हम आपको भी सुनेंगे।

MR. CHAIRMAN: Please no running commentary by anybody while sitting, either from this side or that side. It is for the first time that the Member is speaking. ...*(Interruptions)*... It is his maiden speech. I will have to name you. ...*(Interruptions)*... If anybody speaks while sitting and makes comments, that is very serious matter, not just about this but about any issue. यह क्या स्वभाव है?

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः सभापति महोदय, 2013 में देश की जो स्थिति थी, हमें उसको याद करना पड़ेगा। 2013 में देश की स्थिति क्या थी? देश एक ऐसे प्रश्न के वक़ार के नीचे जी रहा था कि यह देश कि दिशा में जा रहा है, देश का भविष्य क्या होगा, यह महान देश अपनी विकास की गति को कहीं रोक तो नहीं देगा? इस प्रकार का एक भय था। यह वक़ार पूरे देश के जनमानस पर छाया हुआ

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

था। महिलाएँ अपने आपको असुरक्षित महसूस करती थीं। सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठौर-ठिकाना नहीं था। सीमा की रक्षा करने वाले जवान ...(**व्यवधान**)... सीमा की रक्षा करने वाले जवान सरकार की अनिर्णायकता के कारण अपने शौर्य का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे। युवा आक्रोशित था। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, scams की एक series इस देश की जनता के मानस पटल पर बहुत बड़े सवाल कर रही थी। उसी वक्त एक सवाल खड़ा हुआ कि उस सरकार को policy paralysis हो गया है, नीतिगत मामलों में सरकार को लकवा लग गया है। पूरे देश ने मानो एक साथ निर्णय किया कि देश की परिस्थिति को बदलना चाहिए। इतने में ही 2014 में चुनाव आया और 2014 के चुनाव में इस देश की महान जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। महोदय, तीस साल से इस देश में अस्थिरता चल रही थी और तीस साल से इस देश की जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया था। आज़ादी के बाद कभी भी इस देश की जनता ने किसी गैर-कांग्रेसी दल को बहुमत नहीं दिया था, लेकिन 2014 के चुनाव में, पूरे देश की जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से द्वारका तक, एक मेंडेट देकर उन सारी बातों को ध्वस्त कर दिया। आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल की सरकार बनी और वह थी, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार।

सभापति महोदय, 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला, किसी एक दल को मेंडेट मिला कि आइए, अपनी पॉलिसी के आधार पर इस देश को आगे ले जाइए और इस देश की जनता के मन में जो सवाल हैं, इस देश की जो समस्याएं हैं, आप उनका समाधान ढूंढिए। अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मेंडेट था और यह मेंडेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम चुनाव में गठबंधन के साथ गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी हमने एनडीए को सरकार में सम्मिलित किया और सारे एनडीए के साथियों ने, हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए, आज इस सरकार की यात्रा को आगे बढ़ाया है।

महोदय, जब किसी सरकार की रचना होती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, नेता का चुनाव। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने प्रधान मंत्री पद के प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था, परन्तु यहीं, सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे चुने हुए सांसदों की बैठक हुई, जिसमें नेता के चयन की प्रक्रिया हुई और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं भी उस प्रक्रिया का एक हिस्सा था।

सभापति महोदय, जब श्री नरेन्द्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया था, उस वक्त नरेन्द्र भाई ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सरकार बनने जा रही है, वह गरीबों की सरकार होगी, वह किसानों की सरकार होगा, वह दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की सरकार होगी, वह युवाओं की सरकार होगी, वह महिलाओं की सरकार होगी और वह गांधी और दीनदयाल जी के स्वप्नों को पूर्ण करने वाली सरकार होगी, गांधी और दीनदयाल जी के रास्ते पर चलने वाली सरकार होगी।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत आनन्द हो रहा है कि आज साढ़े तीन साल हो गए हैं और इन साढ़े तीन सालों में यह सरकार अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर चली है। यह अंत्योदय का सिद्धांत क्या है? आज अगर आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों के सामने मैं इसको सरल भाषा में रखूं, तो कहना चाहूंगा कि अंत्योदय का सिद्धांत वह है, जो विकास की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा

है, उसको विकास की पंक्ति में अग्रिम खड़े हुए व्यक्ति के बराबर कर देना या इस प्रकार से आगे बढ़ना कि सबको एक समान विकास मिले।

माननीय सभापति महोदय, आज जब हम साढ़े तीन साल के बाद पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस देश के संसदीय लोकतंत्र का इतिहास इतना छोटा नहीं है, हमारे संसदीय लोकतंत्र को 70 साल हो गए हैं। इन 70 सालों में कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं। जब सरकारें 25-30 या 35 साल चलती हैं, तब दो-तीन ऐसे बड़े काम होते हैं, जिनको इतिहास में दर्ज करना पड़ता है, लेकिन यह सरकार साढ़े तीन साल चली है, लेकिन पचास से ज्यादा ऐसे काम हैं, जिनको इस देश के इतिहास में स्थान मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, अंत्योदय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए, शुरू से ही गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सूझ-बूझ के साथ, सातत्य के साथ, टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं, कंटीन्युइटी के साथ विकास करना तय किया और इस क्रम में जो सबसे पहला काम किया गया हैं, वह है जन-धन बैंक एकाउंट खोलने का काम।

सभापति महोदय, इस देश की 70 साल की आज़ादी में 55 साल तक एक ही पार्टी का राज रहा है और यदि मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो कहना चाहूंगा कि एक ही परिवार का शासन रहा है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि 70 साल की आज़ादी के अंदर, 55 साल के कांग्रेस शासन के बाद 60 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिनके घर में एक भी बैंक एकाउंट नहीं था। आप व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी फैमिली के अंदर, एक बैंक एकाउंट भी नहीं था। वे सरकारें किस तरह से चली होंगी? उन सरकारों का विज़न क्या होगा? उन सरकारों का दृष्टिकोण क्या होगा कि वे 70 साल की आज़ादी के बाद एक गरीब व्यक्ति के घर में एक बैंक एकाउंट भी नहीं दे पाए। जब प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की हम जन-धन योजना की शुरुआत करेंगे और हर घर में मिनिमम एक बैंक एकाउंट पहुंचाएंगे, तब मेरा मन भी आशंकित था। मैं सोच रहा था कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वह कैसे हो जाएगा? मगर आज देखिए साहब, इस देश में गरीबों के 31 करोड़ बैंक एकाउंट खोले गए हैं और हर परिवार में एक बैंक एकाउंट उपलब्ध है। आज शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, जिसका बैंक एकाउंट न हो। सभापति महोदय, हमारी मीमांसा की जाती थी और हमारे ऊपर टीका-टिप्पणी की जाती थी कि बैंक एकाउंट तो दे दिया, उसमें जमा कराने के लिए पैसे कहां से आएंगे और गरीब उसमें क्या जमा करेगा? वैसे तो हमने ज़ीरो बैलेंस की व्यवस्था की थी, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जब ये जन-धन योजना के अंतर्गत लगभग 31 करोड़ एकाउंट खुले, तो उनमें 73 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं। गरीबों की गाढ़ी कमाई के इतने रुपए उन एकाउंट्स में जमा हैं। जो गरीब पहले उसे अपनी झोंपड़ी में रखता था, अपने गल्ले में रखता था, उसके इस धन की कभी चोरी हो जाती थी या साहूकार के यहां रखता था, तो कभी लुट जाता था, लेकिन आज वह पैसा बैंक एकाउंट्स में सुरक्षित है और वह अपने आपको इस देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ा हुआ पाता है।

सभापति महोदय, वर्ष 2014 में जब यह योजना शुरू हुई थी, उस समय 77 प्रतिशत zero balance accounts थे और आज उनकी संख्या घटते-घटते 20 प्रतिशत से कम हो गई है। सभी गरीब अपने बैंक एकाउंट्स का उपयोग करने लगे हैं। मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

सभापति महोदय, इस देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है, उसे देखते हुए किसी को किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहना बहुत कठिन होता जा रहा था। कटु बात कहना, कटु बात सुनना, इसका स्वभाव ही हमारा लुप्त होता दिखाई पड़ रहा है। यदि इतिहास, पास्ट या भूतकाल में जाकर देखें, तो सबसे अंतिम घटना उस समय की है जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त कहा था कि इस देश के पास चावल नहीं हैं, इसलिए शनिवार को सभी लोग उपवास करें, यानी एक समय का खाना छोड़ दें। ...(**व्यवधान**)... त्रिपाठी जी, धन्यवाद। आपने ठीक कहा-सोमवार। उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सोमवार को खाना छोड़ दें और उस समय सभी लोगों ने उनकी इस बात का सम्मान किया।

सभापति महोदय, शास्त्री जी के बाद, पहली बार ऐसी हिम्मत, इस देश के अभी के प्रधान मंत्री और हमारे नेता, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा जो सम्पन्न लोग हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा है, जिन्हें आर्थिक दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, वे लोग अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस गैस की सब्सिडी को सरकार गरीबों को देना चाहती है, दलितों को देना चाहती है और ग्रामीण गरीबों को देना चाहती है। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 1 करोड़ 23 लाख लोगों ने प्रधान मंत्री की अपील को सम्मान देते हुए गैस की सब्सिडी को छोड़ा है। उसके बाद क्या किया, यदि कोई और प्रधान मंत्री होता, तो वित्तीय घाटा कम कर लेता और उस सब्सिडी को तिजोरी में जमा कर लेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार तथा हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बची हुई सब्सिडी में खजाने का और पैसा लगाकर 'उज्जवला योजना' शुरू की।

सभापति महोदय, 70 साल की आजादी के बाद, डेढ़ करोड़ ग्रामीणों के पास गैस नहीं थी। उनकी झोंपड़ी में गैस का चूल्हा नहीं था। स्वच्छ ईंधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने तथा हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक संवेदनशील फैसला लिया कि पांच साल में पांच करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देंगे। अभी इस सरकार को लगभग साढ़े तीन साल हुए हैं और 3 करोड़ 30 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम पूरा कर लिया गया है और इसी बजट में यह सरकार 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर देने का प्रयास कर रही है।

सभापति महोदय, आज हमारे सदन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जिन्हें लगता है कि 21वीं सदी में गैस का सिलेंडर विकास का पैमान हो सकता है। मैं कोई गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन गरीबी को मैंने देखा है। डांग के जंगलों में जितने आदिवासी हैं, उन्हें देखा है। पूर्वांचल में गरीबों को देखा है। एक बूढ़ी मां जब अपनी झोंपड़ी के अंदर कंडे और टहनियां जलाकर रसोई बनाती है या खाना बनाती है और उसकी पूरी झोंपड़ी जब धुएं से भर जाती है, तो कोई बुरी आदत नहीं होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुंआ उस मां के फेफड़ों के अंदर घुस जाता है और उसके स्वास्थ्य को शनैः-शनैः हानि पहुंचाता रहता है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी ने करोड़ों मांओं को धुंआमुक्त घर देकर, उन्हें, उनके बच्चों, उस घर के बूढ़ों और स्वयं मां के लिए एक स्वच्छ घर निर्माण करने का काम किया है। मुझे इस बात का विशेष आनंद है कि ये जो 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शंस दिये, उनमें से 30

प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिले हैं और 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, ऐसा ही एक फैसला शौचालय का हुआ। इसको स्वच्छता के अभियान के साथ जोड़ा गया। मगर यह स्वच्छता के अलावा भी अपने गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। सभापति महोदय, घर में शौचालय न होना — आज दिल्ली के लुटियन्स ज़ोन में रहने वाले लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं पड़ता है। काफी लोग ऐसे हैं, जिनको इस तकलीफ़ का ज्ञान भी नहीं होगा। परन्तु, सभापति महोदय, एक गरीब के घर की कल्पना कीजिए, जिसकी एक 16 साल की बच्ची सुबह कुदरती प्रक्रिया के लिए गांव के बीच से गुजर कर खुले में शौच क्रिया के लिए बैठती है और जब पूरे गाँव की नजर उस पर पड़ती है, तो वह बच्ची अपनी आँखें झुका लेती है। धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास हर रोज़, तिल-तिल कर टूटता है। उस बच्ची को अभी तय करना है कि मुझे कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देश के विकास में मैं किस तरह से अपना योगदान करूंगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास 16 साल की उम्र में ही टूट जाता है। वह देश के विकास की प्रक्रिया में आत्मविश्वास के साथ हिस्सेदार नहीं हो सकती। इसके दर्द को कोई सरकार इतने सालों तक नहीं समझी। बहुत सारे लोग योजना लेकर आये, मैं ऐसा नहीं कहता कि यह पहली योजना है, मगर योजना का स्केल देखिए। सभापति महोदय, हम 2022 में हर घर में शौचालय की व्यवस्था कर देंगे और 7 करोड़ के लक्ष्य को समाप्त कर दिया जायेगा। सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आंकड़े देखते हैं, उनको यह उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ेगी। परन्तु एक घर में शौचालय पहुँचने से स्वास्थ्य तो सुधरता ही सुधरता है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिलता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्तुत्य कदम उठाया है। मैं यहाँ इसलिए यह कहना चाहता हूं ताकि देश भर में संदेश जाये। उन्होंने शौचालय को एक नया नाम देने का काम किया है। उन्होंने शौचालय को 'इज्जत घर' का नाम देने का काम किया है। महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने शौचालय योजना के माध्यम से किया है।

सभापति महोदय, गरीब के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कहीं वृक्ष के नीचे प्लास्टिक की शीट पर सो जाना, कहीं ब्रिज के नीचे सो जाना, कहीं फुटपाथ पर या कहीं सर्दियों में बने हुए अस्थायी आवासों में रहना, यह उसका भाग्य बन गया था। हर व्यक्ति को घर देने का स्वप्न भी इस सरकार ने ही देखा है और द्रुत गति से इसकी समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विस्तारों में एक करोड़ 35 लाख आवास की योजना को मंजूर कर दिया गया है और शहरी क्षेत्रों में 70 लाख आवासों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

सभापति महोदय, इस सदन की चारदीवारों ने 'बेरोजगारी' शब्द का प्रयोग बहुत बार सुना होगा, बेरोजगारी पर बहुत बड़े-बड़े अभ्यस्त भाषण भी देखे होंगे, सुने भी होंगे। ...(**व्यवधान**)... आप पूरा सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... आंकड़ों के बहुत से भाषण भी सुने होंगे। बड़े-बड़े विद्वान अर्थशास्त्रियों को भी सुना होगा। मगर इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सका। मैं भी सुन रहा था, जब इस सदन के सदस्य, आनन्द शर्मा जी और बाकी सदस्य चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत तरीके से उठाया। यह वाजिब है। देश में बेरोजगारी की समस्या है। मैं इनकार नहीं करता। मैं मानता हूं

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

कि इस देश में बेरोजगारी की समस्या है। मगर 55 साल आपके शासन करने के बाद भी अगर यह समस्या है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका समाधान किसने नहीं ढूँढ़ा। हम तो 6 साल, 7 साल, 8 साल से ही काम कर रहे हैं। इस देश को चलाने का सौभाग्य हमें 8 साल के लिए मिला है। इतनी विकराल समस्या कोई 8 साल में उत्पन्न नहीं हुई है। जिस पार्टी ने इस देश पर 55 साल शासन किया, वह आज इस समस्या की बात उठा रही है, मगर मुझे इसका आनन्द है कि हमने इसका समाधान ढूँढ़ा।

सभापति महोदय, स्किल इंडिया, बेरोजगार युवाओं को स्किल्ड बनाना, स्टार्ट-अप, स्टैंड-अप और अन्त में मुद्रा बैंक। मैं इस मुद्रा बैंक के लिए विशेष रूप से इस सभा गृह का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसलिए, क्योंकि इंदिरा जी का जमाना था। वे हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री थीं। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने इस देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस वक्त क्या उनका भाषण था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंकों के दरवाजे गरीब के लिए खुल गए हैं! मगर इतने सालों तक बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए नहीं खुले, न उनके पास अकाउंट था, न उनको लोन मिलता था। लोन लेने के लिए जाते ही उनसे इनकम टैक्स नंबर मांगा जाता था। उसकी समस्या ही यही है कि उसको इनकम ही नहीं है, तो वह इनकम टैक्स नंबर कहां से लाएगा? उसको इनकम नहीं है, यही तो उसका सबसे प्रमुख प्रश्न है। ये बेरोजगार युवा दिशाविहीन होकर भटकते थे। आज मुद्रा बैंक के कारण साढ़े दस करोड़ युवाओं को दस हजार से लेकर दस लाख रुपए तक का लोन देने काम समाप्त कर दिया गया है और इसके तहत लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। सभापति महोदय, इसमें न गारंटी देनी है, न गारंटर लाना है, सूद भी कम रखा गया है। अभी-अभी मैं पढ़ रहा था, चिदम्बरम साहब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के तहत किसी ने पकोड़े बनाने का ठेला लगा दिया, इसको रोजगारी कहते हैं? हां, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी करके, मेहनत करके पकोड़े बनाने का काम करता है। अपने परिश्रम से, पसीना बहा कर, हजारों-लाखों-करोड़ों युवा, जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकोड़े बनाने का काम कर रहे हैं, छोटी-छोटी स्वरोजगारी कर रहे हैं, उनको आप भिक्षुक के साथ compare करेंगे? यह किस प्रकार की मानसिकता है? सभापति महोदय, पकोड़े बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि इसको भिक्षुक के साथ compare करना शर्म की बात है। सभापति महोदय, वह बेरोजगार था, आज पकोड़े बनाने का काम कर रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, इस देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी। कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधान मंत्री बन कर इस सदन में बैठा है। ...(**व्यवधान**)... इनको मालूम नहीं है कि पकोड़े बनाने वाले का भी उतना ही महत्व है।

MR. CHAIRMAN: Please. आपको क्या बीमारी है? आपके नेता हैं, वे बाद में बोलेंगे। वे effectively counter करेंगे, आपको क्यों चिंता है? उनकी सामर्थ्य के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि अपने परिश्रम से, अपना पसीना बहा कर अपने जीवन यापन करने वाला हर व्यक्ति उतना ही बड़ा है, जितने हम इस सदन में बैठे हुए लोग हैं।

सभापति महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, इस देश में 70 साल की आज़ादी के बाद जब हमें इस देश की जनता ने शासन दिया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी दलों को शासन दिया, उस वक्त इस देश के अंदर 18 हजार गांव ऐसे थे, जहां बिजली छोड़ दीजिए, बिजली का खंभा या wire भी नहीं पहुंची थी। 18 हजार गांव! सभापति महोदय, मुझे आनंद है कि इस सरकार ने साढ़े तीन साल में 18 हजार में से 16 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। यह कोई कोरा वादा नहीं है। सरकार के विभाग की साइट पर इसकी सूची पड़ी हुई है, प्रांतवार सूची पड़ी हुई है। 16 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है और अठारहवीं सदी में जीते हुए उन गांवों को इक्कीसवीं सदी में लाने का काम इस देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

सभापति महोदय, बिजली गांवों में तो पहुंच गई, इसके बाद घर का क्या? घर में जब तक बिजली नहीं पहुंचती, उसके जीवन-स्तर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। बिजली के साथ शिक्षा जुड़ी है, बिजली के साथ स्वास्थ्य जुड़ा है, बिजली के साथ स्वच्छता जुड़ी है, इन सारी चीज़ों को गरीब के घर में कैसे पहुंचाएं? इसके लिए सौभाग्य योजना का विचार आया और सौभाग्य योजना के तहत 2022 तक इस देश के हर गरीब को मुफ्त बिजली का कनेक्शन देने का निर्धारण इस सरकार ने किया है और चार करोड़ कनेक्शन 16 हजार करोड़ रुपए की कॉस्ट से देने की शुरूआत हो गई है।

सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि हर गरीब के घर में शौचालय बनवाना, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाना, हर गरीब के घर में रोजगारी पहुंचाना, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाना, हर गरीब के घर में स्वास्थ्य पहुंचाना, इसी के लिए तो देश को आज़ाद करने के लिए हमारे पुरखों ने यह लड़ाई लड़ी थी। यह लड़ाई इसीलिए लड़ी थी और यह सरकार उसी दिशा में जा रही है।

जब कोई गरीब अकस्मात अस्वस्थ हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना? यह सरकार इसके लिए दो योजनाएं लाई। बहुत कम यानी मामूली से प्रीमियम में प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना के तहत 13 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा देने का काम समाप्त कर दिया गया है और प्रधान मंत्री ज्योति बीमा योजना के तहत साढ़े पांच करोड़, कुल मिला कर 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षित करने का काम किया गया है। जन-औषधि केन्द्र के माध्यम से, 3 हजार से ज्यादा पीएमबीजेपी केन्द्र से 800 से ज्यादा दवाइयां दस प्रतिशत से तीस प्रतिशत दाम पर गरीब के लिए उपलब्ध करा दी है। भगवान न करे कि किसी गरीब को दिल की बीमारी हो जाए, स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो स्टेंट की कीमत सुन कर ही उसको पहले अटैक आ जाता था। पहले जो 4 लाख रुपए का स्टेंट मिलता था, उसे 40,000 रुपए में और फिर 70,000 रुपए के स्टेंट को 8,000 रुपए में इस सरकार ने उपलब्ध कराया है। Artificial घुटने बिठाने के लिए पहले जो खर्च आता था, उसे भी बहुत कम कर दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, जब वित्त मंत्री जी सदन में बजट प्रस्तुत कर रहे थे। इस बजट में प्रधान मंत्री जी 'आयुष्मान भव योजना' लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत इस देश के 40 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य का खर्च बीमा के माध्यम से मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं, उस सब की लोक-कल्याण की योजनाओं को आप खंगालकर देख लें, देश के 50 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा देना, हैल्थ बीमा देना और 5 लाख रुपए का बीमा देने

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

का काम सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. की सरकार और माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मुझे मालूम है कि अब सामने से थोड़ी आवाज़ उठेगी, क्योंकि 'आयुष्मान भव भारत' को अब 'नमो हैल्थ' के नाम से इस देश की जनता बुलाने वाली है।

सभापति महोदय, कम्युनिस्टों के समर्थन से चलने वाली यूपीए-। सरकार ने भी न्यूनतम वेतन में इतना इज़ाफा नहीं किया था, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार द्वारा इसमें 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इसी प्रकार गरीब कल्याण के लिए इस सरकार ने अन्त्योदय के सिद्धांतों को, दीनदयाल जी के सिद्धांतों को चरितार्थ करने का निर्णय लिया है। मेरे पास बहुत लम्बी सूची है, मगर मैं यहां बहुत थोड़े बिन्दु ही उठाना चाहता हूं, क्योंकि अभी अनेक माननीय सदस्य भी बोलेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गरीब हटाओ के नारे से सत्ता में तो बहुत लोग आए, लेकिन वास्तव में गरीबी हटाने या गरीबों का जीवनस्तर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, 70 प्रतिशत लोगों का जीवन यापन कृषि पर आधारित उद्योगों और व्यवसायों पर निर्भर है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साढ़े तीन साल तक सातत्यपूर्ण तरीके से कृषि के सभी अंग-उपांगों को समाविष्ट करते हुए, कृषि में किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाए हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री Irrigation योजना अपने आप में विशिष्ट प्रकार की योजना है, जिसके तहत लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि माइक्रो-इरिगेशन के अंतर्गत लाई गई है। इससे पानी की बचत तो होगी ही, कृषि उपज में भी बढ़ोत्तरी होगी। महोदय, 285 नई परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनके अंतर्गत 1 करोड़ 88 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई से युक्त कर दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी परियोजना 'प्रधान मंत्री Irrigation योजना' के तहत शुरू हुई है, जिससे किसानों की किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा 30 नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को अटलजी की सरकार जाने के बाद छोड़ दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और एन.डी.ए. की सरकार आने के बाद, उन नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम फिर से आरम्भ किया गया है। सभापति महोदय, अब तक ऐसी तीन योजनाएं शुरू हो चुकी हैं और 30 योजनाएं आने वाले दो साल के अंदर हम हाथ में लेने वाले हैं। इससे देश के irrigated land में बहुत बड़ी योजनाएं होने वाली हैं।

सभापति महोदय, जब कुदरती आपदा आती है, तब किसान के साथ कोई नहीं होता। ऊपर भगवान होता है और नीचे धरती माता होती है। सालों तक इसमें दी जाने वाली राहत के norms को बदला नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार बनने के बाद, पहले ही साल राहत के लिए जो norms बने थे, किसानों की मदद के लिए, उसके amount को डेढ़ गुना किया गया और क्षेत्रफल में चार गुना की बढ़ोत्तरी की गई है। इस तरह किसान को दोनों तरफ से राहत देने हेतु बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। हम वैज्ञानिक assessment की भी एक नई पद्धति लाए हैं, ताकि जिसका नुकसान हुआ है, उसे तुरन्त राहत मिल पाए।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का जहां तक सवाल है, देश में बहुत सी फसल बीमा योजनाएं आईं, हो सकता है कि अभी जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आई है, इससे भी अच्छी योजना लाने का सौभाग्य हमारी ही सरकार को संभव है, 2019 के चुनाव के बाद, फिर से मिले। मगर, मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि यह "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" अपने आप में एक सम्पूर्ण प्रधान मंत्री फसल योजना है। अगर बुआई से लेकर खलिहान तक, पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी आपदा आ जाती है, किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, तो किसान को अपना फसल बीमा मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने इसके अंदर की है। इसमें हर गांव का अलग सर्वे किया जाना है। पहले केवल ब्लॉक्स के सर्वे होते थे, लेकिन अब ब्लॉक्स के सर्वे की जगह हर गाँव का सर्वे करने का निर्णय लिया गया है। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए आनन्द है कि पहले एकाध करोड़ के आस-पास किसान इसका फायदा उठाते थे, लेकिन वर्ष 2016-17 में 5 करोड़ 70 लाख किसानों ने इसका फायदा उठाया है और इसके अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है।

सभापति महोदय, किसान जो उत्पादन करता है, उसके अगर अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, तो किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता है। धीरे-धीरे इस देश की सभी मण्डियों को ई-मण्डियों में तब्दील करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। अभी काम थोड़ा धीरे चल रहा है, मगर दिशा सही है। 455 मण्डियों को ई-मण्डियों में कन्वर्ट कर दिया गया है और 31,000 करोड़ रुपए की बिक्री और क्रय इन्हीं मण्डियों के माध्यम से गत वित्तीय साल के अंदर हुआ है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, जबसे मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, यूरिया की किल्लत को हमने देखा है। गुजरात में तो यूरिया के कारखाने अभी भी चल रहे हैं, फिर भी गुजरात में किल्लत होती थी। जो उत्तर के राज्य हैं, वहां पर तो यूरिया के लिए लाठी भाँजने का समय आता था। चाहे रबी हो या खरीफ, किसान को आन्दोलन किए बगैर यूरिया नहीं मिलता था। यूरिया का उत्पादन तो कम था ही, परंतु यूरिया की कालाबाजारी भी बहुत बड़ी मात्रा में चल रही थी। सभापति महोदय, एक ही निर्णय, नीम-कोटेड यूरिया का किया गया। नीम-कोटेड यूरिया के कारण यूरिया का इंडस्ट्रीज़ में उपयोग समाप्त हो गया, वे कर ही नहीं सकते। इस नीम-कोटेड यूरिया के कारण इंडस्ट्री में जाने वाला यूरिया बाजार में आ गया, जिसके कारण आज सब किसानों को यूरिया मिलता है। यूरिया की खपत भी अब कम हो गई है और पेस्टिसाइड्स का खर्च भी कम हो गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सभासदों से यह कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर, सिन्दरी, बरौनी, तालचर और रामगुंडम के कारखानों में से हमने एक भी नया नहीं बनाया है। ये अलग-अलग सरकारों के समय से बन्द पड़ गए थे, जिनको चालू करने की सुध नहीं ली गई थी, ये छः के छः कारखाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से चालू किए। इन छः कारखानों के शुरू होने के बाद मुझे भरोसा है कि यूरिया इस देश में इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया के कारण उसकी खपत कम हुई है और इन छः कारखानों में उत्पादन शुरू होने के बाद ऐसा हुआ है।

सभापति महोदय, डेयरी के लिए भी 11,000 करोड़ रुपए की योजना रखी गई है। जैविक खेती के लिए भी एक अच्छा इनिशिऐटिव लिया गया है। लगभग साढ़े 22 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के नीचे लाने का काम कर दिया गया है।

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

सभापति महोदय, Soil Health Card पर मैं इसलिए विस्तार से बात करना चाहता हूं, क्योंकि यह एक नई चीज़ है और इस सदन के माध्यम से देश के किसानों तक इसकी बात जानी चाहिए। देश का किसान, जो अपने खेत-खलिहान के अंदर रहता है और हरदम पसीना बहाता है, उसको मालूम नहीं है कि उसकी मिट्टी में क्या चीज़ पड़ी है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, उसके अंदर कौन-सी क्रॉप होगी, यह उसको मालूम नहीं है, उसमें कितना पानी चाहिए, वह मालूम नहीं है, उसकी मिट्टी के तत्व क्या हैं, वह भी उसको मालूम नहीं हैं। उसमें कौन-सी खाद कितनी चाहिए, वह भी उसको मालूम नहीं है। पहले ये सारी चीज़ें लैबोरेटरीज़ के अंदर पड़ी होती थीं। सभापति महोदय, गुजरात में Soil Health Card का एक प्रयोग किया गया और हर किसान को उसकी अपनी भूमि का हेल्थ कार्ड दिया गया। उस हेल्थ कार्ड के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें कौन-सी क्रॉप्स अच्छी हो सकती हैं, उसमें कितना पानी चाहिए, कौन-सी खाद चाहिए। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और 14 भाषाओं में लिखी हुई होती हैं, स्थानीय भाषाओं में लिखी हुई होती हैं। लगभग साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा किसानों को Soil Health Card देने का काम इन तीन साल के अंदर समाप्त कर दिया गया है, 460 full-fledged प्रयोगशालाएं बना दी गई हैं और 4,000 मिनी लैब्स बनाने का काम भी एक तरीके से शुरू हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों के बारे में सबसे अंतिम बात यही कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद 70 साल के अंदर किसान को उसकी लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देना एक पॉलिटिकल नारा तो होता था और सबको लगता था कि यह एक पॉलिटिकल नारा है। जब एक पार्टी सत्ता में होती थी, तो उसके खिलाफ इसको दूसरी पार्टी उपयोग करती थी और जब दूसरी पार्टी सत्ता में आती थी, तो पहली पार्टी इसका उपयोग करती थी, लेकिन अब हमने यह व्यवस्था की है कि इसका उपयोग कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हर फसल के लिए, चाहे वह रबी हो या खरीफ, उसकी लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है। मैं मानता हूं कि आज़ाद हिन्दुस्तान में यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। सभापति महोदय, इसके कारण ही किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें White क्रांति, Blue क्रांति, नई Green क्रांति, micro-irrigation इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए यह कदम भी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में जाएगा। सभापति महोदय, यह सरकार जब से चली, इस सरकार का एक सिद्धांत रहा है कि हम फैसले ऐसे नहीं लेते हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं। सभापति महोदय, vote bank जेनरेट करने के लिए लोगों को अच्छे लगें, ऐसे फैसले लेने वाली सरकार हमने देखी है। यह सरकार ऐसी है जो लोगों के लिए अच्छे हों, ऐसे फैसले लेती है, लोगों को अच्छे लगें, ऐसे फैसले नहीं लेती है। सभापति महोदय, financial discipline के कारण सारे parameters improve हुए हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, हमारे साथी बोलेंगे। Agricultural growth rate जो मायनस .2 परसेंट था, वह 4.1 पर जाकर ठहरा है, मुद्रास्फीति 9.5 से 1.5 तक पहुंची है, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः Interest rate 8 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक चला है, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा यह सब अपने पैरामीटर्स को छूते हैं। FDI inflow भी बढ़ा है, अब तक का रिकॉर्ड Forex reserve 460 बिलियन डॉलर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में है, नरेन्द्र मोदी जी के शासन में है और इसके कारण बहुत सारे reforms भी किए गए हैं और इन reforms के कारण बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में से सरकार ने अपनी अंक तालिका में अंकों की छलांग लगाई है, चाहे वह Ease of Doing Business की ranking हो, getting electricity की रैंकिंग हो, Globalization Index हो, Global Competitiveness Index हो। बहुत सारी चीज़ों में हमने रैंक को आगे बढ़ाया है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा काम अगर किया गया है तो इस देश के मौसमों के हिसाब से बजट को लाने का फैसला किया है। पहले हम बजट को लाते थे 28 फरवरी को। पास होते-होते अप्रैल आ जाता था और बाद में मानसून आ जाता था। इस भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. की सरकार ने, इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक फैसला लिया कि एक फरवरी को इस देश का बजट आ जाएगा, इसके कारण बजट के implementation में अच्छी सहूलियत हुई है, रेलवे बजट को भी हमने perform कर दिया है।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा सुधार इस सरकार ने किया है, जिसका नाम है जी.एस.टी.। जी.एस.टी. अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है। दुनिया में सबसे बड़ा बिक्री और सेवा कर का अगर कोई सुधार हुआ है तो हिन्दुस्तान का जी.एस.टी. के प्रति अर्थतंत्र का जो हमारा आकार है, उसमें कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इतने सारे राज्य, इतने सारे दल, इसमें कभी जी.एस.टी. इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में "एक देश, एक कर" का स्वप्न साकार कर लिया है, पूरे देश में एक समान कर की व्यवस्था हुई है। माननीय सभापति महोदय, इस पर बहुत सारी राजनीति सदन के बाहर हुई। मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में जो सत्य है, हकीकत है वह कहनी चाहिए। सबसे पहले तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जब कांग्रेस की सरकार थी तब जी.एस.टी. का विरोध किया था। सभापति महोदय, यह बात सत्य नहीं है। मैं बताता हूं सुन लीजिए न, मैं बताता हूं, सुनिए आनन्द जी, आप सुनिए। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जी.एस.टी. का विरोध नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जी.एस.टी. के तरीकों का विरोध किया था। सरकारों को क्यों भरोसा नहीं था, क्योंकि यू.पी.ए. सरकार कर सुधार लेकर आई थी। सी.एस.टी. को 4 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट कर लिया था। आपको याद होगा कि 4 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट हुआ था। जो राज्यों को घाटा था, वह आप लोगों को चुकाना था। यूपीए सरकार को चुकाना था, लेकिन वादाखिलाफी हुई, राज्यों को घाटा नहीं चुकाया गया - 37 हजार करोड़ रुपए एनडीए सरकार ने चुकाने का काम किया। राज्यों को भरोसा क्यों नहीं था? Federal Structure की भावना को किसने नष्ट किया? जब एक वचन दिया जाता है और उस वचन का पालन नहीं होता है तो कोई भरोसा नहीं करेगा। सब राज्य चिंतित थे। सब राज्य जीएसटी से नहीं डरते थे, जीएसटी के कारण राज्यों पर जो बोझ पड़ने वाला था, उससे डरते थे। सब कहते थे कि implementation के वक्त अगर आय कम हुई तो हम अपने राज्य को कैसे चलाएंगे, राज्य की जनकल्याण की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? राज्य की जनकल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

संबंध में उनके मन में एक सवाल था, जिसका समाधान हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने ढूंढा। 14 प्रतिशत रेवेन्यु पर बढ़ोत्तरी देने का वादा किया गया तब जाकर सभी राज्य सहमत हुए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः मधुसूदन जी, प्लीज़।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात)ः सर, यह हकीकत नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप बाद में अपनी बात कहिएगा। बाद में जब आपको मौका मिलेगा, तब बोलिएगा। ...(**व्यवधान**)... That will not go on record. Why do you waste your energy?

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः सभापति महोदय, हमने 14 परसेंट revenue growth का जो वादा किया, वह सिर्फ शाब्दिक वादा नहीं था, वह सीएसटी की तरह शाब्दिक वादा नहीं है, हर राज्य को Constitutional guarantee दी गयी है कि अगर आपकी आय कम होती है तो भारत सरकार उसका भुगतान करेगी और 22 राज्यों को आज उस नुकसान का भुगतान भारत सरकार कर रही है - इसलिए भरोसा बना है। विरोध इसलिए था कि भरोसा नहीं था, हमने भरोसा पैदा हो, ऐसा काम किया, ऐसा रास्ता ढूंढा, तब जाकर जीएसटी पास हुआ है।

सभापति महोदय, जीएसट को इतने विकराल तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है, जैसे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली हैं, देश का व्यापार बंद हो जाएगा, छोटे और मंझले व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, लघु उद्योग बंद हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने इसकी deep study की है। सभापति महोदय, ऐसा कुछ नहीं होगा। जीएसटी के कारण देश का व्यापार बढ़ने वाला है, लघु उद्योग और छोटे व्यापारी और मजबूत होने वाले हैं।

सभापति महोदय, पहले इस देश की स्थिति क्या थी? 17 प्रकार के अलग-अलग टैक्स थे - excise से लेकर octroi तक 17 टैक्स और 23 प्रकार के सेस लगते थे - 17 टैक्स और 23 सेस - उन्हें समाप्त करके एक टैक्स बनाया गया। सभापति महोदय, इससे व्यापारी की दिक्कत कभी बढ़ नहीं सकती है, कम होती है। पहले 15 इंस्पेक्टर्स को अपने books of accounts दिखाने पड़ते थे, आज उन्हें एक ही इंस्पेक्टर से डील करना है। जिन सदस्यों को संशय है कि जीएसटी के माध्यम से दिक्कतें बढ़ेंगी, मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि एक बार जब चुंगी की रेड हो जाती है, उस समय आप व्यापारी को जाकर मिलिए। अग्रवाल जी यहां बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि जब चुंगी की रेड होती है तब क्या होता है। टोल टैक्स के नाके पर जो एक-एक दिन की लम्बी ट्रक्स की लाइनें लग जाती थीं, उस वक्त स्थिति क्या होती थी? उस वक्त ट्रक्स का उपयोग कितना कम हो जाता था, उस समय transportation कितना महंगा पड़ता था, यह जरा उनसे पूछिए। 15 इंस्पेक्टर्स की जगह अगर एक एक इंस्पेक्टर आपके books of accounts को देखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापारी इसका विरोध करेगा। मगर हां, सभापति महोदय, teething problem है, शुरुआती दिक्कतें आयी हैं और शायद अभी भी थोड़ी बाकी होंगी। जब 23 cess और 17 taxes को आप मर्ज कर लेते हैं, एक टैक्स बनाते हैं तो शुरुआती दिक्कतें आती हैं, लेकिन यह सरकार संवेदनशील सरकार है। जीएसटी के आने

के तीन महीने के बाद इस सरकार ने एक बहुत बड़ा संवाद का अभियान चलाया। सारे संसद सदस्य, सारे अधिकारी, सारे मंत्री Chamber of Commerce में गए, छोटे व्यापारियों के पास गए, लघु उद्योग वालों के पास गए और उन्हें सुनने की प्रक्रिया की। सभापति महोदय, उस संवाद में से बहुत सारी चीज़ें निकलकर आयीं कि दिक्कतें क्या हैं? उन दिक्कतों को एक-एक करके resolve करने की शुरुआत की और 23 मीटिंग्स में 30 से ज्यादा procedural changes करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये जो सारी मीटिंग्स हुईं, उनमें रेड के लिए हो-हल्ला किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूं कि 400-चीजों के दाम इन 23 मीटिंगों में कम कर दिए गए। 1100 में से 150 चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया। लगभग 1100 में से 550 चीजों पर टैक्स कम करने का काम GST आने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 30 procedural changes किए हैं और सभापति महोदय, सामान्यतः आम सभाओं में कहा जाता है कि यह जो GST है, केवल भारतीय जनता पार्टी का बेबी है। GST Council बनी है। ...(**व्यवधान**)... GST Council में हर राज्य का मुख्यमंत्री आता है, हर राज्य का वित्त मंत्री आता है और वे GST Council में अपनी-अपनी राय रखते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि GST Council की 23 से 25 मीटिंगें हुईं हैं, एक भी प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ है, सारे के सारे प्रस्ताव unanimous हैं। अगर आप विरोध करते हो, विपक्ष के मित्र अगर विरोध करते हैं तो आपका भी एक मत यहां है और मैं विशेषकर कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा कि इन 23 मीटिंगों में अलग-अलग 91 मंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के आए हैं और उन्होंने सहमति दी है और यह आपकी सहमति से हुआ है। GST Council में एक भाषा, सदन में दूसरी भाषा और आम सभा में तीसरी भाष यह किस प्रकार की राजनीति है? किस प्रकार से हम देश को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम GST Council के minutes प्रकाशित करें? आप मुझे सुनो। आपको मुझे 6 साल तक सुनना पड़ेगा। आप मुझे रोक नहीं सकते, सभापति ही रोक सकते हैं। सभापति महोदय, क्या हम इसके minutes को सार्वजनिक करें कि इसमें फलां पार्टी की भी सहमति है, फलां पार्टी की भी सहमति है, फलां पार्टी की सहमति है कोई पार्टी बाकी नहीं है। सबकी सहमति है क्योंकि सर्वानुमति से फैसला हुआ है। सभापति महोदय, शब्द क्या उपयोग होते हैं - गब्बर सिंह टैक्स। कौन है यह गब्बर सिंह? एक मशहूर हिंदी फिल्म थी शोले। उसमें एक डकैत के पात्र का नाम गब्बर सिंह है। यह डकैत कौन है? कानून से बना हुआ टैक्स वसूल करना क्या डकैती है? कितनी समझ रखते हैं ये लोग? जो इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं और गब्बर सिंह टैक्स जाता कहां है, यह GST जाता कहां है? सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह टैक्स One Rank, One Pension देने के लिए जवानों के bank accounts में जाता है, शहीद की विधवा के bank account में जाता है, गरीब महिला को उज्जवला योजना देने के लिए जाता है, गरीब को घर देने के लिए जाता है, सौभाग्य योजना के तहत उसको बिजली देने के लिए जाता है। लोगों को कर न देने के लिए उकसाना, यह राजनीति की अच्छी निशानी नहीं है। हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हम सबको सोचना पड़ेगा। यह कोई दल की बात नहीं है। आज हम हैं, कल आप भी आ सकते हो। ...(**व्यवधान**)... हां, हां, आ सकते हो। ...(**व्यवधान**)... हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है कि हमेशा हमारा ही शासन रहेगा। यह लोकतंत्र है, जनता किसी को भी सत्ता में बैठा सकती है, 5 साल आप भी बैठे हो। ...(**व्यवधान**)... देश इस तरह से नहीं चलता है, देश कुछ मुद्दों में

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चलाना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि GST इस देश का भविष्य सुधारने वाला एक अच्छा reform है, इसमें आप सब सहयोग करिये। जनता का मन बनाने के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए, ऐसी मैं अपील मात्र कर सकता हूं। सभापति जी, बाकी तो राजनीति करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र पड़े हैं। सभापति जी, infrastructure के मामले में भी इस सरकार ने बहुत सारे achievements प्राप्त किए हैं। Road construction में लगभग डेढ़ गुना, National Highway construction में दोगुना, National Highway Construction के order देने में साढ़े चार गुना, rural road construction में दोगुना, fund के मामले में तीन गुना। 2014 में village connectivity के मामले में 56 प्रतिशत गांवों को road से जोड़ा गया था। आज 82 प्रतिशत गांवों को roads से जोड़ने का काम समाप्त कर दिया गया है। सभापति महोदय, 5,29,245 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का काम समाप्त हो गया है। वर्ष 2013-14 में नई रेलवे लाइन का construction 360 किलोमीटर था और वर्ष 2016-17 में 953 किलोमीटर है। Broad-gauge conversion में 750 किलोमीटर थी इसको 1000 किलोमीटर तक पहुंचाया गया है, double trekking railway line को 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 882 किलोमीटर कर दिया गया है और railway outlay को बढ़ाकर ढाई गुना कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 में एक लाख 31 हजार करोड़ रुपये रेल विभाग के लिए आबंटित किए गए। ग्रॉस रेवेन्यू में भी 19 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का काम किया है और एयरपोर्ट्स की संख्या को हमने दोबारा चुनाव में जाने से पहले-पहले पांच गुना करने का लक्ष्य रखा है।

सभापति महोदय, मैं बैंकिंग की बात कह चुका हूं, इसलिए आगे इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

सभापति महोदय, पावर सेक्टर के अंदर भी बहुत सारा काम हुआ है। Installed Capacity जैसे पहले हमारी 243 मेगावॉट थी, अब यह 333 मेगावॉट है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जो 2,51,000 किलोमीटर थी, उसको 3,81,090 किलोमीटर बढ़ाया गया है। पीक पावर डेफिसिट 9 परसेंट था, उसको 1.6 परसेंट तक सीमित कर दिया गया है, मतलब यह है कि पावर सरप्लस स्टेट बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। Installed Wind Capacity 21 गीगावॉट की जगह 31 गीगावॉट हो गयी है। सोलर पावर टैरिफ 12 रुपये यूनिट खरीदी जाती थी, अब ढाई रुपये यूनिट सोलर पावर खरीदी जाती है। Installed Solar Capacity 2.6 गीगावॉट थी, अब इसकी जगह 12 गीगावॉट कर दी गयी है। Un-electrified Villages की संख्या 18,542 थी और अब सिर्फ 1,948 गांव बिना बिजली के रह गए हैं। कोल प्रोडक्शन 462 मिलियन मीट्रिक टन था, अब यह बढ़कर 554 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। सभापति महोदय, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मगर मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है। ...(**व्यवधान**)... बाकी के लोग बोलेंगे, आप चिंता मत करिए।

सभापति महोदय, किसी भी देश की सुरक्षा प्रत्येक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। देश की सुरक्षा तब तक ठीक से नहीं हो सकती, जब तक उसका जवान, फौजी अपने आपको सुरक्षित और गौरवान्वित न समझे। इस देश के जवान 40 साल से "वन रैंक, वन पेंशन" की मांग करते थे। अनेक सरकारें आयीं और अनेक सरकारें गयीं, "वन रैंक, वन पेंशन" को छूता नहीं था, अगर किसी ने किया,

तो चुनाव के वक्त पर 100 करोड़ का एक टोकन बजटरी प्रोविजन करके जवानों को झांसा देने का काम किया।

सभापति महोदय, एनडीए की सरकार आयी, भाजपा सरकार आयी, जब नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री जी बने, हमारा चुनावी वायदा था और हमने एक ही साल में "वन रैंक, वन पेंशन" को लागू करके देश के जवानों को हर साल 8,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है, इससे उनका हौसला बढ़ा है।

सभापति महोदय, जवान चाहे 44 डिग्री टेम्परेचर में कच्छ या राजस्थान के रेगिस्तान में काम करता हो या माइनस 44 डिग्री टेम्परेचर में पहाड़ों की चोटियों पर काम करता हो, उसके परिवार की चिंता करना, यह सरकार अपना फर्ज़ समझती है और "वन रैंक, वन पेंशन" मैं मानता हूं कि उनके लिए बहुत बड़ी राहत है और इसे लागू करके हमने उनकी समस्या का समाधान कर दिया है।

सभापति महोदय, इस देश में कई बार आतंकवादी हमले हुए। आतंकवादी हमले देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों के थानों पर भी हुए हैं, इनके कैम्पों पर भी हमले हुए और बहुत सारे जवान हताहत भी हुए हैं। मगर इतने सारे समय के अंदर किसी ने भी इसका जवाब देना उचित नहीं समझा था। एक दिन सबेरे उरी में तड़के, सुबह तीन बजे पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया, 12 जवानों को जिंदा जला दिया गया। यह कायरतापूर्ण हमला था और उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। वहां पर जिंदा जवान जल गए, सोते-सोते जवान जल गए। पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था और हताशा थी कि अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। पहले क्या हुआ था, प्रधान मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आएगा, सब दुख व्यक्त करेंगे, आक्रोश व्यक्त करेंगे और फिर बात समाप्त हो जाएगी। सभापति महोदय, इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी थे, वे एक शब्द भी नहीं बोले, उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। दस दिन के अंदर, अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया और अपने वीर जवान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की सीमा के अंदर जाकर, आतंकवादियों से अपने जवानों का बदला लेकर सुरक्षित वापस आ गए। और जिस क्षण ये जवान वापस आए, वह क्षण देश की सुरक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था और उसी क्षण दुनिया का देश को देखने का नज़रिया बदल गया। दुनिया को लगा कि अमेरिका और इज़रायल के बाद भारत एक ऐसा देश है, जो अपनी सीमाओं और जवानों की सुरक्षा ठीक प्रकार कर सकता है। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि इस से दुनिया का भारत को देखने का नज़रिया बदला है। देश की सुरक्षा कितनी अहम है, इस का परिचय देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने surgical strike के माध्यम से दिया है। महोदय, बाद में भी तीनों सेनाओं के modernisation के संबंध में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं करता, मगर हमारे शासन में आने के समय यह काम ठप्प था। हमने 10 साल का blueprint बनाकर तीनों सेनाओं के modernisation के काम को आगे बढ़ाया है और तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से लैस बनाने का काम किया है। हमने इनकी संचार व्यवस्था को भी चुस्त-दुरुस्त करने का काम किया है। महोदय, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी 18,000 करोड़ रुपए police modernisation के लिए दिए गए हैं।

सभापति महोदय, police modernisation बी.जे.पी. के साथ जुड़ा शब्द है। यह इसलिए बी.जे.पी. के साथ जुड़ा है क्योंकि पहले जब एन.डी.ए. की सरकार आयी थी, तो modernisation शुरू

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

हुआ था। बाद में एन.डी.ए. की सरकार गयी और यू.पी.ए. की सरकार आयी, तो modernisation बंद हो गया था। अब फिर से एन.डी.ए. की सरकार आने के बाद police modernisation शुरू हुआ है। महोदय, सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा के लिए मजबूत बनाना, उनका modernisation करना इस सरकार की priority है और इस कार्य को हमने आगे बढ़ाया है।

सभापति महोदय, कश्मीर समस्या हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। हमने जब वहां नई सरकार बनने के बाद शासन संभाला और कड़ाई शुरू हुई तो देशभर में सब लोगों में एक चर्चा चली कि इस सरकार की कश्मीर नीति सफल है या विफल है? यह कैसी नीति है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? कश्मीर हमारे हाथ से तो नहीं चला जाएगा? मगर आज मैं कह सकता हूं कि कश्मीर विगत 35 सालों में सब से ज्यादा सुरक्षित और शांत प्रदेश है। आज हवाला के माध्यम से विदेश से पैसा लेकर अलगाववाद और terrorism फैलाने वाले सारे लोग तिहाड़ जेल के अंदर अपने दिन काट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस तरह हमने कश्मीर की समस्या को बहुत अच्छे तरीके से handle किया है।

महोदय, सरकार ने सामाजिक बदलाव के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं। सब से पहला काम काका साहेब कालेलकर कमीशन के वक्त से इस देश का पिछड़ा वर्ग इस घड़ी की प्रतीक्षा में था कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिले। भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का बिल दूसरे सदन से पास किया है। इस तरह देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों की आशा व अपेक्षा को पूरा करने के लिए हम बिल लेकर आए। हमने यह बिल लोक सभा से पारित करा दिया, मगर अभी तक, महोदय "अभी तक" शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक यहां वह बिल पास नहीं हो सका है क्योंकि यहां हमारा बहुमत नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): आप बिल लाइए, हम पास कराने के लिए तैयार हैं।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः हम तो लेकर आए थे और यह बात रिकॉर्ड पर है कि स.पा. समर्थन करेगी। सभापति महोदय, हम तो यह बिल राज्य सभा में लेकर आए थे, मगर कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने इस का विरोध किया ...(**व्यवधान**)...

श्री बी.के. हरिप्रसाद (कर्नाटक): हम ने विरोध नहीं किया। हमने उस में संशोधन करने के लिए कहा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Hariprasad, please sit down.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): कांग्रेस ने विरोध किया था।

श्री सभापतिः रामदास जी, आप मंत्री हैं।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः सभापति महोदय, मैंने सदन में 'विरोध' शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि विरोध का तरीका बदलने से विरोध बंद नहीं हो जाता है। आपने विरोध का तरीका

3.00 P.M.

अलग चुना है। आप यह मत मानिए कि जनता यह समझती नहीं है। वह सब कुछ जानती है। जब आप चुनाव में जाएंगे तो कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, देश के ओ.बी.सी. वर्ग को जवाब देना पड़ेगा कि उसने इनके सम्मान की इस बात को क्यों रोका? सभापति महोदय, पूरा देश देख रहा है। मैं तो आज भी सारी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते अपील करना चाहता हूं कि इस बिल में कोई राजनीति नहीं है बल्कि पिछड़े वर्ग को सम्मान दिलाने की बात है। इसलिए आइए हम सब साथ मिलकर इस बिल को पास करें।

सभापति महोदय, इस देश की मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिलने से लेकर अब तक, इतने सालों से न्याय नहीं मिला था। ट्रिपल तलाक के कानून को कई बार ...(**व्यवधान**)... आप इसको सुनिए। कई बार देश की अलग-अलग अदालतों में इसको चैलेंज किया गया। कई बार इस देश की मुस्लिम महिलाएं व मुस्लिम माता-बहनें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों में गईं। ऐसा नहीं है कि देश की अदालत ने पहली बार यह फैसला लिया है, शाहबानो के केस में भी फैसला लिया था, तब कानून बनाकर उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ...(**व्यवधान**)... ऐसा नहीं है कि आपने इस बार भी विरोध नहीं किया है, अभी आप खड़े हो कर कहोगे। आपके विरोध करने का तरीका अलग है, मगर है विरोध ही। जब इस देश की सरकार, इस देश के प्रधान मंत्री मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आए तो राज्य सभा में इसको रोक दिया गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़। मैंने आपको एलॉउ नहीं किया है। ...(**व्यवधान**)... जब आपको जवाब देना हो, तब बोलिए।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: सभापति महोदय, मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर विरोध नहीं करते हैं, तो हम कल ही लेकर आ सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... हमें क्या आपत्ति है? हम तो लेकर ही आए थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): महिला आरक्षण बिल लेकर आइए।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: महिला आरक्षण बिल आप भी नहीं ला पाए थे।

श्री आनन्द शर्मा: हमने राज्य सभा में पास कर दिया, लेकिन लोक सभा में पेंडिंग है। ...(**व्यवधान**)... हम समर्थन करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: लोक सभा में पारित नहीं कर पाए थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... यह कोई तरीका नहीं है। पुनिया जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... आप इतने अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... आपने बोला, बस हो गया। ...(**व्यवधान**)... पांच लोग खड़े होकर अपनी-अपनी बात बोलें, तो यह कौन सी पद्धति है? विपक्ष के नेता और बाकी सदस्यों को जब बोलने का मौका मिलेगा, तब आप इफेक्टिवली काउंटर करिए, इसमें क्या है?

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः सभापति महोदय, इस देश के दिव्यांगों को आज़ादी से लेकर अब तक 'अपाहिज़' शब्द के अपमानजनक शब्द को झेलना पड़ता था। एक संवेदनशील प्रधान मंत्री की दूरदृष्टि ही थी कि अपाहिज़ की जगह दिव्यांग शब्द को कानूनी जामा पहना कर उनको सम्मान देने का काम किया।

सभापति महोदय, इनके रिजर्वेशन में भी बढ़ोत्तरी की है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर एयर पोर्ट हो, हर जगह दिव्यांग को अपमानित न होना पड़े, इस प्रकार की बातें सरकार की ओर से प्रारम्भ की गई हैं।

सभापति महोदय, सगर्भा महिलाएं, जब भी सगर्भा होती थीं, अगर वे काम करती हैं, तो उनके मन में एक चिंता रहती थी कि उनका बच्चा पैदा होने के बाद उनके लिए जो छः महीने महत्वपूर्ण होते हैं, उस समय में बच्चे की देखभाल कौन करेगा? किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो या न हो, खुद के स्वास्थ्य की चिंता करना, बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करना, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सगर्भा महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद 26 वीक की छुट्टी देकर जच्चा बच्चा दोनों को मदद देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाकर सरकार के संवदेनशील चहरे को हमारे सामने रखा है।

सभापति महोदय, बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार की ओर से लिए गए हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं, जिनको सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती है, बल्कि जनता के साथ मिलकर करने पड़ते हैं। जनभागीदारी से स्वच्छता का संस्कार आज समाज के अंदर एक आंदोलन के रूप में प्रस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं कि पीढ़ियों तक यह स्वच्छता का संस्कार देश को स्वच्छ रखेगा। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इनकी जेंडर रेश्यो भी बहुत से राज्यों में सुधर रही है और बच्चियों का ड्राप ऑउट रेश्यो भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। हमारा "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" और योग पूरे विश्व में मनाने का प्रस्ताव यूएन ने मान लिया है। आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर योग पूरे विश्व के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए काम कर रही है।

सभापति महोदय, डीबीटी की चर्चाएँ होती थीं, लेकिन किसी में साहस नहीं था। इस देश में एक बहुत बड़ा स्कैम चलता था, जिसको न कभी दोनों में से किसी एक सदन ने नोट किया, न कभी देश के मीडिया ने नोट किया। डीबीटी के माध्यम से सारे फायदे डायरेक्ट बैंक एकाउंट में पहुंचाकर जब सरकार ने उसे जाँचा तो पाया कि सरकार के हर साल 57,000 करोड़ बचे हैं। यह पैसा कहाँ जाता था? मैं यह नहीं कहता कि इसको कोई एक व्यक्ति खा जाता था, मगर व्यवस्था के छिद्रों के कारण लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा ऐसे लोग ले जाते थे, जिनका इस पर अधिकार नहीं है। यह 57,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण बचा है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, नीति आयोग का नया इनिशिएटिव भी आज देश में बहुत सारी नीतियाँ बनाने के काम आ रहा है। मैं मानता हूं कि यह परंपरा आने वाले दिनों में देश को बहुत आगे ले जाने के लिए आने आप में एक बहुत बड़ा काम करेगी।

सभापति महोदय, अभी-अभी जो "खेलो इंडिया" का इनिशिएटिव लिया गया है, जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहा है और जो खेलों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मालूम होगा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे रजत पदक और स्वर्ण पदक मुझे इस "खेलो इंडिया" के अंदर दिखाई पड़ते हैं। सभापति महोदय, देश के बच्चों की खेलने की आदत चली गई थी, लेकिन "खेलो इंडिया" इनिशिएटिव ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है।

सभापति महोदय, 115 पिछड़े जिलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य योजना है। इस देश में कभी ऐसा नहीं सोचा गया कि कौन-सा जिला पिछड़ गया है, लेकिन यह सरकार पहली बार 115 जिलों को चिह्नित करके, उनके लिए एक विशेष कार्य योजना लेकर आई है। माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।

सभापति महोदय, काफी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिससे देश का गौर बढ़ा है। मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा, आप चिंता मत करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः पेरिस समझौते में भारत का जो रोल रहा, उसने पूरी दुनिया में भारत को गौरव दिलाया है। अभी दाओस में प्रधान मंत्री जी का जो उद्घाटन भाषण था, मैं मानता हूं कि यह हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। सभापति महोदय, आज दुनिया जिस दिशा में जा रही है, प्रधान मंत्री ने बहुत विश्वास से, किसी को भी नीचा दिखाए बगैर, देश कितना बड़ा है और कितनी ऊंचाई पर हम हैं, यह दुनिया को बताने का काम दाओस के अंदर किया है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी बात है। यू.एन. असेम्बली के अंदर के हो या अमरीका की सीनेट के अंदर, उन्होंने समानता के भाव के साथ अमरीका की संसद को जिस प्रकार से संबोधित किया, यह देश को दुनिया में गौरव दिलाने वाली घटना है।

सभापति महोदय, इसरो ने अंतरिक्ष में 104 उपग्रह एक साथ छोड़कर रिकॉर्ड बनाया है। ...(**व्यवधान**)... पहले हम एक उपग्रह, दो उपग्रह, तेरह उपग्रह, तीस उपग्रह तक पहुंचे थे, लेकिन अंतरिक्ष में एक साथ 104 उपग्रह स्थापित करके इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं मानता हूं कि इससे देश के सोचने का स्केल बदलता है। अब देश के युवा की "हम सबसे पहले होने चाहिए" - यह भूख जगी है। देश का स्केल बदलने का काम भी इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, डिज़िटल कनेक्टिविटी और शपथ में सभी सार्क देशों का उपस्थित होना और इस 26 जनवरी को दस के दस आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों का यहाँ होना, मैं मानता हूं कि यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, जब हम इस सरकार में आए, तब हमने भ्रष्टाचार के लिए भी कहा था कि हम इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का निष्ठावान प्रयास करेंगे। महोदय, 12 लाख करोड़ के घपलों, घोटालों की सरकार के बाद हमारी सरकार बनी, हमें साढ़े तीन साल हो गए हैं, मगर हमने इस प्रकार का काम किया है कि हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। हमने कोल ब्लॉक्स की नीलामी पारदर्शी तरीकों से की, खदानों की नीलामी पारदर्शी तरीकों से की,

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

स्पेक्ट्रम की नीलामी पारदर्शी तरीकों से की और इन तीनों नीलामियों का यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा था, set aside करना पड़ा था। आज हम इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। काला धन के खिलाफ एक सोची-समझी रणनीति के तहत बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी गई है। सबसे पहला प्रस्ताव कैबिनेट का हमने एसआईटी को बनाने का किया, जिसको कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत भी लटकाया जा रहा था। सारी सूचनाएं एसआईटी को ट्रांसफर कर दी गई। कई नए कानून बनाए, बेनामी संपत्ति का कानून उसमें से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने काले धन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाने का सफल प्रयास किया और जिसके कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फायदा हुआ। साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर के रास्ते से जो पैसा, काला धन घूम कर आता था, एक अलग तरीके से आता था, उन संधियों को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। नोटबंदी के कारण भी काले धन पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No party will be allowed to speak for more than the allotted time Don't worry on that count.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः तीन लाख से ज्यादा शैल कंपनियों को बंद करने का काम भी किया है। सभापति महोदय, अब तक 70 साल के इतिहास में जितनी भी सरकारें आईं, वे द्वंद्व में फंसी रहीं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः क्या द्वंद्व में फंसी सरकारें किसानों का विकास करेंगी या उद्योगों को बढ़ावा देंगी? क्या द्वंद्व में फंसी सरकारें गांवों का विकास करेंगे या शहरों का विकास करेंगी? क्या द्वंद्व में फंसी सरकारें रिफॉर्म करेंगी या कल्याण राज्य की स्थापना करेंगी, विदेश नीति को तवज्ज़ोह देंगी या रक्षा नीति को तवज्ज़ोह देंगी? क्या ऐसी सरकारें ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे या जन-प्रतिनिधि चलाएंगे? इस सरकार ने किसी भी द्वंद्व में फंसे बगैर यह सिद्ध कर दिया है कि किसानों का भी विकास हो सकता है, उद्योगों का भी विकास हो सकता है, गांव का भी विकास हो सकता है, शहर का भी विकास हो सकता है, रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं, जन-कल्याण के काम भी हो सकते हैं, विदेश नीति भी अच्छे से आगे बढ़ाई जा सकती है और दृढ़ रक्षा नीति को भी लागू किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और जन-प्रतिनिधि नीतियां बना रहे हैं। अनेक प्रकार के द्वंद्वों में से बाहर निकालने का काम इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

सभापति महोदय, मल्टीपार्टीज़ डेमोक्रेसी सिस्टम में स्वाभाविक है कि विपक्ष का दायित्व है कि सरकारों की कमजोर कड़ियों को लोगों के सामने रखे और सरकार अपने किए हुए कामों को लोगों के सामने रखे। इसलिए कई बार सदन की कार्यवाही को देखने वाले लोग पशोपेश में पड़ते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है? बुनियादी ये दोनों प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं, मगर लोकतंत्र में सरकार ठीक से चली या नहीं चली, इसका पैमाना क्या हो सकता है? मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में सरकार ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, इसका सबसे बड़ा पैमाना जनादेश हो सकता है। जनादेश ही तय करता है कि

सरकार ठीक से चली या नहीं चली। साल 2014 की सरकार आने के बाद हरियाणा में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस पार्टी हारी। महाराष्ट्र में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस की सरकार गई। झारखंड में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस की सरकार गई। जम्मू-कश्मीर में चुनाव आया, हम जीत कर आए, कांग्रेस की सरकार गई। ...(**व्यवधान**)... बिहार और दिल्ली में चुनाव आए, हमारी सरकार नहीं आई, मगर हमारा मत प्रतिशत बढ़ा। असम में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। मणिपुर में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः उत्तराखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, सपा-कांग्रेस हारी, भाजपा जीती और अभी-अभी गोवा में भी चुनाव हुआ, हम फिर से एक बार जीत कर आए हैं। ...(**व्यवधान**)... सुनिए, सुनिए। अभी-अभी गुजरात में भी चुनाव आया। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, please.

श्री अमित अनिल चन्द्र शाहः सभापति महोदय, गुजरात में भी चुनाव आया, 22 साल के बाद फिर से एक बार पांच साल के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ...(**व्यवधान**)... हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस गई। सभापति महोदय, अब कुछ लोगों को हार में भी जीत दिखाई पड़ती है। अब हम क्या करें? इसका हमारे पास रास्ता ही नहीं है। आजादी के बाद अगर कोई एक राज्य ऐसा है, जहां किसी एक दल को 49 प्रतिशत मत मिला है, तो मैं मानने को तैयार हूं कि गुजरात में जनादेश मिला है, 49 प्रतिशत वोट यानी हर दूसरा वोट जनता पार्टी को मिला है। बाईस साल शासन में रहने के बाद फिर से यह पांच साल के लिए जनादेश मिला है। सभापति महोदय, 1965 के बाद एक भी कांग्रेस सरकार ऐसी नहीं है, मैं रिकॉर्ड चेक करके आया हूं, जो 27 साल के लिए शासन में रही हो। फिर भी इसमें जीत दिखाई पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं?

सभापति महोदय, मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि तीन नासूर हमारे देश के लोकतंत्र को बहुत समय से डँसे हुए थे - वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण। उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव के बाद मैं भरोसे से कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इस देश के लोकतंत्र में से वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण को उखाड़ कर फेंक दिया है। हमारे लोकतंत्र को इस अभिशाप से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। सभापति महोदय, हमने एक पारदर्शी सरकार चलाई है, एक निर्णायक सरकार चलाई है, एक संवेदनशील सरकार चलाई है और भारत के गौरव को स्थापित करने की सरकार साढ़े तीन साल तक चलाई है। इसलिए हमें जनादेश मिला है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने और इस देश के प्रधान मंत्री ने एक विचार देश के सामने रखा था कि इस देश में बारंबार चुनाव के कारण विकास में बाधा आती है, इसलिए चुनाव एक साथ होने चाहिए। अगर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव एक साथ होते हैं, विधान सभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे खर्च में भी काफी बचत होगी और बारंबार जो चुनाव आचार

[श्री अमित अनिल चन्द्र शाह]

संहिता आती है इसके कारण विकास की बाधा भी समाप्त होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि इससे भाजपा को फायदा होगा, मगर कोई भी जो तत्कालीन स्थिति होती है, वह हमेशा के लिए नहीं होती है। आज हमारा फायदा होता है, कल किसी और का होगा। मेरा सभी दलों से एक अनुरोध है कि हम इस देश में एक अच्छी बहस छेड़ें, सभी दल इसमें हिस्सा लें और हम एक साथ चुनाव के लिए आगे आएँ।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने एक 'New India' का सपना देखा है, जिसमें कोई बेरोजगार न हो, हर घर में बिजली हो, शुद्ध पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सेवाएँ हों, शिक्षा की सेवा बहुत अच्छे तरीके से हर व्यक्ति को मिल पाए और भारत का गौरव पूरी दुनिया में प्रस्थापित हो। इस प्रकार के 'New India' के निर्माण के लिए यह सरकार आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया है, इसलिए उनका धन्यवाद करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe to make his speech seconding the Motion. मित्रों, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्माः सर, 'माननीय सदस्यों', 'मित्रों' बाहर कहना चाहिए।

श्री सभापतिः 'माननीय सदस्य', I stand corrected. माननीय सदस्यों, संख्या बल के आधार पर समय पहले निर्धारित होता है, यह पद्धति शुरू से चल रही है। इस हिसाब से बीजेपी को 2 hours 47 minutes, कांग्रेस को 2 hours 36 minutes और समाजवादी पार्टी को 52 minutes, इस तरह already division हो चुका है। वह मेरे सामने है। उसमें कुछ गलत दिखाया गया होगा। मेरा सभ पार्टियों से यह कहना है कि आप जितना समय लेना चाहते हैं, उतना लीजिए, रिकॉर्ड आपके पास है, मगर आप आपस में चर्चा करके कि कितने लोगों को बोलना है और उनको कितना समय देना है, वह आप तय करें, तो अच्छा होगा। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। किसी को ज्यादा समय नहीं मिलेगा। Number two, यह उनकी maiden speech थी और एक पार्टी के अध्यक्ष यहाँ बोल रहे हैं, वह तो secondary विषय है, main issue यह है कि यह उनकी maiden speech थी। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सहनशील होकर बाकी लोगों को सुनना है।

तीसरा, ...(**व्यवधान**)... आपने सुना और बाकी लोगों ने व्याख्या भी की। मेरा कहना यह है कि it is not any charity that we heard others. It is the responsibility of everybody that we should hear others, this side and that side. So, please cooperate accordingly. After Dr. Vinay Sahasrabuddhe, we have to go to amendments. Then, the round starts. We will start with the Congress Party, and, then, the other parties. Now, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. आप आपस में चर्चा करके समय तय कीजिए कि किसको कितना बोलना है।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र): आदरणीय सभापति जी, इस सदन में हमारे आदरणीय सम्मानित सदस्य, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्रीमान् अमित भाई शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हृदयपूर्वक अनुमोदन करने के लिए यहां खड़ा हूं।

महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने देश की राजनीति और विशेष रूप से देश की गवर्नेंस के संबंध में बताया कि सरकार किस पद्धति से विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है और कैसे परिवर्तन को मुहैया करने की कोशिश में प्रामाणिकता से लगी हुई है, इसका एक विस्तृत चित्र हमारे सम्मुख रखा है और एक big picture हमारे सामने आई है। जिन बातों को मेरे पूर्व वक्ता ने स्पर्श किया है, उनको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर राजनीति शास्त्र और गवर्नेंस के एक छात्र के रूप में जब विगत साढ़े तीन या पौने चार सालों के आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के काम को मैं देखता और समझने की कोशिश करता हूं अथवा विश्लेषण करता हूं, तो मेरे जैसे छात्र के सामने तीन बिंदु आते हैं।

सभापति जी, मुझे लगता है कि इस सरकार से आखिरकार आने वाली पीढ़ियां यह चीज़ पूछने ही वाली हैं कि What is your value addition? आपने नया क्या किया, यह प्रश्न कोई भी पूछेगा और लोकतंत्र में यह पूछने का अधिकार भी है।

महोदय, मैं मानता हूं कि इस सरकार की विशेषताओं के तीन पहलू हैं, जिनका विवरण मैं संक्षेप में आपके सम्मुख रखूंगा। इस सरकार का पहला पहलू है, 'Politics through Inspiration', 'प्रेरणा के आधार पर राजनीति'। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में विचारधारा की प्रेरणा पर काम करने वाले बहुत कम राजनीतिक दल हैं। दुर्भाग्यवश बहुत सारे दलों की प्रेरणा किसी एक घराने के साथ संबंधित होती है, इसलिए प्रेरणा का जो एक निरंतर वातावरण बनना चाहिए, वह बनता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरी बात है, 'Governance through Innovation', 'नवाचार के आधार पर शासकता का परिचय', जिसमें इस सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तीसरी बात है, 'Transformation through Implementation.' यानी क्रियान्वयन के माध्यम से परिवर्तन।

सभापति महोदय, हम कहते हैं, the taste of sugar is in eating. ऐसे ही जो नीतियां आती हैं या जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनके परिणाम किस पद्धति से निकल कर आते हैं, इसका परिचय क्रियान्वयन के माध्यम से मिलता है और मैं संक्षेप में इन तीन पहलुओं को आपके सम्मुख उजागर करूंगा।

सभापति महोदय, जब मैं सोचता हूं कि यह सब कैसे हो पाया, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमें एक ऐसा जननायक मिला है, जिसका अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। किसी को आगे लाया या किसी एक घराने को आगे ले जाना, यह उनकी कार्यसूची का पहलू बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हमारे पास ऐसा एक नेता है, जिनके उद्देश्यों के बारे में, जिनकी प्रेरणा के बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं है।

दूसरी बात है, केवल किसी एक समाज विशेष को आगे बढ़ाना। हम देखते हैं कि हमारे कई मान्यवर राजनीतिक नेता अपने-अपने समाज विशेष के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। प्रधान मंत्री हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करते हुए, उसी कार्यक्रम को अमल में लाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े हैं, चाहे वह गुजरात में हो या अभी हमारी केन्द्र सरकार का नेतृत्व करते हुए हो। मैं मानता हूं कि देश की राजनीति में और देश का नेतृत्व जो अब तक रहा है, उसमें विद्यमान नेतृत्व एक विशेषता इस पहलू की भी है, जिसको मैं उजागर करना चाहूंगा।

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

सभापति महोदय, मैंने इनोवेशन का जिक्र किया। आज लोग इनोवेट करते हैं, नवाचार से सोचते हैं, नई कल्पनाओं को लड़ाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक ऊर्जा अंदर होती है, कुछ नया करने की एक ललक होती है और ललक होती है कि हम कुछ नया करके दिखाएं, कुछ अलग पद्धति से पेश आएं। मगर मैं सोच में पड़ गया कि इतनी सारी सरकारें हुईं, इतने सारे प्रधान मंत्री हमारे देश ने देखे और 55 साल हो तो एक ही दल का शासन हमने देखा, तो क्या इनको इनोवेशंस की कोई पड़ी नहीं थी? इन्होंने नवाचारों का अमल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने out-of-the-box सोच को अपनाया? मुझे लगता है कि जब किसी दल विशेष के अंदर यथास्थिति *(status quo)* को मेंटेन करने में एक निहित स्वार्थ (vested interest) बन जाता है, तो innovation से लोग दस कदम दूर रह जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, क्या करना है परिवर्तन करके, सत्ता तो हमारे साथ आनी ही है। लोगों को taken for granted लेते हुए जिन्होंने अपनी राजनीति की, मैं मानता हूं कि उन्होंने इस पद्धति से innovations का सहारा न लेते हुए, जो यथास्थिति थी, जो *status quo* था, उसको ही और अधिक मज़बूत करने की दिशा में अपनी राजनीति और अपने शासन तंत्र को आगे बढ़ाया, जिसके कारण 55 साल के बाद भी स्थिति जैसी थी, लगभग वैसी ही बनी रही। सभापति महोदय, कई बार तो मैं अचरज में पड़ जाता हूं, क्योंकि इन्हीं के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि करप्शन तो पूरे विश्व में है, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? महोदय, दूसरे एक प्रधान मंत्री ने कहा कि जब एक रुपया खर्च होता है, तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। बड़े सत्य का साक्षात्कार हुआ, लेकिन बाद में किया गया? कुछ किया ही नहीं। उसके बाद भी इन दलों के कई प्रधान मंत्री आए, मगर किया तो कुछ नहीं, क्योंकि करने के प्रति कोई प्रतिबद्धता, कोई कमिटमेंट वाला विषय ही नहीं था।

सभापति महोदय, अब मैं पुनः एक बार प्रेरणा के विषय पर आता हूं, जो पहला पहलू, मैंने आपके सम्मुख उजागर किया था। प्रेरणा का भी एक संक्रमण होता है। जब लोगों के ध्यान में आता है कि ऊपर बैठे हुए शीर्षस्थ नेतृत्व का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, किस घराने को आगे बढ़ाने की कवायद नहीं है, किसी समाज विशेष को नेतृत्व करते हुए, जैसे माननीय अमित भाई शाह ने कहा कि 'यावत्चंद्र दिवाकरो', बस हम ही सत्ता में रहें, इस तरह की भावना जब नहीं है, तो मैं मानता हूं कि लोग भी उस प्रेरणा से स्वयं प्रेरित हो जाते हैं।

सभापति महोदय, हमने अभी-अभी देखा, विशेषकर पिछले साल सितम्बर में, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने Smart India Hackathon किया। अब यह Hackathon नई बात नहीं है। विश्व के कई देशों में Hackathon होता रहा है और Hackathon का मतलब यह होता है कि software के माध्यम से बुनियादी और विशेष रूप से गवर्नेन्स की समस्याओं के कोई समाधान ढूंढ़ना। समाधान ढूंढने के लिए प्रधान मंत्री जी ने और हमारे संबंधित मंत्रालय ने पूरे देश के छात्रों का आह्वान किया, इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ का आह्वान किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 7,530 टीमें बनी थीं। एक टीम में इंजीनियरिंग पढ़ने वाले होनहार और प्रतिभाशाली छात्र थे। इसमें 40 हजार छात्रों ने भाग लिया और 598 समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए सारे छात्र अपना समय और अपनी प्रतिभा लगाते रहे। इसमें 2150 इंस्टीट्यूशन्स के छात्र आए। ये तब होता है, जब उनके ध्यान में आता है कि

कोई यदि हम कोई सुझाव देंगे, हम यदि कोई समाधान ढूंढ कर निकालेंगे, तो यह सरकार उसका स्वागत करेगी, क्योंकि सरकार का कोई स्वार्थपरक और दलगत एजेंडा नहीं है।

सभापति महोदय, संक्रमण कैसे होता है? इसका संक्रमण समाज के अन्यान्य क्षेत्रों में होता है। अभी हमने सुना कि शौचालय की समस्या के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उल्लेख किया। किसी की कल्पना में भी नहीं आया होगा और किसी को यह लगा भी नहीं होगा कि प्रधान मंत्री इस तरह के विषय को भी लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे और उनके भाषण का यह भी एक बिन्दु बन सकता है। मगर फिर भी यह हुआ। हमने कहा था कि सारे सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनेंगे और बनवा दिये। जो कहा सो किया। इसके कारण प्रेरणा का संक्रमण हुआ और हमारे अक्षय कुमार को लगा कि हम 'टॉयलेट' का विषय मध्य में रखते हुए एक प्रेम कहानी की फिल्म भी बना सकते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि टॉयलेट जैसे विषय पर, एक कहानी को उसके इर्द-गिर्द गूंथते हुए, एक अच्छी-खासी फिल्म बन सकती है, मूवी बन सकती है, लेकिन बन गई। अभी 'पैडमैन' नाम की एक मूवी आई है, क्योंकि महिला के स्वास्थ्य का विषय, इस देश के विकास के एजेंडे से हमने जोड़ा है। आप चाहें, तो उपहास कर सकते हैं। यह तो आपका अधिकार है ही और आपने कई बार उपहास किया भी। कभी कहा कि विकास पगला हो गया। भाई, विकास का जिसके लिए महत्व ही नहीं है, वही उसे पगला कहेगा, क्योंकि आपने कभी लोगों को विकास की दिशा देने के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए आपने सोचा कि विकास को बदनाम करो, विकास के बारे में अनाप-शनाप बातें कहो। आपने इसी पद्धति से राजनीति को आगे बढ़ाया। मगर मैं मानता हूं कि विकास की आकांक्षा निर्माण करने के अन्योन्य प्रयास की छोटी-छोटी चीजें भी व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा निर्माण कर सकती हैं और इसके कई उदाहरण हैं।

महोदय, हमने स्मार्ट सिटीज़ का विषय आगे बढ़ाया। अब लोग बोलते हैं कि यह सरकारी कार्यक्रम है। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम जन सहभागिता के आधार पर चल रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि किस पद्धति से लोग इससे जुड़ रहे हैं। I am now quoting from a book where a report has been published. By and large, the cities organized workshops about smart cities, held talks and blogs, printed newsletters, employed FM radio and local cable channels, held street plays, marathons, about smart cities concept बहुत सारे विषय हुए, कहां-कहां हुए? Pune and Sholapur deployed youth associations like *Ganesh Mandals* during *Ganesh Chaturthi* to crowd-source ideas. Pune also organized the Digitzl Hackathon and Appathon, conducted a signature campaign where three lakh citizens pledged their support to Pune's Smart City Plan. स्मार्ट सिटी का प्लान, किसी सरकारी बाबू द्वारा बनाया गया प्लान नहीं है। यह लोगो की सहभागिता से बन रहा है। केवल पुणे और शोलापुर की बात नहीं है। भुवनेश्वर में, वहां के छात्रों ने आगे आकर 'हमारा बचपन कैम्पेन' और 'हमारे विश्व की चिन्ता' आदि विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित कीं और 'मेरे सपनों का भुवनेश्वर कैसा हो' इस विषय की चर्चा छोड़ी। यह तब होता है, जब जनता को लगता है कि विकास का एजेंडा हमारा साझा एजेंडा है, यह किसी एक व्यक्ति का, किसी एक दल का या किसी एक सरकार का एजेंडा नहीं है। इसलिए यह प्रेरणा का जो संक्रमण हुआ, उसके माध्यम से हम आगे बढ़े। इसमें कई सारी बातें हैं।

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

सभापति महोदय, हमारे यहाँ पर हमारी एक माननीय संसद सम्पतिया उइके जी मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र से, मंडला से आती हैं। उनके बारे में किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि ब्रीफ बायो वगैरह पढ़ने का बहुत ज्यादा कष्ट भी हम नहीं लेते। अब ये हमारे ही सदन का एक हिस्सा बन जाती हैं। सम्पतिया जी की एक विशेषता है, जो मैं सदन को बताना चाहता हूं। ये एक ग्राम पंचायत की प्रधान बन कर सामने आईं, विगत 17 सालों में जिला परिषद् की अध्यक्षा बनीं और ये लगातार तीन-चार बार निर्विरोध चुन कर जिला पंचायत की अध्यक्षा के रूप में आईं। उन्होंने क्या किया? सम्पतिया जी और उनके सहयोगी 16,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जिन महिलाओं ने अपना विकास करा लिया, जो आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी हो गईं -- राजा साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह आपके आनन्द का विषय है -- उनमें से 6,000 महिलाओं ने अपने Below Poverty Line Cards सरकार को वापस किये और कहा कि अब हम गरीब नहीं हैं। 'हम गरीब नहीं हैं', यह कहने के लिए भी ताकत लगती है। 'गरीबी हटाओ' का नारा देना तो आसान होता है, मगर गरीबी से लोगों को यथाशीघ्र मुक्त करना और यह कहना कि 'अब यह उन लोगों को दो, जो वास्तविकता में इसके लिए हकदार हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है।' यह साधारण बात नहीं है।

ऐसी ही प्रेरणा का संक्रमण हमारे पंजाब के संत सींचेवाल जी के द्वारा हुआ है। उन्होंने अपनी नदी का उद्धार किया। एक दृष्टि से नदी को साफ रखने का एक बहुत ही असाधारण उदाहरण संत सींचेवाल जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। सींचेवाल जी के पास हमारे गंगा के किनारे के सारे सरपंचों को सरकार के गंगा विभाग ने प्रशिक्षण के लिए भेजा। लोग वहां से प्रशिक्षित होकर आये। उस प्रेरणा से अपने गाँव वालों को प्रेरित करते हुए गंगा की सफाई के लिए हमारी सरकार सारे सरपंचों की मदद से, सहयोग से काम कर रही है।

वही बात महिलाओं की है, जो सम्पतिया जी ने किया। अभी एक सरकार ने last year, 7 सितम्बर, 2016 में महिलाओं के e-haat खोले हैं। आपको पता नहीं होगा, मगर कई सारी women entrepreneurs, self help groups and NGOs इसका उपयोग करते हुए अपनी छोटी-छोटी चीज़ें अब विश्व के बाजार में बेचने के लिए समर्थ हुए हैं और उस पद्धति में खुद को ढाल भी रहे हैं।

वनवासियों, आदिवासियों के बारे में भी बहुत सारी चर्चा होती है। इस सरकार ने वनाधिकार के तहत जो पट्टों को वितरित करने की आवश्यकता थी, उसको एक अभियान के रूप में, राज्यों के सहयोग से चलाने की एक मुहिम भी अपनायी है। मनरेगा का उपयोग करते हुए वनवासी, आदिवासी किसानों के खेत-तालाबों का काम भी हो रहा है और अभी-अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एकलव्य विद्यालयों की योजना का इजहार किया है, घोषणा की है, मैं मानता हूं कि आदिवासी जनजातीय जीवन में भी यह एक अपने आप में एक बड़ा कदम है। उससे निश्चित रूप से आदिवासी, वनवासियों की जो नयी पीढ़ी है, वह और अधिक कुशलतापूर्वक विकास पथ पर आगे बढ़ सकेगी। मेरे मन में इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय, जब-जब विकास की चर्चा होती है, एक competitive spirit आ जाती है। Healthy competition होना भी चाहिए। मगर हम जब भी कुछ करते हैं, तो सामने बैठे हुए हमारे मित्र

बोलते हैं कि यह तो हमने भी शुरू किया था। हमारे मराठी में 'आरम्भशूर' नाम का एक शब्द है कि आरम्भ करना, बाद में छोड़ देना, फॉलो अप नहीं करना। यह सही है। 2012 में मेरे ख्याल से इन्हीं की सरकार ने दलितों के लिए, हमारे Scheduled Castes भाइयों के लिए एक Venture Capital Fund बनाया था। यह 2012 में बना। इनकी सरकार 2014 तक थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2015 में इस योजना पर कारगर अमल करने की शुरुआत हुई। 200 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि हमने मुहैया की और आज दलित समाज से, Scheduled Castes समाज से कितने सारे उद्यमी इस *Dalit* Venture Capital Fund का उपयोग कर रहे हैं! समस्याएँ तो रहती हैं। योजना बनाना आसान होता है। जब उसको क्रियान्वयन के धरातल पर लाते हैं, तो समस्याएँ आती हैं। There were may challenges in the path of the VCF or Scheduled Castes. The first challenge was smooth and speedy delivery of credit which was addressed by insulting a single-window system. The second was to address the lack of equity capital by funding entrepreneurs through a mix of equity, *quasi* equity and debt instruments. Equity instruments are expected to yield a return of 15 per cent and debt instruments are expected to yield a return of 10 per cent per annum. The third challenge was the very real issue of constraints on providing collateral against loans or debentures which was dealth with by making the assets of the project funded through VCF and promoters' contribution part of the security. जब एक इच्छा-शक्ति होती है, एक राजनीतिक इच्छा-शक्ति होती है, एक political will होती है and when there is a will, there is a way. इस पद्धति से यह सरकार काम करते आई, इसके कारण परिणाम निकल कर आ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं innovation की बात कर रहा था। हम कई बार बारीकियों में जाते नहीं और तफसील से बहुत ज्यादा झांक कर देखने का स्वभाव ही नहीं होता, भूल जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये केवल नारे हैं। मगर यह सरकार नवाचार के माध्यम से क्रियान्वयन को और अधिक तगड़ा कर रही है। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है, Government e-Market, जिसको GeM बोलते हैं। आपको पता होगा और सदन में इतने सारे पुराने मंत्री भी बैठे हैं, वे तो जानते ही हैं कि भारत सरकार हर वर्ष लगभग चार लाख करोड़ रुपए की सामग्री परचेज़ करती है, उसमें टेबल-कुर्सी, फाइल, पेपरवेट से लेकर सारी चीज़ें होती हैं। अभी तक परचेज़ करने की जो स्थापित पद्धति थी, वह टेंडरिंग की थी और एल-वन, एल-टू आदि सारी बातें हम जानते हैं, इस भाषा का भी हमें परिचय है। मगर इस प्रक्रिया में दुनिया के, कम से कम भारत देश के अंदर के सारे उद्यमियों की सहभागिता के लिए कोई अवसर नहीं था, क्योंकि कई बार एक कारटेल जम जाता है, सत्ता के निकट जो होते हैं, उन्हीं को वह अवसर मिल जाता है। सरकार ने इसका भी एक democratization किया और minimum price, maximum ease के सूत्र को अपनाते हुए उसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हो, इसकी चिंता की। Technology को leverage किया। आज हम देख रहे हैं, जुलाई, 2017 के आंकड़े मेरे पास हैं, लगभग 9,500 वेंडर्स ने GeM पर खुद को रजिस्टर किया। अब सरकार 21 हजार प्रोडक्ट्स इन वेंडर्स के माध्यम से ले रही है और 1,370 सेवाओं को भी सरकार इसी माध्यम से अर्जित कर रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि त्रिपुरा के bamboo की चटाई बनाने वाले या ट्रे बनाने वाले किसी व्यक्ति को भी अपना उत्पाद दिल्ली के मंत्रालयों के गलियारे में बेचने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब इस पद्धति के

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

माध्यम से त्रिपुरा के bamboo की चटाई बनाने वाले या ट्रे बनाने वाले व्यक्ति के लिए दिल्ली के गलियारों में अपनी ट्रे बेचना आसान हो गया है, संभव हो गया है। किसी ने इस पद्धति का शायद सपना भी नहीं देखा होगा और फिर भी बड़ी आसानी से यह हो रहा है।

सभापति महोदय, इसके कारण लगभग 15 से 20 प्रतिशत की बचत हुई है। पहले मार्केट में वह जिस प्राइस पर मिलती थी, अब उससे कम प्राइस पर हम इस पद्धति से खरीदारी की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं। मैं यह मानता हूं कि यह सफलता एक उल्लेखनीय सफलता है।

मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय implementation के बारे में है, हमारे क्रियान्वयन के बारे में है। मैं क्रियान्वयन के ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं, मगर एक उदाहरण, जो मुझे लगता है कि हम सबको जिसके बारे में गौर करना चाहिए, वह है आधुनिक सूचना तंत्र का प्रशासन के साथ रिश्ता बिठाना, क्योंकि आम आदमी भी, जो अभी स्मार्टफोन यूज़ करता है और न भी यूज़ करता हो, जो एसएसएस भेज सकता है, वह फोन के माध्यम से अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी समस्या विश्व के सम्मुख ला सकता है। विशेष रूप से हमारे रेल विभाग ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। मैं वर्तमान रेल मंत्री और पूर्व रेल मंत्री का भी अभिनन्दन करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस पद्धति से twitter और फेसबुक पर जो लोग अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, उनका संज्ञान लेकर और उनके ऊपर कार्रवाई करने का एक सफल, कारगर और एक प्रभावी तंत्र विकसित किया है, वह सराहनीय है। इसके लिए रेल विभाग अभिनंदन का पात्र है। पूरे देश में लगभग 12,670 गाड़ियां हर रोज चलती हैं और 8,000 से भी अधिक रेलवे स्टेशन्स हैं। यहां पर जितनी सारी समस्याएं आती हैं, चाहे ट्रेन के डिब्बे में कोई शराब पीकर महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की समस्या हो, चाहे कोई महिला अपने नन्हे बच्चे के साथ सफर कर रही हो और बच्चे को दूध पिलाने के समय अगर उसका दूध खराब हो गया हो, तो उसको दूध कैसे मिलेगा, अगले स्टेशन पर दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह समस्या हो, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को लेकर लोगों ने tweet किया और रेल विभाग ने उसका जवाब दिया तथा उनका सहयोग किया। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं, जिसके कारण RailMinIndia, यह जो twitter handle है, उसके followers की संख्या कैसे निरंतर बढ़ी है, यह पता चलता है। अप्रैल, 2016 में इसके followers की संख्या लगभग 10 लाख थी, दिसम्बर, 2016 में यह 20 लाख हो गई और नवंबर, 2017 में यह बढ़ कर 33 लाख हो गई। इतनी मात्रा में यह बढ़ोत्तरी हुई है, इसका कारण यह है कि लोगों के बीच एक भरोसा कायम हुआ है कि अगर हम tweet करते हैं, फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं, तो रेल विभाग के संवेदनशील अधिकारी तुरंत उसके बारे में कार्रवाई के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि अब उनको पूछने वाला कोई है। अब तक तो ऐसा था कि हम भी पूछेंगे नहीं, आप भी हमें पूछो मत और फिर जब जनता पूछती थी, तब जवाब देना पड़ता था। मगर आज यह पूछपरक होती है। अब यह पूछा जाता है कि यह क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इतना समय क्यों लगा? मैं मानता हूँ कि इसके कारण प्रशासन तंत्र में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने बाकी भी काफी काम किए हैं, जैसे कोच मित्र योजना है, डीआरडीओ की मदद से बॉयो टायलेट्स बने हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इन सारे विषयों पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मगर यह हो पाया है। महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी का तंत्र एन.डी.ए. सरकार का खोजा हुआ नहीं है, बल्कि यह तो पहले से था। 2005, 2008, 2010, 2012 में आपका ही

राज था। आप भी कर सकते थे। मनरेगा के बारे में यहां चर्चा तो बहुत चलती रही और मनरेगा का क्रेडिट भी आप लेते रहे, मगर MNREGA assets का geo-tagging करना, यह काम आपके ज़माने में नहीं हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि जैसे ग्रामीण सिंचाई योजना है, प्रधान मंत्री आवास योजना है, भुवन पोर्टल के माध्यम से इन पर निगरानी रखने का जहां तक सवाल है, वह काम इस सरकार ने किया है, जिसके लिए सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। इसका कुछ सन्दर्भ महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आया है।

अब अंतिम तीन बिन्दु कहकर, सभापति महोदय, मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक विषय की ओर तो हमारे माननीय पूर्ववक्ता ने इंगित किया है कि पकौड़े बेचना किसी भी तरह गलत काम नहीं कहा जा सकता। उसे लेकर अनेक तरह की बातें कही गईं और उसकी तुलना भिक्षा मांगने वाले से की गई - मैं समझता हूं कि वह बहुत गलत और बहुत घिनौना स्टेटमेंट था। जब मैंने वह ट्वीट देखा, सुना और पढ़ा तो मैं बहुत उद्वेलित हो गया। मैं जानता हूं कि जिन्होंने पकौड़े बेचे हैं, उन्होंने कम-से-कम अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, self-respect को नहीं बेचा। अपनी self-respect को बेचते हुए, कदम-कदम पर जिन्होंने compromise किए, corruption को सहारा दिया और अनेक गलत बातें की, मैं मानता हूं कि उनसे हमारा पकौड़े बेचने वाला अधिक सम्मान का अधिकारी है। उसके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वह देश में मेहनत-मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। वह किसी भी पद्धति से, किसी appeasement के माध्यम से या किसी व्यक्ति के चरण तले अपनी सेवा समर्पित करके अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं मानता हूं कि उसके प्रति हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए।

जब यहां विकास को नकारने की बात आई, विकास के उपहास की बात आई - ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभाव का भी हम महिमा-मंडन करते आए हैं। अभाव की स्थिति, गरीब की स्थिति अवांछनीय स्थिति है। गरीब के प्रति, अभावग्रस्त व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गरीबी को glorify करें, मगर ऐसा हुआ। इस देश में गरीबी को glorify करते हुए राजनीति करने की कोशिश की गई और लोगों को बताया गया कि गरीब रहना ही ज्यादा अच्छा है। मैं मानता हूं कि देश में अपराधजन्य स्थिति बनाई गई, लोगों के मन में निराशा का वातावरण पनपने दिया गया और एक नकारात्मकता का दौर चलाने की कोश्शि हुई और इसी आधार पर अपनी राजनीति को मजबूत करने का माहौल इस देश ने देखा। इसी के चलते, देश में वोट बैंक की राजनीति मुख्य धारा बन गई।

अभी मैं देख रहा था, दो दिन पहले की बात है, ट्रिपल तलाक के बारे में आदरणीय अमितभाई शाह ने अपने भाषण में भी उल्लेख किया और सदन में उस पर चर्चा भी होगी, मगर क्या आज के ज़माने में, महाराष्ट्र के हमीद दलवाई जैसे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, एक प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी महाराष्ट्र के एक नेता का यह कहना है कि हमारे धर्मग्रन्थ के साथ खिलवाड़ करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है - कौन से विषय को लेकर हम चल रहे हैं? क्या देश में हम वोट बैंक की politics करेंगे और वह कौन सा धर्म ग्रन्थ है जो कहता है कि महिलाओं को अपमान-भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करना आवश्यक है? मैं नहीं मानता कि कोई धर्म ग्रन्थ ऐसा कहता होगा। हर धर्म ग्रन्थ व्यक्ति की इज्जत करता है, मगर ऐसा statement एक सुलझे हुए नेता की ओर से क्यों

[डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे]

आया? इस तरह की वोट बैंक की politics करना, इसके सिवाय दूसरा जिन्दगी में कुछ किया ही नहीं, जिसके चलते ऐसी स्थिति आ गई। इसकी जितनी भर्त्सना कड़े-से-कड़े शब्दों में हम करें, मैं मानता हूं कि वह कम है।

सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 55 साल तक जिस दल का राज रहा और आज भी वे आदतें जाती नहीं - Mr. Chairman, Sir, most of the Members on the other benches, unfortunately, are indulging in a crass politics of doubt. As against that, we are working with a politics of determination. This is a struggle between doubt versus determination, between ridicule versus resoluteness, between fragmentation versus fraternity. मैं मानता हूं किं अत में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे पास एक प्रेरणा है, एक उद्देश्य है और क्रियान्वयन के आधार पर जनता की रोज़मर्रा की जिन्दगी में परिवर्तन लाना हमारा संकल्प है, हमारी निष्ठा है। महोदय, मुझे कई बार याद आता है कि आज दुनिया में बहुत सारे जनतांत्रिक देशों में और भारत के बारे में भी कुछ साल पहले यह स्थिति थी कि लोगों को यह लगता था कि इस जनतंत्र ने हमें दिया क्या है। सभापति महोदय, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक उपन्यास है - "ए फेयरवेल टू आर्म्स।" उसका जो नायक है, वह आर्मी का एक जवान है। उसमें एक दृष्टांत यह आता है कि बहुत कड़ाके की ठंड है और वह जवान एक लकड़ी को जला रहा है। उसके आस-पास और दो-तीन लोग बैठे हैं, जो उस लकड़ी के जलाने से उत्पन्न हो रही उष्मा का आनन्द ले रहे हैं। तभी उस नायक के ध्यान में यह आता है कि इस जलती हुई लकड़ी पर कुछ चींटियाँ हैं। वह देखता है कि वे चीटिंयाँ उस जलती हुई लकड़ी पर एक ओर जाती हैं, तो उन्हें वहाँ अग्नि का जाल दिखाई देता है और जब वे दूसरी ओर जाती हैं, तो वहाँ भी वे देखती हैं कि वहाँ भी अग्नि ही है। उनको देखकर वह नायक कहता है - Like these ants, I also feel that I am trapped. मैं मानता हूँ कि इस देश की जनता को भी कई बार ऐसा लगा होगा कि we are trapped, क्योंकिं जनतत्र से अलग कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, मगर जनतंत्र मेरी थाली में कुछ परोस भी तो नहीं रहा! तो जनतंत्र चाहिए भी, मगर जनतंत्र डिलीवर तो नहीं कर रहा! इस अवस्था को पूर्णविराम देते हुए आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में what we have given is a delivering democracy. We have established that the democracy also can deliver; we have established that development is the right of every other person, अंत्योदय के विचार से अनुप्रेरित होते हुए। इसलिए सभापति महोदय, इस सरकार के हमारे साथी, जो *तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें, न रहें* - इस भाव से काम कर रहे हैं, एक दृष्टि से उस काम का ही एक reflection माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में है। इसलिए इस सदन को राष्ट्रपति जी के प्रति साधुवाद देना चाहिए, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as I said in the beginning, I would like to repeat again, whoever is speaking either from this side or that side, he should be heard with respect and rapt attention even if you may agree or disagree. Even the Leader of the Opposition is also likely to speak today. Please see to it that during his speech also, all

sides may respect each other so that the level of the debate can go up and people can appreciate the standard of the debate in the House. Please keep it in mind.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is time for moving amendments. There are 324 amendments to the Motion. Now, I am allowing these amendments one by one. Amendment Nos. 1 to 68 and 69 to 75 by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): सर, मैं प्रस्ताव करता हूँः-

1. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि देश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने हेतु आयोगों और भर्ती केन्द्रों द्वारा विलंब को दूर करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

2. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि देश में किसानों द्वारा कर्ज के बोझ के कारण लगतार की जा रही आत्महत्याओं को समाप्त करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।

3. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि पढ़े-लिखे बेरोजगारों को जीवन-यापन हेतु रोजगार या बेरोजारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।"

4. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि बढ़ती महंगाई से किसानों और निम्न आय वर्ग तथा गरीबों को राहत देने का उल्लेख नहीं है।"

5. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि देश में वर्ष 2011 के जनगणना में बेघर लोगों को आधार नंबर उपलब्ध हो सके जिससे वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले पाएं, के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

6. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत और अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

7. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि देश में स्वच्छता अभियान के नाम पर खुले में शौच करने वालों के साथ

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

मार-पीट और उन्हें सामाजिक तौर पर बेइज्जत करने से रोकने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

8. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की होने वाली बर्बादी को रोकने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

9. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में गाय को पालने के लिए खरीद कर ले जाते समय तथाकथित गौ-रक्षकों द्वारा गौ-तस्कर के नाम पर हिंसा की घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

10. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में किसानों के सभी फसलों को लागत मूल्य से अधिक मूल्य दिलाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

11. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अत्यधिक खेती लागत को कम करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

12. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि खेती में प्रयोग होने वाली नई प्रौद्योगिकी कीटनाशकों, बीजों और अन्य संसाधनों को नियंत्रिम मूल्य पर किसानों तक मुहैया कराने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

13. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि किसानों के आलू उत्पाद सहित सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था हेतु उल्लेख नहीं है।"

14. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में लगातार अलाभकारी होती खेती के कारण किसानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्याओं को रोकने के उपायों की जानकारी नहीं है।"

15. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अलाभकारी होती कृषि के कारण गांवों से पलायन रोकने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

16. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि कृषि क्षेत्र में घटते रोजगार के अवसरों को बढ़ाए जाने की जानकारी नहीं है।"

17. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि खेती योग्य भूमि का लगातार घटते रकबे को स्थिर बनाने या रकबा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।"

18. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में आए दिन बढ़ोत्तरी से किसानों को सिंचाई हेतु डीजल के दर बढ़ोत्तरी के प्रभाव से मुक्त कर नियंत्रित दर पर डीजल उपलब्ध कराने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

19. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में खेती भूमि की सिंचाई प्रणाली को और दुरूस्त करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

20. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त परिवहन सुविधाओं को कमी को समाप्त करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

21. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि पूरे देश खासकर गांवों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

22. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में सरकारी नौकरी पाने की आयु से ऊपर निकल चुके बेरोजगार पढ़े-लिखे शिक्षित नागरिकों को रोजागार के अवसरों के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

23. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पूरे वर्ष काम मिले, इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं है।"

24. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के समस्त नागरिकों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

(सीजीएचएस) की तय सरकारी दरों के समान आम नागरिकों के इलाज हेतु अस्पतालों एवं जांच केन्द्र को चार्ज लेने की बाध्यता, जिससे आम नागरिक भी कम दर पर अपना इलाज करा सके, के संबंध में जानकारी नहीं है।"

25. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों की रखरखाव को और सुदृढ़ करने तथा नये गोदामों के निर्माण हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

26. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ा कर निजी स्कूलों के समान लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

27. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि विद्यालयों से बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ने की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

28. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत व अभेद बनाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

29. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि छोटे-शहरों, कस्बों तक औद्योगिक प्रगति और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में उल्लेख नहीं है।"

30. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के तहत लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

31. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि बैंकों में अपनी जमा राशि पर बचत बैंक खातों से विभिन्न मदों में बैंकों द्वारा काफी कम बैलेंस तो कभी अन्य मद में राशि खर्च करने की नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साफ और बैंकों के लिए बाध्यकारी बनने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

32. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में चल रहे पोंजी योजनाओं जिनसे नागरिकों को गुमराह कर

उनकी मेहनत की धनराशि हड़प करने वाली पोंजी योजनाओं की रोकथाम और कानून के दायरे में लाने हेतु कदमों की जानकारी नहीं है।"

33. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि दिल्ली सहित देश में महानगरों में बढ़ते प्रदूषण को मानक के अनुरूप लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

34. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर पूरी तरह रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

35. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि भारतीय रेल की लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर विराम लगाने हेतु उठाए जाने वाले सार्थक कदमों की जानकारी नहीं है।"

36. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अत्यधिक विलंब से संचालित ट्रेनों को समय पर चलाए जाने का उल्लेख नहीं है।"

37. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि रेलवे में अत्यधिक रिक्त पदों को समय पर भरने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।"

38. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि बैंकों के लगातार बढ़ रहे एनपीए को कम करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

39. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि किसानों को कृषि कार्य हेतु बैंकों द्वारा कर्ज को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

40. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रिक्त पड़े विभिन्न शिक्षकों के पदों को भरने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

41. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर नियुक्तियों को समय पर भरने में विलंब को दूर करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

42. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी तथा अगले पंचवर्षीय योजना की घोषणा न करने से विकास हेतु विकास हेतु विभिन्न मदों में धनराशि की उपलब्धता और कार्यनीति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

43. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए जनगणना में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबों के लिए चलाए जाने वाले योजनाओं में आंकड़ों के आधार पर समावेश हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

44. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए जनगणना में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन का मापदण्ड महंगाई दर को देखते हुए पुनः निर्धारित कर योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

45. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश से पूरी तरह नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदमों की जानकारी नहीं है।"

46. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि भारतीय समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ते या भूलवश जल सीमा के पार गए भारतीय मछुआरों को पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा पकड़ने की घटनाओं के शीघ्र समाधान हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

47. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि नोटबंदी के दौरान ऑनलाइन लेन-देन पर छूट के बावजूद विभिन्न बैंकों द्वारा वसूले गए चार्ज को वापस उपभोक्ताओं/खाताधारकों के खाते में वापस दिलाए जाने के बारे में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

48. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के न्याय व्यवस्था मे रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है जिससे मुकदमों को शीघ्र निपटा कर समय पर नागरिकों को न्याय मिल सके।"

49. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि नये जाली नोटों की रोकथाम हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

50. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि नोटबंदी से कालेधन की प्राप्ति की संतोषजनक जवाब न देने से उत्पन्न भ्रम की स्थिति को दूर करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

51. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि दिल्ली क्षेत्र में लगातार यमुना नदी के सिकुड़ते आकार और यमुना नदी के पानी में बढ़ते जहरीले तत्व से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

52. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि चीन द्वारा हड़पी गई भारतीय क्षेत्र को पुनः भारतीय परिधि में लाए जाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

53. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

54. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि कुशल कामगारों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों के देश से पलायन रोकने हेतु जानकारी नहीं है।"

55. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश में लगातार बढ़ रहे अमीरों एवं गरीबों की खाई कम करने की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

56. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि मानव तस्करी रोकने की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

57. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि मशीनों का सीमित उपयोग जिससे बेरोजगारी कम हो की दिशा में किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

58. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु उठाए जाने वाले सार्थक कदमों की जानकारी नहीं है।"

59. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचारों-दुराचारों को समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं है।"

60. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि ई-वेस्ट के उचित निपटारे हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

61. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि विलुप्त हो रहे वन्य संपदा के संरक्षण हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

62. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि भ्रष्ट अफसरों को दंडित करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

63. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि प्रधान मंत्री आवास योजना की धनराशि बढ़ाकर 5 लाख करने जैसे प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।"

64. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि देश के सभी तालाबों, जलाशयों में मौजूद सिल्ट सफाई करा कर इस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता को वर्षा जल द्वारा तालाबों एवं जलाशयों में अधिक जल एकत्रित करने की किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

65. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि देश के किसानों के उत्पाद खासकर दुग्ध उत्पादों की जीएसटी से बाहर रखा जाए।"

66. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि देश के दिल्ली सहित महानगरों एवं राज्यों की राजधानियों में

अत्यधिक बढ़ते वाहनों से ट्रैफिक व्यवस्था धराशाही न हो इसके लिए वाहनों के पंजीकरण पर कार्यनीति का उल्लेख नहीं है।"

67. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।"

68. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि देश के दूर-दराज के गांवों, कस्बों में शुद्ध पीने योग्य पानी की उपलब्धता हेतु कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

69. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि बुन्देलखंड में कई वर्षों से पड़ रहे सूखे के समाधान हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है और इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों की आर्थिक मदद का उल्लेख नहीं है।"

70. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश की 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु उल्लेख नहीं है।"

71. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास हेतु अतिरिक्त सहायता हेतु किसी कार्य-योजना की जानकारी नहीं है।"

72. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि बुंदेलखंड के नागरिकों को प्रति वर्ष सूखे के कारण आने वाली दिक्कतों के समाधान हेतु अतिरिक्त राशन, आवास, पीने योग्य पानी एवं खेती के लिए किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है।"

73. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि अलाभकारी कृषि को देखते हुए सभी किसानों और वृद्धों को कम से कम 2000 रुपया पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।"

74. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि बुंदेलखंड के निवासियों को पलायन को रोकने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानकारी नहीं है।"

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

75. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आरक्षण नीति में शामिल न किए गए वंचितों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिशों के उपबंधों के अनुसार इस नीति की प्रत्येक दस वर्ष में समीक्षा नहीं की जा रही है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 76 to 77, Ch. Sukhram Singh Yadav; absent. Then, Shrimati Chhaya Verma; absent. Then Amendment Nos. 78 to 81 by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

78. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि देश की सुरक्षा सेना के तीनों अंगों में बाढ़ जैसी दैवीय आपदा से निपटने हेतु जन्मजात मछुआ समुदाय के नौजवानों की भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाए।"

79. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि जनगणना 2011 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण नीति में समावेशन हेतु उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी नहीं है।"

80. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि गंगा सहित महत्वपूर्ण नदियों के सफाई अभियान में नदी किनारे निवास करने वाले मछुआ समुदाय के नाविकों को 50 फीसदी आरक्षण भर्ती में प्रदान किया जाए।"

81. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की तरह एकलव्य पुरस्कार दिए जाने का जिक्र नहीं है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 82 to 90 by Shrimati Chhaya Verma; absent. Then Amendment Nos. 91 to 95 by Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move:-

91. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the grant of Special

Category Status to the residuary State of Andhra Pradesh inspite of the assurance given by the then Prime Minister on the floor of Parliament on 20th February, 2014 and the then Union Cabinet decision on 3rd March, 2014."

92. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the Government's commitments made in Schedule 10 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 including establishing a Railway Zone headquartered at Visakhapatnam, an Integrated Steel Plant at YSR District, a port at Duggirajapatnam etc., in Andhra Pradesh."

93. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the Government's commitment to bear the complete costs of the Polavaram National Project at the current, post-2014, price levels."

94. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the address does not mention about fulfillment of the assurance given to the successor State of Andhra Pradesh that package for backward districts of Rayalaseema and North Andhra region would be given on the lines of Bundelkhand in UP and MP and KBK districts in Odisha, as mentioned in the Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014."

95. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention that the Government is committed to greater political participation of women by securing passage of the Constitutional Amendment Bill for the reservation of seats for women in Parliament and State Legislatures at the earliest."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 96 to 107 by Shri Naresh Agrawal.

श्री नरेश अग्रवालः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः-

96. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्ः—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में उल्लेख नहीं है।"

[श्री नरेश अग्रवाल]

97. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान विदेश नीति के बारे में उल्लेख नहीं है।"

98. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर समस्या के समाधान के बारे में उल्लेख नहीं है।"

99. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनकी उपज का डेढ़ गुना मूल्य दिए जाने के बारे में उल्लेख नहीं है।"

100. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा कराने के संबंध में उल्लेख नहीं है।"

101. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दिए जाने के बारे में उल्लेख नहीं है।"

102. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।"

103. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा के संबंध में किए जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं है।"

104. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलितों पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रतिं संवेदनहीनता का उल्लेख नहीं है।"

105. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति का उल्लेख नहीं है।"

106. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय रेल की गिरती दशा के बारे में उल्लेख नहीं है।"

107. कि प्रस्ताव के **अंत** में निम्नलिखित **जोड़ा** जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति के बारे में उल्लेख नहीं है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 108 to 188 by Dr. T. Subbarami Reddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move:-

108. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing Special Development Package/Central Grants for the State of Andhra Pradesh in the backward districts of Rayalaseema and north Coastal Andhra Pradesh."

109. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about giving tax incentives for the State of Andhra Pradesh to compensate revenue deficit in the State."

110. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to expedite national Polavaram multi-purpose project for providing water and electricity to the State of Andhra Pradesh.

111. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to take all necessary measures as enumerated in the 13th Schedule of A.P. Reorganisation Act for the progress and sustanable development of the successor States."

112. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to take appropriate fiscal measures, including offer of tax incentives, to the successor States to promote industrialization and economic growth in both the States, as provided in the A.P. Reorganisation Act."

113. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about expanding existing Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati airports to international standards."

[Dr. T. Subbarami Reddy]

114. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about creation of separate railway zone with the headquarters at Visakhapatnam, as provided in the A.P. Reorganisation Act."

115. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about waste, polluted water from drains discharged into the major rivers of the country, particularly, the Yamuna, the Ganga, the Godavari, and the Krishna."

116. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting an end to economic disparity."

117. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about making polluted cities of the country pollution-free."

118. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need of balanced growth in the country."

119. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about brining appropriate reforms in the present education system and making it employment-oriented."

120. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the formulation of a national level action plan for water conservation."

121. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of a comprehensive scheme for tackling growing unemployment and to create more employment opportunities in the rural areas."

122. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulation of a national level action plan for land conservation in the country."

123. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about improving the quality of programmes being broadcast/telecast by Akashwani and Doordarshan in the rural parts of the country."

124. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steep rise in the incidents of murder of old people, women and children and providing proper security in the metropolitan cities."

125. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about formualation of effective scheme for the welfare of landless labourers."

126. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing telecom services on priority basis in the backward and rural areas of the country."

127. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about arresting the steep fall in the ground water level in the country."

128. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the formulation of National Livestock policy."

129. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the development of the tourist spots of the country particular in Andhra Pradesh in order to attract domestic and foreign tourists all the year round."

130. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to bring rational changes in the income-tax structure."

[Dr. T. Subbarami Reddy]

131. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking measures for increasing the production of foodgrains, pulses and edible oils in proportion to the increasing population in the country."

132. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the prevalence of fake currency in Indian market which tends to weaken the economical structure of the country."

133. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret, that the Address does not mention about the increasing pendency of the cases in various courts including High Courts and Supreme Court."

134. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about adopting modern technology for agricultural development in the country."

135. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about adopting new technology in the sugar industry of the country for increasing the production."

136. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about putting a check on the tendency of dropping-out from the schools by a large number of boys and girls in the primary and middle classes of the schools in the country."

137. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about establishment of agriculture science centres in all the districts of the country."

138. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing loan assistance by re-structuring the loans to be given to the farmers by Nationalised Banks/

Cooperative Banks in view of adverse weather conditions and natural calamities."

139. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about improving industrial production in the country."

140. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to achieving annual export targets."

141. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about checking increasing activities of I.S.I, in the country."

142. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about resolving the border disputes among different States in the country."

143. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about resolving the water disputes among different States in the country."

144. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the necessity of providing drinking water to every village in the country."

145. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about satutory plans for compensation to the victims of violence especially the victims of communal riots and rehabilitation to such victims."

146. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about an effective industrial policy to check migration from rural areas to cities."

[Dr. T. Subbarami Reddy]

147. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to immediate reforms in judicial process to deliver expeditious justice."

148. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the facilities to be provided for the upliftment of women belonging to the backward and rural areas of the country."

149. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about measures to check brain drain of specialists, technicians, scientists and doctors from the country."

150. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about overcoming the shortage of cold storages for storing vegetables, potatoes, onions and other perishable goods in the country."

151. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the lack of transportation facilities in more than half of the rural areas of the country."

152. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to take steps to protect and provide financial and marketing assistance to small and taditional industries in the wake of entry of big multinational companies and big industrial houses."

153. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about launching a computer based education system in the rural areas."

154. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing about

necessary reforms for ensuring efficiency, efficacy and accountability in administration."

155. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient funds for specific programme to encourage girls and women in the fields of sports."

156. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about popularizing sports like Judo and Karate among girls and women for self-defence."

157. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to purchase sophisticated defence equipments in time."

158. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to modernize the fleet and submarines in Indian Navy which witnessed frequent break-downs and failures recently."

159. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing easy access to the farmers in scientific research particularly in the area of bio-diversity."

160. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about financial assistance to voluntary sports clubs in cities and villages."

161. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sports facilities to youth through Residents' Welfare Associations."

162. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about playing the conventional role by India in promoting peace, stability and security in international relations."

[Dr. T. Subbarami Reddy]

163. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing security to all important nuclear plants and establishments in the country."

164. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about improving the facilities provided to Central Reserve Police Force and other central security forces."

165. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about streamlining the public administration system across the country."

166. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about filling up the posts of thousands of officers and defence personnel lying vacant in Indian Army, Air Force and Navy."

167. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing good quality mid day meal to the children during recess in the school."

168. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about opening of various monuments/heritage sites for viewing by common public on the line of Taj Mahal, to promote tourism."

169. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up of any regulatory authority for monitoring, and regulating the income generated through telecast of sports tournaments."

170. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to formulate Pricing Policy of Drugs due to wide difference in the manufacturing cost of the medicines and their retail prices."

171. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing more funds for Scientific and Industrial Research."

172. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about supplying coal according the demand to the Thermal Power Stations, steel and cement plants throughout the country."

173. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to ban the spurious medicines in the country."

174. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about making Khadi Village Industries Commission more result oriented and productive."

175. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:'—

"but regret that the Address does not mention about augmenting domestic production of crude oil to become self-reliant in the filed of crude oil ana to decrease the continuous import of crude oil."

176. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing adequate storage capacity in public sector of agricultural produce and about promoting creation of storage facilities in private sector."

177. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up an animal husbandary and dairy work research centre in Andhra Pradesh for helping the farmers."

178. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about effectively implementing the technology mission in the field of horticulture."

[Dr. T. Subbarami Reddy]

179. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing loan facility to farmers through cooperative primary banks, rural banks and commercial banks."

180. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing housing facility to mining workers."

181. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing sufficient number of doctors, medical equipments, medicines in ESI hospitals."

182. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about introducing environment and climate change as a compulsory subject at the primary level schooling."

183. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about opening of residential schools in each development block to promote girl-education at primary school level."

184. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing special assistance to para-military forces like ITBP, CRPF, BSF for purchasing vehicles, modern communication technology and weapons to keep vigil on borders and stop infiltration."

185. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about providing grants and technical facilities for the articles made by the Indian craftsmen/artisans through the cottage and small-industries "of the country and encouraging the export of produced goods."

186. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about steep rise in the prices of petrol and diesel, which is increased marginally on day to day basis."

187. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about enacting appropriate legislation to ensure major role of local panchayats in the preparation of development schemes for the rural development of the country."

188. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about formulating appropriate policy to meet the challenge of deteriorating political, economic and social situation in the country."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 189 to 193 by Dr. Pradeep Kumar Balmuchu; absent. Then, Amendment Nos. 194 to 217 by Shri Kiranmay Nanda.

SHRI KIRANMAY NANDA (Uttar Pradesh): Sir, I move:-

194. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about atrocities on Dalits and Minorities in various States, which cause loss of human life and property."

195. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about attacks on Minority in the name of Cow protection."

196. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about sharp increase in unemployment caused by demonetization and GST."

197. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there Is no mention in the Address about increasing incidence of sexual attacks on girls specially on minor girls."

198. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about sharp hike in the prices on general commodities by which common man is affected."

[Shri Kiranmay Nanda]

199. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about increasing trend of farmers suicide due to sharp increase in their financial debts."

200. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about increasing problems of potato growers."

201. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about uncontrolled air and water pollution in the NCR and other cities in the country."

202. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about increasing trend of Cancer and Diabetes in the country."

203. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about eradication of child labour from the country."

204. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about continuous increase of Petrol prices under new Petrol pricing Policy."

205. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about out come of dream project of Prime Minister about Sansad Aadarsh Gram Yojana." .

206. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about usefulness of Toilets in absence of piped water supply."

207. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address is to mention how to improve quality of education in Government Primary Schools, which makes foundation of nation".

208. That at the *end* of the motion, the following be added namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about sharp decrease in ground water level, in spite of rain water harvesting schemes being already in implementation".

209. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about very sharp increase of communal and religious intolerance".

210. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about in the digital transactions and threat of cyber crimes to digital world".

211. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about dying Small Scale Industry of our country due to dumping policy of China to kill our Industrial growth".

212. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about our tense relations with China and Pakistan".

213. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about increasing trend of Bank's NPAs, affecting financial health of Indian Banking System".

214. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the concrete measures taken so far for doubling of farmers income".

215. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about Waste (Kachara) management and processing etc."

216. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about continuous devaluation of Indian Rupee as compared to US Dollar".

[Shri Kiranmay Nanda]

217. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about amount of black money collected so far by Government through demonetisation".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 218 to 231 by Shri T.K. Rangarajan, Shri C.P. Narayanan, Shri K. Somaprasad and Shri K.K. Ragesh. Yes, Shri T.K. Rangarajan.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I move:—

218. That at the *end* of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities, including petrol and diesel."

219. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about growing unemployment and the jobless growth phenomenon in the country and also the failure of the Government in providing employment to the unemployed as promised earlier."

220. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the growing intolerance manifesting in the violence against writer and cultural activities and spread of communal polarization in the country."

221. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the agrarian crisis and increasing suicide of farmers in the country due to faulty policy of the Government."

222. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the growing incidents of mob lynching, for increase the recent brutal killing of a migrant labourer in Rajasamand, Rajasthan and another in Gujarat."

223. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the increasing attacks and atrocities on dalits, tribals and Adivasis in the country."

224. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the lack of transparency in the selection of judges as well as the accountability of judiciary towards the people."

225. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the natural calamities including Okhi cyclone and subsequent loss of lives and properties particularly in Kerala, Tamil Nadu, Lakshadweep and other parts of the country and failure of the Government to provide adequate compensation to the affected States."

226. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention In the Address about the guidelines for the Government for liberalizing Foreign Direct Investment (FDI) and portfolio management."

227. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the deprivation of vast majority of poor people for food under Public Distribution System in the country even after implementation of the Food Security Act."

228. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill."

229. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to allot 6 per cent of GDP to education as well as 5 per cent of GDP to health sector."

230. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of

[Shri T.K. Rangarajan]

Government to bridge the gap of demand and supply of electricity and under utilisation of the hydro electric power potential of various rivers in Kerala."

231. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about Justice Ranganath Misra Commission report which recommended 10% reservation for Muslims and 5% for other minorities, based on socially and economically backward criteria."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 232 to 259 by Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I move:

232. That at the *end* of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not reiterating India's commitment to pursue an independent foreign policy."

233. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not refer to the continuous attack on the ideals enshrined in the Constitution of the country."

234. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not refer to the increasing attack on the constitutional and democratic rights of the citizens."

235. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not refer to the issue of judicial accountability and to the prevailing crisis in judiciary in general and higher judiciary in particular."

236. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing incidents of atrocities on people of Dalit communities in the country."

237. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to repeal the archaic sedition law which is not needed in the democratic India."

238. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of attempt to take away the land rights of tribals given under the Forest Rights Act to facilitate coal mining in certain tribal villages."

239. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to enact a central legislation for the welfare and security of the agricultural workers in the country."

240. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the attempts to curtail trade union rights of the workers in the name of ease of doing business."

241. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the prevailing crisis in the agriculture sector and increasing incidents of farmes committing suicide in the country."

242. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the abnormal increase in the Non-Performing Assets (NPAs) of the public sector banks and the need to take stringent measures to recover the defaulted loans from the willful defaulters particularly in the corporate sector."

243. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the continuous slow down in-the growth rate of economy."

244. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note to attract the continuous decline in India's export during the last few years."

245. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the delay in passing

[Shri D. Raja]

the legislation on Reservation for women in the Parliament and State Assemblies."

246. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the deteriorating quality of education, particularly at the higher level in the country."

247. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the increasing commercialization of education sector making it impossible to get quality education for the common people."

248. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the deteriorating condition of the public health facilities in the country compelling the poor patients to avail medical treatment from costly private medical institutions."

249. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the increasing incidents of crime against women and children in the country."

250. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the government to solve the problem of unemployment particularly of the educated youth in the country."

251. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to recognize the 'scheme workers' numbering a crore in the country mostly women working under various schemes of the Government of India, as workers, as per the recommendations of the 45th- Indian Labour Conference making them eligible for PF, ESI and other social security benefits."

252. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the increasing attacks on the trible people in the country, particularly in Chhattisgarh."

253. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the fact decision of demonetization of currency notes of Rs. 500 and Rs. 1000 denominations pushed the economy as well as the common people into a distressful condition."

254. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take note of the fact that certain right wing forces in the country are trying to destory the secular-democratic fabric of the country by attacking the Universities, all educational and cultural institutions, freedom of speech, right to dissent, minorities, dalits, tribals and progressive activists."

255. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the diversion of allocations made for sub-plans for Tribals and SC/ST."

256. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the increasing number of derailments in Railways due to deterioration of safety standards and ignoring the recommendations of various reports on accidents in the Railways."

257. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the continued protest of the Ex-servicemen demanding full implementation of the One-Rank-One Pension (OROP)."

258. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the thousands of villages still remain without electricity in the country."

259. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the disinvestment, of the public sector undertakings thereby weakening the fundamentals of the economy."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment No. 260 by Shri Narain Dass Gupta; absent.

Now, Amendment Nos. 261 to 268 by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Sir, I move:-

261. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the dignity and pride that a Muslim woman enjoys under Shariah Law and has therefore, undermined the status of Muslim women."

262. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the condition of the 85% women from religions other than Muslim in the country, who are facing daily harassment and are fighting legal battles after their husbands have deserted them for years without any maintenance and without even giving divorce, and the Government's policy about such, women."

263. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the relaxation given to the women above 45 years of age to perform Haj Pilgrimage in a group of four is as per the new guidelines and exemptions given by the Saudi Government from the ensuing Haj season and that the Indian Government has adopted the new Saudi policy."

264. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take notice of the plight of the Muslim women who are socially and educationally backward and have negligible representation in Government Services."

265. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention the reasons as to why subsidy on Haj had to be abolished with immediate effect and the amount of subsidy Government was paying."

266. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not take notice of the increased incidents of Communal violence's in the country."

267. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the alarming financial health of the Indian Banks due to increase in NPA's of the Public and Private sector Banks which according to finance ministry stands at ₹ 7,73,974 crore and ₹ 1,02,808 crore, respectively as on 30.09.2017."

268. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention the reasons as to why the Petrol and Diesel prices were not reduced proportionately in spite of a huge fall in the oil prices at the international market."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment Nos. 269 to 272 by Shri K.K. Ragesh.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I move:-

269. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"out regret that there is no mention in the Address about the growing attack on freedom of speech and expression as manifested in the henious killings of Gauri Lankesh, Kalburgi, Narender Dhabolkar, Govind Pansare, etc."

270. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the drastic cut in subsidies including fertilizers, LPG, Diesel etc."

271. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the growing NPA in public sector banks and the Government's decision to write off the NPA as book adjustment."

272. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the injustice by State Bank of India in imposing fine on poor account holders who are unable to maintain monthly average balance."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment Nos. 273 to 297 by Shri Motilal Vora.

SHRI MOTILAL VORA (Chhhattisgarh): Sir, I move:-

273. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the halting of businesses and difficulties being faced by the common masses due to sealing in Delhi."

274. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the military structures being set up by China in Doklam."

275. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the communal riots that took place in Kasganj, Uttar Pradesh on Republic Day."

276. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the ongoing dispute between Punjab and Haryana Governments on SYL Canal and redressal of difficulties being faced by farmers in irrigating the land."

277. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to stop the migration from villages as farming is increasingly becoming unprofitable."

278. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any plan for stabilizing or increasing the area of steadily shrinking land holdings of cultivable land."

279. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for addressing the lack of adequate transport facilities in rural areas."

280. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for ensuring 24 hours availability of electricity across the country."

281. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken with regard to employment opportunities for the educated citizens of the country who have crossed the stipulated age for getting Government jobs."

282. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken to ensure availability of work for the labourers of unorganised sectors throughout the year."

283. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the obligation of realizing charges by the hospitals and test centres for the medical treatment of common citizen at the rate fixed by the C.G.H.S. with a view to providing medical treatments to ail the citizens of country."

284. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to strengthen the storage of foodgrains in Government godowns and for construction of new godowns.

285. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about raising the standards of education in Government schools so that parents' preference toward private school diminishes."

286. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to strengthen the internal security of the country and to make it strong and fool proof."

287. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to stop ponzi schemes which usurp the hard earned money of the citizens by misleading them or bringing them in the purview of law of the country."

[Shri Motilal Vora]

288. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to bring the rising pollution in the metro cities of the country including Delhi as per the norms."

289. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for putting a complete check on adulteration of food items."

290. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention making adulteration free pure milk available to the children in the country."

291. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for filling up the various posts of teachers lying vacant on large scale in the education sector of the country."

292. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about concrete steps to be taken to wipe out naxalism from the country."

293. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely.—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken for an early solution of incidents of arrest of Indian fishermen by neighbouring countries of Sri Lanka and Pakistan who unknowingly cross the country waters while going for fishing."

294. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps taken for appointment on vacant posts in higher judiciary by which justice can be given to citizens on time by early disposal of cases."

295. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about steps to be taken to bring back the land area in Indian territory that was annexed by China."

296. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to be taken to the provide equal education to all the children of the country."

297. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any steps to be taken ever increasing gap between the rich and the poor of the country."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment Nos. 298 to 324 by Shri Husain Dalwai.

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, I move:-

298. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about rising intolerence in the form of attacks on minority communities by vigilante groups and failure of government to protect these communities."

299. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about attacks on Dalits in States like Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh."

300. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the inability of the Government to ensure protection of women from sexual and physical abuse, to utilise the Nirbhaya Fund and to criminalise marital rape."

301. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government in addressing concerns of the transgender community in the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016 arid extending reservation benefits to them."

302. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the lack of interest of the Government to introduce the Women's Reservation Bill on a priority basis."

[Shri Husain Dalwai]

303. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the rising Non-Performing Assets (NPAs), failure of Public Sector Banks to recover these NPAs even though banks go about collecting charges from account holders who are unable to maintain minimum balance."

304. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not condemn the inability of the Government to take adequate steps for welfare of unorganized sector workers."

305. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to reduce dependence of farmers on informal sources of capital and instead increase access to formal institutionalized source of capital and the need to encourage organised retail to prevent market dominance as well as allow easy access to land through leasing and contract farming models."

306. That the *end* of the Motion the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the fall in prices of crops as well as climate change induced temperature and rainfall ariability affecting farmer's earnings leading to rise in farmer suicides."

307. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about rising income inequality in India."

308. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the failure of the Government to adequately address the issue of manual scavenging despite the enactment of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation act."

309. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the issue of low adoption rate of technology, in rural areas due to lack of technology enablers, which is making

schemes related to e-health, e-governance, e-education and e-commerce ineffective."

310. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the problem of malnutrition faced by India, which ranks 100 out of 119 countries on the Global Hunger Index."

311. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention that while providing Constitutional status to the National Commission of Backward Classes, there are apprehensions over diluting the existing powers of the Commission."

312. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the attempts being made to dilute the protection provided to tribals under the Forest Rights Act, through several measures, for instance by delay for the formulation of rules under the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016."

313. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not condemn the mistreatment of activists protesting against increasing height of Sardar Sarovar Dam and displacement of several people without adoption of adequate rehabilitation measures."

314. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about attacks on free speech and the inability of the Government to protect journalists, RTI activists, whistleblowers who stand for free speech."

315. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the introduction of electoral funds will adversely affect transparency in election funding and strengthen the business political nexus.

316. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the lack of steps taken to ensure preparedness and build capacity to deal with natural disasters of many

[Shri Husain Dalwai]

States suffered immense loss of life and property due to Cyclone Ockhi, one of the most intense cyclones in the country, due to their unpreparedness."

317. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to stabilize the situation in Jammu and Kashmir and the lack of clarity with respect to the role of representative of the Indian Government appointed to conduct talks with different stakeholders."

318. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention that India is one of the four worst performing countries (ranked 177 out of 180 countries) in the Environmental Performance Index 2018."

319. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the increasing number of road accidents and inadequate measures to upgrade quality of roads and incomplete and slow construction work on NH-66, connecting Mumbai to Goa, which has caused several road accidents killing many people every year."

320. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention that anganwadi workers are not receiving timely payment of wages."

321. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the issues faced due to linkage of Aadhaar, including security issues like bank frauds, authentication failures leading to exclusion deaths and disruptions in availability of entitlements under various welfare schemes."

322. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the increasing train accidents,

poor railway infrastructure and inadequate investment is safety as in a short period of 1 August and 30 November, 2017, 30 train accidents killed 35 people and injured more than 180 people resulting in the highest death toll from train derailments in 2016-17."

323. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about high rates of GST on basic necessities like sanitary napkins and assistance devices for persons with disabilities."

324. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the insufficient investment in welfare of fishermen to create necessary infrastructure and protect their rights and interests."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Motion and the Amendments moved are open for discussion.

The questions were proposed.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आजाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यहां राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने और उनको धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बधाई देता हूं माननीय अमित शाह जी को, पहला भाषण इनका हुआ, मेडन स्पीच हुई। इसलिए हम लोगों ने बड़े ध्यान से उनका भाषण सुना, लेकिन उनके भाषण मे सरदार पटेल जी का नाम नहीं आया, यह देखकर, सुनकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि दो-तीन चीजों की तथा अन्य और बातों की 2014 के इलेक्शन में बहुत चर्चा हुई थी। हम लोगों पर आरोप लगा था कि हम सरदार पटेल का आदर नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा मैं यह कहूंगा कि जब कभी भी हमने गांधी जी और नेहरू जी का नाम लिया है, साथ में सरदार पटेल जी का नाम जरूर बचपन से लिया है, बल्कि मौलाना आज़ाद का भी नाम लिया है। इन तीनों-चारों का नाम इकट्ठा लेते आए हैं। सुभाष् चन्द्र बोस को एक अलग तरीके से हम और महत्व देते आए हैं कि उन्होंने भारत की सीमाओं से लेकर और अम्बेडकर जी का उनका कांस्टीट्यूशन बनाने में जो रोल रहा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में कुछ अंदर रोल करते थे, कुछ देश से बाहर करते थे कांस्टीट्यूशन वाले, उनका अलग किरदार रहा। बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, बहुत है। सब राजनति दल, उनके नेताओं को अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन जिस बुनियाद पर 2014 में यह सरकार बनी थी, 2013 के आखिरी कुछ महीनों से माननीय प्रधान मंत्री के उम्मीदवार हो गए थे, तो जो सबसे बड़ा

[श्री गुलाम नबी आजाद]

आरोप यू.पी.ए. सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया गया था, आज आपकी ही सरकार, बहुत खुश हुई कि आज हमारी सरकार में अगर हमको कोर्ट अदालतें और अटॉर्नी जनरल शायद उन आरोपों से मुक्त कराते तो हम पर जरूर यह आरोप लगता कि हमसे प्रभावित होकर, सरकार से प्रभावित होकर सी.बी.आई. कोर्ट ने निर्णय लिया 2जी का, तो हमारे खिलाफ जो हिमालय का पहाड़ खड़ा किया गया था, सबसे भ्रष्ट सरकार का नाम लिया गया था, सैंकड़ों और हजारों सभाओं में, शुक्र है कि आपकी ही सरकार में उस सी.बी.आई. के जज ने उन तमाम दोषियों को बरी कर दिया। तो आपने जो इमारत खड़ी की थी, जो रेत की दीवार, रेत का हिमालय आपने बनाया था, वह चार-पांच साल तक तो चला, लेकिन गांधी जी हमेशा कहते थे कि सत्य की विजय होती है - आखिरकार सच की विजय हुई। बोफोर्स पर कई सरकारें बनीं। 1986-87 से लेकर, बल्कि शायद भारत के इतिहास में पहली दफा हुआ कि लेफ्ट, राइट और सेंटर सब कांग्रेस के खिलाफ एक हो गए। मैं उस समय यूपी का इंचार्ज था और देख रहा था कि सब पोलिटिकल पार्टीज़ एक फोरम से भाषण कर रही थीं। भगवान माननीय वी.पी. सिंह साहब को स्वर्ग में जगह दे, वे जेब में एक कागज़ लिए हर वक्त मीटिंग में कहते थे, यह मेरी जेब में कागज़ है, आप हमारी सरकार बना दो और मैं दूसरे दिन नाम बता दूंगा। आप सब लोगों ने मिलकर उनकी मदद की, वे प्रधान मंत्री बने, लेकिन उनके जीवन-काल में वह कागज़ उनकी ऊपर वाली जेब से नहीं निकला। तब से लेकर आज तक कई प्रधान मंत्री बने, वे बोफोर्स की आग पर अपनी रोटियां सेंकते रहे। मैं भगवान का लाख-लाख शुक्र करता हूं कि आपकी सरकार ने ही, आपके ही Attorney General ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि इस पर और कोई सबूत नहीं है, इतने सालों से हम इस पर लगे हुए हैं। इसलिए वह बेबुनियाद था, फिर भी आप करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : مائنے ڈپٹی چیئرمین سر، میں یہاں راشٹر پتی جی کے ابھیبھاشن پر چرچا کرنے اور ان کو دھنیواد کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ میں بدھائی دیتا ہے مائنے امیت شاہ جی کو، پہلا بھاشن ان کا ہوا، میڈن اسپیچ ہوئی۔ اس لئے ہم لوگوں نے بڑے دھیان سے ان کا بھاشن سنا، لیکن ان کے بھاشن میں سردار پٹیل جی کا نام نہیں آیا، یہ دیکھہ کر، سن کر بڑی حیرت بھی ہوئی، کیوں کہ دو تین چیزوں کی اور دیگر باتوں کی 2014 کے الیکشن میں بہت چرچہ ہوئی تھی۔ ہم لوگوں پر آروپ لگا تھا

†Transliteration in Urdu script.

کہ ہم سردار پٹیل کا آدر نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ، میں یہ کہوں گا کہ جب کبھی بھی ہم نے گاندھی جی اور نہرو جی کا نام لیا ہے، ساتھ میں سردار پٹیل جی کا نام ضرور بچپن سے لیا ہے، بلکہ مولانا آزاد کا بھی نام لیا ہے۔ ان تینوں چاروں کا نام اکٹھا لیتے آئے ہیں۔ سبھاش چندر بوس کو ایک الگ طریقے سے ہم اور بھی اہمیت دیتے آئے ہیں کہ انہوں نے بھارت کی سرحدوں سے لے کر، اور امبیڈکر جی کا ان کا کانسٹی ٹیوشن بنانے میں جو رول رہا، کیوں کہ آزادی کی لڑائی میں کچھ دیش کے اندر رول کرتے تھے، کچھ دیش سے باہر کرتے تھے۔ کانسٹی ٹیوشن بنانے والے، ان کا الگ کردار رہا۔ بہت ساری چیزوں پر چرچا ہوئی۔ سب سیاسی جماعتوں کو، ان کے نیتاؤں کو اپنی بات رکھنے کا پورا حق ہے، لیکن جس بنیاد پر 2014 میں یہ سرکار بنی تھی، 2013 کے آخری کچھ مہینوں سےمحترم وزیر اعظم جی بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے کیمپین کمیٹی کے صدر اور پردھان منتری کے امیدوار ہو گئے تھے، تو جو سب سے بڑا الزام یوپی۔اے۔ سرکار کے خلاف، کانگریس کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، آج آپ کی ہی سرکار میں، بہت خوشی ہوئی کہ اگر ہماری سرکار میں ہم کو کورٹ، عدالتیں اور اٹارنی جنرل شاید ہمیں ان الزامات سے بری کراتے تو ہم پر ضرور یہ الزام لگتا کہ ہم سے متاثر ہو کر، سرکار سے متاثر ہوکر سی۔بی۔آئی۔ کورٹ نے فیصلہ لیا ٹو-جی کا، تو ہمارے خلاف جو ہمالیہ کا پہاڑ کھڑا کیا گیا تھا، سب سے کرپٹ سرکار کا نام لیا گیا تھا، سیکڑوں اور ہزاروں سبھاؤں میں، شکر ہے کہ آپ کی ہی سرکار میں اس سی۔بی۔آئی کے جج نے ان تمام دوشیوں کو بری کر دیا۔

تو آپ نے جو عمارت کھڑی کی تھی، جو ریت کی دیوار، ریت کا ہمالیہ آپ نےبنایا تھا، وہ چار پانچ سال تک تو چلا، لیکن گاندھی جی ہمیشہ کہتے تھے کہ ستیے کی وجے ہوتی ہے۔ آخرکار سچ کی وجے ہوئی۔ بوفورس پر کئی سرکاریں بنیں۔ 87-1986 سے

[श्री गुलाम नबी आजाद]

لیکر، بلکہ شاید بھارت کے اتیہاس میں پہلی دفعہ ہوا کہ لیفٹ، رائٹ اور سینٹر سب کانگریس کے خلاف ایک ہوگئے۔ میں اس وقت یوپی کا انچارج تھا اور دیکھ رہا تھا کہ سب پالیٹیکل پارٹیز ایک فورم سے بھاشن کررہی تھیں۔ بھگوان مانیئے وی پی سنگھ صاحب کو سورگ میں جگہ دے، وہ جیب میں ایک کاغذ لیے ہر وقت میٹنگ میں کہتے تھے، یہ میری جیب میں کاغذ ہے، آپ ہماری سرکار بنادو اور میں دوسرے دن نام بتادوں گا۔ آپ سب لوگوں نے ملکر ان کی مدد کی، وہ پردھان منتری بنے، لیکن ان کے جیون کال میں وہ کاغذ ان کی اوپر والی جیب سے نہیں نکلا۔ تب سے لیکر آج تک کئی پردھان منتری بنے، وہ بوفورس کی آگ پر اپنی روٹیاں سینکتے رہے۔ میں بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی سرکار نے ہی، آپ کے ہی Attorney General نے سپریم کورٹ کو بتادیا کہ اس پر اور کوئی ثبوت نہیں ہے، اتنے سالوں سے ہم اس پر لگے ہوئے ہیں ۔ اس لیے وہ بے بنیاد تھا، پھر بھی آپ کریں گے۔ ...(مداخلت)...

कुछ माननीय सदस्यः कर दिया।

श्री गुलाम नबी आज़ादः आपने कर दिया। आप उस नाम पर कितनी सरकारें बनाएंगे जिसमें उसके बाद इतने प्रधान मंत्री बने और विपक्ष की कई सरकारें बनीं। माननीय बीजेपी के अध्यक्ष ने यहां बताया कि माननीय मोदी साहब ने तीन चीज़ों से देश को मुक्त किया। आपने वंशवाद की बात की। ज़ाहिर है, आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले 29-30 साल से उनका कोई प्रधान मंत्री नहीं है। जब प्रधान मंत्री नहीं है तो आपने निजात किसको दिलायी है?

† **جناب غلام نبی آزاد:** آپ نے کردیا۔ آپ اس نام پر کتنی سرکاریں بنائیں گے جس میں اس کے بعد اتنے پردھان منتری بنے اور وپکش کی کئی سرکاریں بنیں۔ مانیئے بی جے پی کے ادھیکش نے یہاں بتایا کہ مانیئے مودی صاحب نے تین چیزوں سے دیش کو مُکت کیا۔ آپ نے ونشواد کی بات کی۔ ظاہر ہے، آپ جس پریوار کی بات کررہے ہیں، میں سدن کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 30-29 سال سے ان کا کوئی پردھان منتری نہیں ہے۔ جب پردھان منتری نہیں ہے تو آپ نے نجات کس کو دلائی ہے؟

श्री आनन्द शर्माः मंत्री भी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ादः मंत्री जी नहीं है, कोई सरकार में नहीं है, प्रधान मंत्री भी नहीं हैं। इससे पहले भी 1977 में आपकी ही पार्टी थी। उससे पहले भी दो प्रधान मंत्री बन गए, बल्कि तीन प्रधान मंत्री बन गए - लालबहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के थे, लेकिन दो गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री बन गए। तो ऐसा कहने केलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देता, यह जो डर उनके जीवित रहते था, अब कुछ

†Transliteration in Urdu script.

4.00 P.M.

लीडर्स ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन अब उनके बच्चों से भी आपको रात को नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? वह डर बना रहे।

आपने जातिवाद के बारे में कहा। मैं कहता हूं कि जातिवाद तो एक बहुत पुरानी चीज़ थी - आज़ादी से पहले थी। आज तो देश का बंटवारा हो गया है, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर में बंटवारा हो गया है। आज कोई किसी के साथ नहीं है। धर्मों का बंटवारा हुआ, जातियों का बंटवारा हुआ, एक-एक धर्म के कई बंटवारे हुए - मैं बाद में जब उन बातों पर आऊंगा, तब उनका उल्लेख करूंगा।

तुष्टिकरण के बारे में कहा गया। आप तुष्टिकरण के संबंध में जिस तबके की बात करते थे, आज दूसरी तरह का तुष्टिकरण है। आज पार्टी का तुष्टिकरण है और एक ही पार्टी चला रही है, उसी की बात सुनी जा रही है।

नीचे ब्लॉक से लेकर, ग्रामसेवक से लेकर सिर्फ उसी पार्टी के आदमी को काम मिलेगा, उसी को रोजगार मिलेगा, उसी को ठेका भी मिलेगा, इतनी भयंकर बात आज तक इतिहास में न सुनी थी, न पढ़ी थी।

माननीय उपसभापति जी, यह सरकार हर बात पर कहती है कि हमारी सरकार गेम चेंजर है। यह गेम चेंजर नहीं है, यह नेम चेंजर है। जितनी भी योजनाएं हैं - मेरे पास बहुत बड़ी सूची है, लेकिन मैं 20-22 योजनाओं का ही नाम लूंगा। जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जो 1985 के बाद कांग्रेस शासन में, यूपीए के शासन में बनी थीं, उनके नाम बदल दिए गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह गेम चेंजर नहीं है, नेम चेंजर है। इंदिरा आवास योजना, 1985 में बनी थी और एनडी की सरकार आने के बाद यह प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना बन गई। राजीव आवास योजना 2009 में Centrally-sponsored Scheme बनी थी, अब यह Sardar Patel National Urban Housing Mission बन गयी। मैं आपत्ति नहीं जताता हूं कि इसमें किसका नाम आ गया, मैं खाली नाम बदलने की बात करता हूं। निर्मल भारत अभियान अब स्वच्छ भारत बन गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बना दिया है। Basic Savings Accounts, 2005 में बन गया था, इसे अब जन-धन योजना बना दिया गया। National Project on Management of Soil Health and Fertility, यह योजना 2008 में बनी थी, अब यह सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम बन गयी। Swavalamban Pension Scheme for Unorganized Sector, 2010 में बनी, अब यह अटल पेंशन योजना बन गयी। हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2010 में बनाया था, अब यह स्किल इंडिया बन गया। JNNURM, 2005 में बना था, जब मैं इसका मंत्री था, यह अब AMRUT योजना बन गयी। Accelerated Irrigation Benefit Programme, 2007 में बना था, यह प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना बन गया। हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में बनाई थी, अब यह परम्परागत कृषि विकास योजना बन गयी। National Agriculture Insurance Scheme (NAIS), हमने 1985 में बनायी थी, अब यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना बन गयी। National Manufacturing Policy, 2011 में हमने बनाय, यह मेक इन इंडिया बन गयी। National Maritime Development Scheme, 2005 में बनी, अब यह सागरमाला बन गई। हमने Fortified Urea Policy, 2005 में बनायी, अब इसका हिन्दी में अनुवाद हो गया, तो नीम कोटेड यूरिया स्कीम बन गयी। जन औषधि स्कीम 2008 मे बनी थी, तब भी दवाइयों की सैकड़ों, हजारों दुकानें खुली थीं, अब यह प्रधान मंत्री जन औषधि योजना बन गयी। अब इसका नाम बदल गया, तो यह नई योजना हो गई। जैसे भारत का नाम Old Bharat से अब new

[श्री गुलाम नबी आजाद]

Bharat हो गया है, यह new India हो गया। आपने भारत को भी नहीं छोड़ा। National Governance Plan, 2006 में बना, तो अब यह Digital India बन गया। Universal Immunization Programme 1985 में बना, तो अब यह इंद्रधनुष बन गया। National Optical Fibre Network 2011 में हमने बनाया, अब यह Bharat Net बन गया। National Rural Livelihood Mission 2005 में बना था, यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण औषधि योजना बन गयी। National Direct Benefit Transfer 2013 मे बना, अब यह पहल बन गया। National Girl Child Day Programme 2008 में बना था, अब यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बन गया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 में बनी थी, अब यह प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना बन गई। ये इकनी स्कीम्स हमारी ही हैं, तो नई स्कीम्स कहां हैं? माननीय प्रधान मंत्री जी को याद होगा, मैंने वर्ष 2014 या 2015 में बताया था कि अगर पूरे 5 साल भी आप और आपका मंत्रिमंडल 24 घंटे उद्घाटन करते रहें, तो भी यू.पी.ए. की जितनी स्कीम्स लागू हैं, उनका उद्घाटन भा.ज.पा. का पूरा मंत्रिमंडल नहीं कर पाएगा और आज वही हो रहा है।

यहां बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हुई। हमे प्राइमरी स्कूल में टीचर बहुत डांटते थे कि घर के लिया दिया गया काम करते नहीं हो और कहते हो और काम दे दो। वह कहते थे, "आगे दौड़, पीछे छोड़" नहीं चलेगा। यहां लोगों से 2014 में बहुत वायदे किए गए थे। गरीब के account में 15 लाख रुपए जाएंगे, लेकिन उसका उल्लेख न तो महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में है और न ही बजट में। इस देश के नौजवान, ऐसे लड़के और लड़कियों की संख्या करोड़ों में है, जो आप से काम मांगते हैं। उनमें से कुछ ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, कुछ ने कम प्राप्त की है, आपने उनसे 10 करोड़ jobs देने का, 2 करोड़ साल में देने का वायदा किया था, लेकिन उसका भी न माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई उल्लेख है और न ही बजट में। इस देश के अन्नदाता किसानों के साथ, जो खून-पसीना बहाकर इस देश को पालते हैं, उनसे वायदा किया गया था कि आपकी लागत पर 50 परसेंट profit देंगे। हालांकि अब कुछ नज़र आता है, लेकिन वह वायदा बहुत भयंकर है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। एक और बड़ा वायदा डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें कम करने का किया गया था। मुझे याद है हमारे दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और आज के गृह मंत्री ढोल व तालियां बजाकर प्रदर्शन करते थे और भारत बंद होता था कि जब सब्जी, तेल, डीजल, गैस या पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए बढ़ते थे। जहां हमारे वक्त में गैस सिलेंडर का दाम 350 रुपए था, वह आज 800 रुपए में मिलता है। आज सब्जी, दालें और किसी भी चीज को हाथ लगाओ, तो वह कई सौ गुना महंगी है। मैं पेट्रोल व डीजल की कीमतों का जिक्र करूं। जहां हमारे वक्त में 111 और 120 डॉलर में एक बैरल तेल मिलता था ...(**व्यवधान**)... मैं सब से कम कीमत की बात कह रहा हूं, तब आज जितनी कीमत में डीजल, पेट्रोल मिलता है, उससे कम कीमत मे हम लोगों को देते थे। आज तो 30 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे crude oil आ गया है, लेकिन आपने 60 से 70 रुपए प्रति लीटर डीजल व पेट्रोल पहुंचा दिया है। आज आपको जो पैसा डीजल, पेट्रोल से बचा, यदि हमारे वक्त में ऐसी कीमतें होतीं, तो हमने भारत में एक क्रांति और इंकलाब लाया होता, लेकिन आपके वक्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप तो अभी भी हमारी स्कीम्स के फीते काटते हैं और उनका नाम बदलकर टेलिविजन और मीडिया में 24 घंटे दर्शाते हैं। आपका अपना कुछ नहीं है। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, प्रेजिडेंट एड्रेस में लिखा है, To make the country swachh by 2019. सर, जैसा मैंने कहा कि हमने यह "निर्मल भारत" की शक्ल में 2012 में शुरू किया था। सन् 2019 तक 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाने का वायदा हुआ है। अभी केवल 50 per cent ही टॉयलेट्स बने हैं। मुझे 50 per cent पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है कि अभी आधे टॉयलेट्स ही बने हैं। जब पौने चार सालों में आधे टॉयलेट्स बने हैं, तो आगे नौ या दस महीनों में, इलैक्शन मोड में कुछ महीनों के बाद बाकी के

आधे टॉयलेट्स कैसे बन सकते हैं? U.N. Special Report में कहा गया है कि out of the constructed toilets only 33 per cent are sustainable and safe, the rest 67 per cent are not usable. टॉयलेट्स के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपने घर में देखें कि हम सभी लोग टॉयलेट्स में पानी का इस्तेमाल करते हैं। यदि एक परिवार के दो-चार लोग टॉयलेट में चले जाएं और उसमें पानी न आए, तो हम उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। वह टॉयलेट किसी दूसरे आदमी के यूज़ के काबिल नहीं रहता है। आप इतने लोगों के लिए जो टॉयलेट्स बनाते हैं, अगर उनमें पानी की व्यवस्था न हो, फ्लश की व्यवस्था न हो, उसके सीवरेज के टैंक की व्यवस्था न हो, तो आप मुझसे कहिए, तो मैं बिना इस प्रकार की सुविधाओं के एक करोड़ टॉयलेट्स बनाकर दे दूंगा। आप चार दीवारी करिए एक सीट रख दीजिए, तो टॉयलेट तैयार हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी को quote नहीं कर रहा हूं, मैं यूएन रिपोर्ट को quote कर रहा हूं। एक RTI में कहा गया है कि "स्वच्छ भारत" के लिए साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए तीन साल में सिर्फ पब्लिसिटी के लिए खच हुए हैं। साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए इसकी पब्लिसिटी पर खर्च हुए हैं और जो आधे बने हैं, उनमें से 67 per cent usable नहीं हैं। जो टॉयलेट्स इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं, यह शायद उनके लिए पब्लिसिटी हो रही है। आपने एक नया नाम देकर हमारे 'निर्मल भारत' अभियान का यह हाल किया है।

सर, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ओ' का जिक्र किया गया है। मैं इसको बजट की दृष्टि से देखना चाहता हूं। अभी तक यह 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' 161 districts में था और पिछले साल में इसका बजट 200 करोड़ था। इस साल से इसको 161 districts से बढ़ाकर 640 districts किया है। That is four times districts बढ़ा दिए हैं। मुझे ज्यादा mathematics नहीं आता है, लेकिन यहां Finance Minister बैठे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जब आपका बजट पिछले साल दो सौ करोड़ था, तो इस साल आठ सौ करोड़ होना चाहिए, लेकिन बजट में बढ़ोतरी कितनी है, सिर्फ 80 करोड़। हमने बजट से ही स्कीम का गला घोंट दिया है। हमने districts तो बढ़ाए हैं चार गुना, लेकिन एमाउंट कुछ ही दशमलव बढ़ा दिया, तो यह स्कीम तो at the outset शुरू में ही खत्म हो गई, लेकिन आज यह सबसे बड़ा मुद्दा है। माननीय प्रधान मंत्री जी, बेटी को पढ़ाओ, तो बाद की बात है, लेकिन आज बेटी बचाओ की सबसे बड़ी जरूरत है। आप सुबह का अखबार पढ़ नहीं सकते हैं, चाहे वह हिन्दी का अखबार हो या अंग्रेजी का अखबार है। आप टेलीविजन भी नहीं देख सकते हैं। यह 'बलात्कार' शब्द एक जगह नहीं है, बल्कि पूरे देश में सब जगह है। आप नाराज हो जाएंगे, अगर मैं यह कहूंगा कि यह बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में सबसे भयंकर है। हरियाणा तो गढ़ बन गया है, मध्य प्रदेश और यू.पी. में भी बुरा हाल है।

उपसभापति जी, हम बलात्कार के बारे में हमेशा सुनते थे कि यह बुरी बात है, लेकिन यह पहली दफा सुना है कि पाँच महीने की, तीन महीने की, चार महीने की आठ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार! जिस वक्त यहाँ माननीय राष्ट्रपति जी भाषण दे रहे थे, दोनों सदनों को सम्बोधित कर रहे थे, उन दिन भी यहाँ दिल्ली में आठ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। हर मिनट के बाद बलात्कार हो रहा है। इसके लिए इस सरकार ने क्या किया है? इसके लिए कौन-से कदम उठाए हैं? उन मासूम बच्चियों के लिए, जो अभी साल भर की भी नहीं हैं, उनके लिए आपने क्या प्रबंध किया है? हम यह कौन-से भारत का निर्माण कर रहे हैं? यह कौन-सा नया भारत है? इस नये भारत की हमने कल्पना नहीं की थी। माननीय उपसभापति जी, आप नहीं कह सकते कि नया भारत लाए हैं, क्योंकि अगर यह नया भारत है तो मुझे ऐसे नये भारत पर अफसोस है। हमें वह पुराना भारत दे दो, जो भारत हमने छोड़ा था। हमें यह भारत नहीं चाहिए, जहाँ हमारी बहू, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मेरी बच्ची जाती है, तो मैं अपने सिक्युरिटी वाले - क्योंकि आपकी सरकार ने सिक्युरिटी वाले विदड्रा किए, इसलिए मैं

[श्री गुलाम नबी आजाद]

कहीं अपने प्रोग्राम्स कैंसिल करके रात में उसको भेजता हूं। इतना असुरक्षित यह देश बन गया है, यह शहर बन गया है, इस देश की राजधानी बन गई है!

उपसभापति जी, हमारे वक्त में भी निर्भया का एक केस हुआ था, लेकिन हम इतने सेंसेटिव थे कि हम तुरंत पार्लियामेंट में एक कानून लेकर आए। हम एक केस के लिए इतना बड़ा, मोटा कानून लेकर आए थे, लेकिन आज दिन में सैंकड़ों, हज़ारों केस होते हैं, पर इस सरकार के सिर पर जूं तक नहीं रेंगती, यह सरकार टस से मस नहीं होती।

उपसभापति जी, यहाँ "जन-धन योजना" की बात करते हैं। भाजपा का हर नेता, मंत्री "जन-धन योजना" की बात करता है। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से राजनीति में थोड़ी सी ईमानदारी की जरूरत है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी ईमानदारी की जरूरत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की तरफ से 31 करोड़ बैंक अकाउंट्स की बात की गई है, लेकिन कितना अच्छा होता, अगर आप ऐसा कहते कि 24 करोड़, 30 लाख एकाउंट्स तब से, यूपीए सरकार में खुले हैं और बीजेपी के वक्त में सिर्फ सवा 7 करोड़ एकाउंट्स खुले हैं। आपने सवा 7 करोड़ एकाउंट्स खोले और हमने जो 24 करोड़, 30 लाख एकाउंट्स खोले, उनका नाम भी नहीं, जबकि चौबीस घंटे "जन-धन योजना" सुनते-सुनते हमारे कान पक गए। यदि आप उसका भी उल्लेख करते कि 80 परसेंट एकाउंट्स पहले खुले थे, तो अच्छा लगता। ठीक है, उस वक्त इस स्कीम का नाम "जन-धन योजना" नहीं था, स्कीम का नाम अलग था, लेकिन उस स्कीम का नाम बदल दिया गया। उस नई स्कीम में सवा 24 करोड़ में से आपने खोले सवा 7 करोड़, तो ¾ भाग हमारा और ¼ भाग आपका, लेकिन उस स्कीम का नाम बदल गया और उस स्कीम की वाह-वाह भी पूरे देश में हो रही है।

†**جناب غلام نبی آزاد:** منتری بھی نہیں ہے، کوئی سرکار میں نہیں ہے، پردھان منتری بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی 1977 میں آپ کی ہی پارٹی تھی۔ اس سے پہلے بھی دو پردھان منتری بن گئے، بلکہ تین پردھان منتری بن گئے۔ لال بہادر شاستری جی کانگریس کے تھے، لیکن دو غیر کانگریسی پردھان منتری بھی بن گئے۔ تو ایسا کہنے کے لیے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو دوش نہیں دیتا، یہ جو ڈر ان کے جیوت رہتے تھا، اب کچھ لیڈرس زندہ نہیں ہیں، لیکن اب ان کے بچوں سے بھی آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ وہ ڈر بنارہے۔

آپ نے جاتی واد کے بارےمیں کہا۔ میں کہتا ہوں کہ جاتی واد تو ایک بہت پرانی چیز تھی۔ آزادی سے پہلے تھی۔ آج تو دیش کا بٹوارہ ہوگیا ہے، محلے محلے، گھر گھر میں بٹوارہ ہوگیا ہے۔ آج کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ دھرموں کا بٹوارہ ہوا، جاتیوں کا بٹوارہ ہوا، ایک ایک دھرم کے کئی بٹوارے ہوئے۔ میں بعد میں جب ان باتوں پر آؤنگا، تب ان کا اُلّیکھ کرونگا۔

†Transliteration in Urdu script.

تُشٹی کرن کے بارے میں کہا گیا۔ آپ تُشٹی کرن کے سمبندھ میں جس طبقے کی بات کرتے تھے، آج دوسری طرح کا تُشٹی کرن ہے۔ آج پارٹی کا تُشٹی کرن ہے اور ایک ہی پارٹی چلا رہی ہے، اسی کی بات سنی جارہی ہے۔

نیچے بلاک سے لیکر، گرام سیوک سے لیکر صرف اسی پارٹی کے آدمی کو کام ملیگا، اسی کو روزگار بھی ملے، اسی کو ٹھیکا بھی ملے گا، اتنی بھینکر بات آج تک اتیہاس میں نہ سنی تھی، نہ پڑھی تھی۔

ماتیئے اُپ سبھاپتی جی، یہ سرکار ہر بات پر کہتی ہے کہ ہماری سرکار گیم چینجر ہے۔ یہ گیم چینجر نہیں ہے، یہ نیم چینجر ہے۔ جتنی بھی یوجنائیں ہیں۔ میرے پاس بہت بڑی سوچی ہے، لیکن میں 22-20 یوجناؤ کا ہی نام لونگا۔ جتنی بھی اسکیمس ہیں، جتنی بھی یوجنائیں ہیں، جو 1985 کے بعد کانگریس شاسن میں، یوپی اے کے شاسن میں بنی تھیں، ان کے نام بدل دیئے گئے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ گیم چینجر نہیں ہے، نیم چینجر ہے۔ اندرا آواس یوجنا، 1985 میں بنی تھی اور این ڈی اے کی سرکار آنے کے بعد یہ پردھان منتری آواس یوجنا بن گئی۔ راجیو آواس یوجنا 2009 میں Centrally-sponsored Scheme بنی تھی، اب یہ Sardar Patel National Urban Housing Mission بن گئی۔ میں آپتّی نہیں جتاتا ہوں کہ اس میں کس کا نام آگیا، میں خالی نام بدلنے کی بات کرتا ہوں۔ نرمل بھارت ابھیان اب سُوچھ بھارت ابھیان بن گیا ہے۔ راجیوگاندھی گرامین وِدُھوتی کر یوجنا کو اب دین دیال اپادھیائے گرام جیوتی یوجنا بنادیا ہے۔ Basic Savings Account، 2005 میں بن گیا تھا، اسے اب جن دھن یوجنا بنادیا گیا۔ National Project on Management

[श्री गुलाम नबी आजाद]

of Soil Health and Fertility یہ یوجنا 2008میں بنی تھی، اب یہ سوئل ہیلتھ کارڈ اسکیم بن گئی۔ Swavalamban Pension Scheme for Unorganized Sector, 2010میں بنی، اب یہ اٹل پینشن یوجنا بن گئی۔ ہم نے نیشنل اسکِل ڈیولپمنٹ مِشن 2010 میں بنایا تھا اب یہ اسکِل انڈیا بن گیا۔ JNNURM 2005 میں بنا تھا، جب میں اس کا منتری تھا، یہ اب AMRUT یوجنا بن گئی۔ Accelerated Irrigation Benefit Programme, 2007 میں بناتھا، یہ پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا بن گیا۔ ہم نے راشٹریہ کرشی وِکاس یوجنا 2007 میں بنائی تھی، اب یہ پرمپراگت کرشی وِکاس یوجنا بن گئی۔ National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) ہم نے 1985 میں بنائی تھی، اب یہ پردھان منتری فصل بیما یوجنا بن گئی۔ نیشنل مینوفیکچرنگ پالیسی، 2011 میں ہم نے بنائی، یہ میک اِن انڈیا بن گئی۔ National Maritime Development Scheme , 2005 میں بنی، اب یہ ساگرمالا بن گئی۔ ہم نے Fortified Urea Policy , 2005 میں بنائی، اب اس کا ہندی میں ترجمہ ہوگیا، تو نیم کوٹیڈ یوریا اسکیم بن گئی۔ جن اوشدھی اسکیم 2008 میں بنی تھی، تب بھی دوائیوں کی سیکڑوں، ہزاروں دکانیں کھلی تھیں، اب یکہ پردھان منتری جن اوشدھی یوجنا بن گئی۔ اب اس کا نام بدل گیا، تو یہ نئی یوجنا ہوگئی۔ جیسے بھارت کا نام اولڈ بھارت سے اب نیو بھارت ہوگیا ہے، یہ نیو انڈیا ہوگیا۔ آپ نے بھارت کو بھی نہیں چھوڑا۔ نیشنل گورنینس پلان 2006 میں بنا، تو اب یہ ڈجیٹل انڈیا بن گیا۔ Universal Immunization Programme 1985, میں بنا تو اندر دھنُش بن گیا۔ National

Optical Fibre Network, 2011 میں ہم نے بنایا، اب یہ بھارت نیٹ بن گیا۔ National Rural Livelihood Mission , 2005 میں بنا تھا، یہ دین دیال اپادھیائے گرامین اوشدھی یوجنا بن گئی۔ National Direct Benefit Transfer , 2013 میں بنا، اب یہ پہل بن گیا۔ National Girl Child Day Programme , 2008 میں بنا تھا، اب یہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ بن گیا۔ اندرا گاندھی ماترتو سہیوگ یوجنا 2010 میں بنی تھی، اب یہ پردھان منتری ماتر وندنا یوجنا بن گئی۔

یہ اتنی اسکیمس ہماری ہی ہیں، تو نئی اسکیمس کہاں ہیں؟ مانئے پردھان منتری جی کو یاد ہوگا، میں نے سال 2014 یا 2015 میں بتایا تھا کہ اگر پورے پانچ سال بھی آپ اور آپ کا منتری منڈل 24 گھنٹے ادگھاٹن کرتے رہیں، تو بھی یو۔پی۔اے۔ کی جتنی اسکیمس لاگو ہیں، ان کا ادگھاٹن بھاجپا کا پورا منتری منڈل نہیں کر پائے گا اور آج وہی ہو رہا ہے۔

یہاں بہت ساری چیزوں کی چرچا ہوئی۔ ہمیں پرائمری اسکول میں ٹیچر بہت ڈانٹتے تھے کہ گھر کے لئے دیا گیا کام کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو اور کام دے دو۔ یہ کہتے تھے ' آگے دوڑ، پیچھے چھوڑ، نہیں چلے گا۔ یہاں لوگوں سے 2014 میں بہت وعدے کئے گئے تھے۔ غریب کے اکاننٹ میں پندرہ لاکھ روپے جائیں گے، لیکن اس کا اُلیکھ نہ تو مہامہم راشٹرپتی جی کے بھاشن میں ہے اور نہ ہی بجٹ میں۔ اس دیش کے نوجوان، ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، جو آپ سے کام مانگتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ نے کم حاصل کی ہے، آپ نے ان سے دس کروڑ جوبس دینے کا، دو کروڑ سال

[श्री गुलाम नबी आजाद]

میں دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کا بھی مانئے راشٹر پتی جی کے بھاشن میں کوئی الّیکھ ہے اور نہ ہی بجٹ میں۔ اس دیش کے انّ-داتا کسانوں کے ساتھہ، جو خون پسینہ بہا کر اس دیش کو پالتے ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی لاگت پر 50 فیصد پروفٹ دیں گے۔ حالانکہ اب کچھہ نظر آتا ہے، لیکن وہ وعدہ بہت خطرناک ہے، میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ ایک اور بڑا وعدہ ڈیزل، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں کم کرنے کا کیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارے دونوں سدنوں کے وپکش کے نیتا اور آج کے ہوم منتری ڈھول اور تالیاں بجاکر پردرشن کرتے تھے اور بھارت بند ہوتا تھا جب سبزی، تیل، ڈیزل، گیس یا پیٹرول کی قیمتوں میں دس روپے بڑھتے تھے۔ جہاں ہمارے وقت میں گیس سلنڈر کا دام 350 روپے تھا، وہ آج 800 روپے میں ملتا ہے۔ آج سبزی، دالیں اور کسی بھی چیز کو ہاتھہ لگاؤ، تو وہ کوئی سو گنا مہنگی ہے۔ میں پیٹرول و ڈیزل کی قیمتوں کا ذکر کروں۔ جہاں ہمارے وقت میں 111 اور 120 ڈالر میں ایک بیرل تیل ملتا تھا ...(مداخلت)... میں سب سے کم قیمت کی بات کر رہا ہوں، تب آج جتنی قیمت میں ڈیزل، پیٹرول ملتا ہے، اس سے کم قیمت میں ہم لوگوں کو دیتے تھے۔ آج تو تیس ڈالر پرتی بیرل سے بھی نیچے کروڈ-آئل آ گیا ہے، لیکن آپ نے ساٹھہ سے ستر روپے پرتی لیٹر ڈیزل و پیٹرول پہنچا دیا ہے۔ آج آپ کو جو پیسہ ڈیزل، پیٹرول سے بچا، اگر ہمارے وقت میں ایسی قیمتیں ہوتیں، تو ہم نے بھارت میں ایک کرانتی اور انقلاب لایا ہوتا، لیکن آپ کے وقت میں ایسا کچھہ نہیں ہوا ہے۔ آپ تو ابھی بھی ہماری اسیکمس کے فیتے

کاٹتے ہیں اور ان کا نام بدل کر ٹیلی ویژن اور میڈیا میں چوبیس گھنٹے درشاتے ہیں۔ آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے۔

مانئے ڈپٹی چیئرمین سر، پریزیڈینٹ ایڈریس میں لکھا ہے، To make the country swachh by 2019. سر، جیسا میں نے کہا کہ ہم نے یہ "نرمل بھارت" کی شکل میں 2012 میں شروع کیا تھا۔ سن 2019 تک بارہ کروڑ ٹائلیٹ بنانے کا وعدہ ہوا ہے۔ ابھی صرف پچاس فیصد ہی ٹائلیٹ بنے ہیں۔ مجھے پچاس فیصد پر کوئی آپتّی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ابھی آدھے ٹائلیٹ ہی بنے ہیں۔ جب پونے چار سالوں میں آدھے ٹائلیٹ بنے ہیں، تو آگے نو یا دس مہینوں میں، الیکشن موڈ میں کچھ مہینوں کے بعد باقی کے آدھے ٹائلیٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ یو۔این۔ اسپیشل رپورٹ میں کہا ہے کہ out of the constructed toilets only 33% are sustainable and safe, the rest 67 per cent are not usable. ٹائلیٹ کے لئے پانی کی کوئی ویوستھا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہم سبھی لوگ ٹائلیٹس میں پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک پریوار کے دو چار لوگ ٹائلیٹ اور اس میں پانی نہ آئے، تو ہم اس کو یوز کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ ٹائلیٹ کسی دوسرے آدمی کے یوز کے قابل نہیں رہتا ہے۔ آپ اتنے لوگوں کے لئے جو ٹائلیٹس بناتے ہیں، اگر ان میں پانی کی ویوستھا نہ ہو، فلش کی ویوستھا نہ ہو، اس کے سیوریج کے ٹینک کی ویوستھا نہ ہو، تو آپ مجھ سے کہئے، تو میں بنا اس طرح کی سہولتوں کے ایک کروڑ ٹائلیٹ بنا کر دے دوں گا۔ آپ چار دیواری کرئے اور سیٹ رکھ دیجئے، تو ٹائلیٹ تیار ہو گیا۔ میں کانگریس پارٹی کو quote نہیں کر رہا ہوں، میں یو۔این۔ رپورٹ کو

[श्री गुलाम नबी आजाद]

quote کر رہا ہوں۔ ایک آرٹی۔آئی میں کہا گیا ہے کہ "سوچھہ بھارت" کے لئے ساڑھے پانچ سو کروڑ روپے تین سال میں صرف پبلسٹی کے لئے خرچ ہوئے ہیں، ساڑھے پانچ سو کروڑ روپے اس کی پبلسٹی پر خرچ ہوئے ہیں اور جو آدھے بنے ہیں، ان میں سے 67 فیصد usable نہیں ہے۔ جو ٹائلیٹ استعمال کے قابل نہیں ہے، یہ شاید ان کے لئے پبلسٹی ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک نیا نام دے کر ہمارے 'نرمل بھارت' ابھیان کا یہ حال کیا ہے۔

سر، مانئے راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں 'بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ' کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں اس کو بجٹ کی درشٹی سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک یہ 'بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ' 161 ڈسٹرکٹس میں تھا اور پچھلے سال میں اس کا بجٹ دوسو کروڑ تھا۔ اس سال سے اس کو 161 ڈسٹرکٹس سے بڑھا کر 640 ڈسٹرکٹس کیا ہے۔ That is four times districts بڑھا دئے ہیں۔ مجھے زیادہ mathematics نہیں آتا ہے، لیکن یہاں فائننس منسٹر بیٹھے ہیں، تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا بجٹ پچھلے سال دو سو کروڑ تھا، تو اس سال آٹھہ سو کروڑ ہونا چاہئے، لیکن بجٹ میں بڑھوتری کتنی ہے، صرف اسّی کروڑ۔ ہم نے بجٹ سے ہی اسکیم کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ہم نے ڈسٹرکٹس تو بڑھائے ہیں چار گنا، لیکن امائنٹ کچھہ کی اعشاریہ بڑھا دیا، تو یہ اسکیم تو at the outset شروع میں ہی ختم ہو گئی، لیکن آج یہ سب سے بڑا مدّعا ہے۔ مانئے پردھان منتری جی، بیٹی کو پڑھاؤ، تو بعد کی بات ہے، لیکن آج بیٹی بچاؤ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ صبح کا اخبار پڑھہ

نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ ہندی کا اخبار ہو یا انگریزی کا اخبار ہے۔ آپ ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 'بلاتکار' شبد ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ پورے دیش میں سب جگہ ہے۔

آپ ناراض ہو جائیں گے، اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ بی۔جے۔پی۔ رولنگ اسٹیٹس میں سب سے خطرناک ہے۔ ہریانہ تو گڑھ بن گیا ہے، مدھیہ پردیش اور یو۔پی۔اے۔ میں بھی حال برا ہے۔

اُپ سبھا پتی جی، ہم بلاتکار کے بارے میں ہمیشہ سنتے تھے کہ یہ بری بات ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ پانچ مہینے کی، تین مہینے کی، چار مہینے کی، آٹھ مہینے کی بچی کے ساتھ بلاتکار! جن وقت یہاں مانّنے راشٹرپتی جی بھاشن دے رہے تھے، دونوں سدنوں سے سمبودھت کر رہے تھے، اس دن بھی یہاں دہلی میں آٹھ مہینے کی بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا۔ ہر منٹ کے بعد بلاتکار ہو رہا ہے۔ اس کے لئے اس سرکار نے کیا کیا ہے؟ اس کے لئے کون سے قدم اٹھائے ہیں؟ ان معصوم بچیوں کے لئے، جو ابھی سال بھر کی بھی نہیں ہیں، ان کے لئے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ ہم یہ کون سے بھارت کا نرمان کر رہے ہیں؟ یہ کون سا نیا بھارت ہے؟ اس نئے بھارت کی ہم نے کلپنا نہیں کی تھی۔ مانّنے اپ سبھا پتی جی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ نیا بھارت لانے ہیں، کیوں کہ اگر یہ نیا بھارت ہے تو مجھے ایسے نئے بھارت پر افسوس ہے۔ ہمیں وہ پرانا بھارت دے دو، جو بھارت ہم نے چھوڑا تھا۔ ہمیں یہ بھارت نہیں چاہئے، جہاں ہماری بہو، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ میری بچی جاتی ہے، تو میں اپن سیکورٹی والے، کیوں کہ آپ کی سرکار نے سیکورٹی والے وڈرا کئے، اس لئے میں کہیں اپنے پروگرامس کینسل کرکے رات میں اس کو بھیجتا

[श्री गुलाम नबी आजाद]

ہوں۔ اتنا غیر محفوظ یہ دیش بن گیا ہے، یہ شہر بن گیا ہے، اس دیش کی راجدھانی بن گئی ہے۔

اپ سبھا پتی جی، ہمارے وقت میں بھی نربھیا کا ایک کیس ہوا تھا، لیکن ہم اتنے سینسٹو تھے کہ ہم فورا پارلیمنٹ میں ایک قانون لے کر آئے۔ ہم ایک کیس کے لئے اتنا بڑا، موٹا قانون لے کر آئے تھے، لیکن آج دن میں سیکڑوں، ہزاروں کیس ہوتے ہیں، پر اس سرکار کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، یہ سرکار ٹس سے مس نہیں ہوتی۔

اُپ سبھا پتی جی، یہاں 'جن-دھن یوجنا' کی بات کرتے ہیں۔ بھاجپا کا ہر نیتا، ہر منتری، 'جن-دھن یوجنا' کی بات کرتا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں راجنیتی میں تھوڑی سی ایمانداری کی ضرورت ہے۔ زیادہ تو نہیں، لیکن تھوڑی سی ایمانداری کی ضرورت ہے۔ راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں سرکار کی طرف سے 31 کروڑ بینک اکاؤنٹس کی بات کی گئی ہے، لیکن کتنا اچھا ہوتا، اگر آپ ایسا کہتے کہ 24 کروڑ، 30لاکھ اکاؤنٹس تب سے، یوپی۔اے۔ سرکار میں کھلے ہیں اور بی۔جے۔پی۔ کے وقت میں صرف سوا سات کروڑ اکاؤنٹس کھلے ہیں۔ آپ کے سوا سات کروڑ اکاؤنٹس کھولے اور ہم نے جو 24 کروڑ، 30 لاکھ اکاؤنٹس کھولے، ان کا نام ہی نہیں، جبکہ چوبیس گھنٹے 'جن-دھن یوجنا' سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے۔ اگر آپ اس کا بھی الیکھ کرتے کہ اسی فیصد اکاؤنٹس پہلے کھلے تھے، تو اچھا لگتا۔ ٹھیک ہے، اس وقت اس اسکیم کا نام 'جن-دھن یوجنا' نہیں تھا، اسکیم کا نام الگ تھا، لیکن اس اسکیم کا نام بدل دیا گیا۔ اس نئی اسکیم میں سوا چوبیس کروڑ میں سے آپ نے کھولے

سوا سات کروڑ، تو تین چوتھائی حصہ ہمارا اور ایک چوتھائی حصہ آپ کا، لیکن اس اسکیم کا نام بدل گیا اور اس اسکیم کی واہ-واہی بھی پورے دیش میں ہو رہی ہے۔

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): आपके आंकड़े ठीक नहीं हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: हमारे आंकड़े बहुत ठीक हैं, बस हमें रीपैकेजिंग नहीं आती है ...(**व्यवधान**)... हमें पैकेजिंग और रीपैकेजिंग नहीं आती है। ...(**व्यवधान**)... मैं इसी सदन में पहले भी कह चुका हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी को याद होगा या नहीं। तीन साल पहले मैंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर भी होती है, तो पैकेजिंग और रीपैकेजिंग के लिए जब ग्लोबल टेंडर्स होंगे, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टेंडर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पूरी दुनिया में जापान, अमरीका, चीन, रशिया, यूरोपीय देशों के पैकेजिंग के, रीपैकेजिंग के जितने ठेके दिए जाएंगे, वे आपको दिए जाएंगे, क्योंकि आपसे बड़ी रीपैकेजिंग किसी को आती नहीं है। हम तो बुद्धू हैं, हमें तो पैकेजिंग भी नहीं आती, रीपैकेजिंग क्या करेंगे? हम तो सिर्फ 24 घंटे बैठो, योजना बनाओ, करो, पहुंचा दो, उसकी पब्लिसिटी भी हमने कभी नहीं की। हम लोगों ने कभी इतनी स्कीमों की प्रेस-कॉफ्रेंस भी नहीं की। माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, यहां तो ऑर्डर बाद में होना है, प्रेस कॉफ्रेंस पहले हो जाती है। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام نبی آزاد:** ہمارے آنکڑے بہت ٹھیک ہیں، بس ہمیں ری-پیکجنگ نہیں آتی ہے...(مداخلت)... ہمیں پیکجنگ اور ری-پیکجنگ نہیں آتی ہے ...(مداخلت)... میں اسی سدن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مانّنے پردھان منتری جی کا یاد ہوگا یا نہیں۔ تین سال پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی ستّہ سے باہر بھی ہوتی ہے، تو پیکجنگ اور ری-پیکجنگ کے لئے جب گلوبل ٹینڈرس ہوں گے، تو پوری دنیا میں سب سے بڑا ٹینڈر بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملے گا۔ پوری دنیا سے جاپان، امریکہ، چین، رشیا، یوروپی دیشوں کے پیکجنگ کے، ری-پیکجنگ کے جتنے ٹھیکے دنے جائیں گے، وہ آپ کو دئے جائیں گے، کیوں کہ آپ سے بڑی ری-پیکجنگ کسی کو آتی نہیں ہے۔

ہم تو بدّھو ہیں، ہمیں تو پیکجنگ بھی نہیں آتی، ری-پیکجنگ کیا کریں گے؟ ہم تو صرف چوبیس گھنٹے بیٹھو، یوجنا بناؤ، کرو، پہنچا دو، اس کی پبلسٹی بھی ہم نے کبھی نہیں کی۔ ہم لوگوں نے کبھی اتنی اسکیموں کی پریس-کانفرنس بھی نہیں کی۔ مانّنے پردھان منتری جی بیٹھے ہیں، یہاں تو آرڈر بعد میں ہونا ہے، پریس کانفرنس پہلے ہو جاتی ہے ....(مداخلت)....

†Transliteration in Urdu script.

श्री विजय गोयलः आपकी जो योजनाएं रही हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ादः आप तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स देखते हैं, मैंने कई दफा कहा है कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स के बारे में अपने लीडर से कुछ सुनिए, लीडर ऑफ द हाउस से कुछ सीखिए। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर का, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने ओथ के बाद जो पहला टेलीफोन मुझे किया, उसमें कहा कि मैं मदन लाल खुराना को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसको ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि मेरे हिसाब से हम हमेशा गौरव मानते थे कि तुम ऑपोजिशन के पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर रहे, चूंकि मैं पांच साल पार्लियामेंटरी अफेयर्स में 1991 से 1996 तक रहा और वे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा समझता था कि तुम हमें रिप्रजेंट करते हो, सरकार को नहीं, आप जरा, इनको समझाओ। मैंने पहला लेक्चर उन्हें दिया था और आपके साथ भी एक घंटा जरूर बैठूंगा। आप कुछ नहीं सीखे, तो अपने लीडर से सीख लो। Parliamentary Affairs Minister is not supposed to interrupt.

†**جناب غلام نبی آزاد :** آپ تو پارلیمنٹری افینرس دیکھتے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پارلیمنٹری افینرس کے بارے میں اپنے لیڈر سے کچھ سنئے، لیڈر آف دی ہاؤس سے کچھ سیکھئے۔ پارلیمنٹری افینرس منسٹر کا، جب اٹل جی پرائم منسٹر بنے تھے، تو انہوں نے اوتھ کے بعد جو پہلا ٹیلی فون مجھے کیا، اس میں کہا کہ میں مدن لان کھورانہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کو ٹریننگ دے دو، کیوں کہ میرے حساب سے ہم ہمیشہ گورو مانتے تھے کہ تم اپوزیشن کے پارلیمنٹری افینرس منسٹر رہے، چونکہ میں پانچ سال پارلیمنٹری افینرس سے 1991 سے 1996 تک رہا اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ تم ہمیں رپریزینٹ کرتے ہو، سرکار کو نہیں، آپ ذرا، ان کو سمجھاؤ۔ میں نے پہلا لیکچر انہیں دیا تھا اور آپ کے ساتھ بھی ایک گھنٹہ ضرور بیٹھوں گا۔ آپ کچھ نہیں سیکھے، تو اپنے لیڈر سے سیکھ لو۔ Parliamentary Affairs Minister is not supposed to interrupt.

MR. CHAIRMAN: Why don't you teach him now?

श्री गुलाम नबी आज़ादः सर, इसीलिए अब इस योजना पर कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्रा योजना के बारे में भी बहुत बातें कही गई हैं। यह 1990 की स्कीम थी, जो बाद में मुद्रा योजना हो गई। इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन मुद्रा योजना में इनको जो मैक्सिमम पैसे मिल सकते हैं, वह 43,000/- रुपए मिल सकते हैं। ऐसा कौन सा व्यापार है, जो 43,000/- रुपए में हो सकता है? देश का कोई भी आदमी 43,000/- रुपए में छोटे से छोटा बिजनेस नहीं कर सकता है। ...(**व्यवधान**)... उसके लिए भी 43,000/- रुपए में शायद आटा आएगा, दूसरा सामान आएगा, लेकिन जगह नहीं आएगी। अब हम उतने खुशकिस्मत तो नहीं हैं, बीजेपी के पास एक स्कीम थी, जहां 50,000 से कुछ 80 करोड़ बन सकते हैं, लेकिन वे हमसे शेयर नहीं करते। वे हमसे शेयर करते, तो देश कितना

†Transliteration in Urdu script.

सुखी हो जाता। हमारा भी इस 43,000 में काम होता, लेकिन जो उन्होंने अपनी पार्टी तक ही सीमित रखा है, उसमें मैं विनती करता हूँ कि उसको सदन के साथ शेयर करें। हम भी अपनी पार्टी में उसका उपयोग करें, तो शायद हमारा भी कुछ उत्थान हो। देश के करोड़ों लोगों के साथ भी शेयर करें, दस करोड़ बच्चों के साथ, जिनके साथ वायदा किया है उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी उत्थान हो।

सर, फॉर्मर्स के बारे में प्रेसिडेंट साहब के एड्रेस में लिखा गया है - The highest priority will be given to remove various difficulties faced by farmers and Government is committed to doubling the farmers' income by 2022. सबसे पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि इतने सालों से जब भी बजट बनाते आए हैं, तो 2010, 2011, 2012, 2013 रहता था, मगर यह पहली बार है कि बजट में हर स्कीम में 2022, तो क्या यह चार साल का बजट कैसे बन रहा है? मैं यह माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बता रहा हूँ कि इसमें 2022 तक का उल्लेख है। माननीय प्रधान मंत्री जी तो चार साल से कई चीज़ों को 2022, 2024 बता रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि इतने सालों से, अब हमें भी इस सदन में एकाध साल में 40 साल होने वाले हैं, हम सुनते आए हैं 2010, 2011, 2012, 2013, लेकिन पिछले एकाध साल से देख रहे हैं कि जो भी स्कीम बनी है, जिसको टालना हो, जिसका इलेक्शन से पहले जवाब न देना हो, उसको कहो 2022, फिर 2022 में देखेंगे, तब तक लोग भूल जाएंगे। इसी तरह से आपने farmers के साथ भी 2014 में जो वादा किया था कि लागत plus 50 per cent profit, वह तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन अभी 2022 तक दूसरा लॉलीपॉप दे दिया। अभी पहला लॉलीपॉप तो मिला नहीं, दूसरा लॉलीपॉप दे दिया कि आपकी income दोगुनी हो जाएगी। अब मैं तो किसान हूँ हमारे घर में भी जमीन, माल-मवेशी हैं, लेकिन जो सब लोग बताते हैं, जो इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, वे यह कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको Additional Secretary, Agriculture, श्री अशोक दलवई की recommendation के बारे में बताना चाहूंगा। जाहिर है सरकार ने कमिटी बनाई थी कि farmers की income 2022 तक दोगुनी होनी चाहिए। उसकी recommendation है कि ₹ 6.4 lakh crore investment is needed for that. ₹ 6.4 lakh crore! और agriculture की आपकी जो growth होनी चाहिए, वह 10 परसेंट से 12 परसेंट होनी चाहिए, then only can you think of it. आपकी growth 12 per cent हो, आप उस पर 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करें, तब यह सपना साकार होगा, लेकिन आपका जो रिकार्ड है, 4 सालों में आपकी जो average agricultural growth है, वह 1.9 परसेंट है। यह एक दफा एक साल ऊपर चला गया था, लेकिन आपकी average agricultural growth 1.9 परसेंट है। इस सदी में 2021 के आखिर तक यह growth 12 परसेंट होनी नहीं है, आप 50 साल हुकूमत करेंगे, तो भी आपने 6 लाख करोड़ रुपए देने नहीं है, तो उनकी income double नहीं होनी है। लिहाजा यह बहुत simple method है। आप क्यों ऐसे वादे करते हैं, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है और जिनके लिए आपको पछताना भी पड़ता है? इस साल के agriculture budget में यह कितना बढ़ा है, 4,845 करोड़। अगर आपको इसे आने वाले 4 सालों में achieve करना था, तो इसके लिए इस दफा आपको सवा लाख करोड़ रुपए extra देने चाहिए थे, न कि साढ़े चार हजार करोड़। एक दफा फिर, अब मुझे यह कहना बहुत बुरा लगता है कि 'झूठा वादा', लेकिन आप किसानों के साथ सच्चा वादा नहीं कर रहे हैं, जो रोज मरते हैं, जो रोज आत्मदाह करते हैं, जो रोज खुदकुशी करते हैं। उनकी खुदकुशी पर मरहम लगाने के बजाय आप उनसे गलत वादा करते हैं, जो वादा आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस पर मुझे घोर आपत्ति है।

[श्री गुलाम नबी आजाद]

माननीय President's Address में आपने लिखा है, "To ensure availability of two-square meals to every person, effective enforcement of National Food Security Act is necessary." शुक्र है कि अभी आप Food Security Act का नाम बदलना भूल गए हैं, शायद एकाध साल में यह बदल जाएगा, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा है। The Supreme Court in July, 2017 has said that the National Food Security Act, 2013 has not been implemented properly and it is a pity that legislation enacted by Parliament for citizen's benefit was kept on the backburner by various States. यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम दो वक्त का खाना ensure करेंगे। यूपीए गवर्नमेंट थी और मैं यूपीए गवर्नमेंट के पीछे सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह उनका brainchild था कि food security होनी चाहिए। देश में जो गरीब है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो कमा नहीं सकते, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए दो रुपए/3 रुपए फी किलो अनाज होना चाहिए। यह यूपीए की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और सुप्रीम कोर्ट आपको कहता है कि आप इसको ठीक तरह से लागू नहीं करते हैं।

आगे है, 'National Health Policy'. चार दिन टेलिविज़न पर 'National Health Policy' के बारे में डिस्कशन चला। इस दफा टेलिविज़न पर अगर किसी चीज़ पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है, तो हेल्थ पर हुआ है। लेकिन बाद में बेचारे किसान जाग गए कि यह तो ऐसे ही था, जैसे 10 करोड़ नौजवानों को बाद में पता चला था कि यह तो जुमला ही था, उसी तरह से बेचारे हेल्थ वाले भी परेशान हैं कि हमको कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं है। मैं पांच साल इस मिनिस्ट्री में रहा और उस दौरान अमरीका के हेल्थ मिनिस्टर के साथ कई मीटिंग्स हुईं। प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने चंद देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स को बुलाया था, हमें भी बुलाया कि इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताइए। दोनों देशों ने कहा कि इस इंश्योरेंस स्कीम ने हमको लूट लिया और खा लिया। इन इंश्योरेंस कंपनियों ने तो पैसा बना लिया, लेकिन इससे लोगों का कुछ नहीं बना। प्लानिंग कमीशन में जब चर्चा हुई थी, तो मैं इतनी ढेर सारी किताबें लेकर गया था। आज मेरे पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उस वक्त मिनिस्ट्री ने बहुत सारी किताबें दी थीं। मिनिस्ट्री भी अच्छी चीज़ है, ना कहोगे तब भी किताबें लाएगी और हां कहोगे तब भी किताबें लाएगी। उस वक्त उन्होंने यह केस लड़ने के लिए मुझे इतनी सारी किताबें दी थीं, जिसमें अमरीका, ब्रिटेन और कई कंट्रीज़ का उल्लेख था कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होता है, लोगों को या पेशेंट्स को कोई फायदा नहीं होता है। यह तो मैं अमीर देशों की बात कर रहा हूं, जिनके यहां जीडीपी का 10-15 प्रतिशत या 17 प्रतिशत खर्च होता है। हम तो अभी 1.5 प्रतिशत से ही जूझ रहे हैं, तो हमारा इंश्योरेंस कितना होगा और फायदा कितना होगा?

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह स्कीम

उठेगी ही नहीं। आपकी पहले एक इंश्योरेंस स्कीम थी, लेकिन 2015-16 में आपने एक रुपया भी उस पर खर्च नहीं किया। आपने 2016-17 में 1500 करोड़ रुपया इस स्कीम में रखा था, लेकिन सिर्फ 724 करोड़ रुपया ही खर्च किया, यानी आधे से भी कम पैसा इस पर खर्च किया गया और 776 करोड़ रुपया unspent रह गया। आपने इस स्कीम के लिए 2017-18 में 100 करोड़ रुपए रखे, लेकिन सिर्फ 471 करोड़ रुपये ही खर्च किए, यानी सिर्फ 35 प्रतिशत ही खर्च किए। आप दो-तीन साल से इस स्कीम के लिए जो पैसा दे रहे हैं, वह आधा भी खर्च नहीं हो रहा, सिर्फ 40-45 प्रतिशत खर्च हो रहा है। अब आप पूरे देश के लिए 2000 करोड़ रुपए की स्कीम बना रहे हैं, यह 2000 करोड़ रुपये की स्कीम शुरू कब होगी? यह कामयाब नहीं होनी है। इसके बजाय, हमने इस संबंध में जो कदम उठाए थे, आप सरकारी अस्पतालों को आगे बढ़ाइए। प्राइवेट अस्पताल के लिए आप जो पांच लाख देंगे, आप मुझे बताइए, दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप डॉक्टर्स को दिखाइए, तो शाम को पांच लाख का बिल आ जाएगा, इसलिए हम यह सोचते थे कि सरकारी अस्पतालों में इलाज होना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा हम इंश्योरेंस स्कीम पर लगाएंगे, अगर हम अपना ही सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर मज़बूत करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, रीजनल हेडक्वार्टर पर लगाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने अपने बजट में 24 मेडिकल कॉलेज रखे हैं, लेकिन हमने 58 मेडिकल कॉलेज दिए थे। शायद हिस्ट्री में पहली दफा हमारे वक्त में हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू किए। सबसे पहले तो उन 58 मेडिकल कॉलेजों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। 40 मेडिकल कॉलेजों को upgrade करके AIIMS like institutions बनाने के लिए पैसा रिलीज़ हुआ, sanction किया गया, उनको बना देना चाहिए। सर, हमने नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स लगभग 40 से 50 हजार तक बनाए थे और उतने का ही एक्सपेंशन हो रहा था, उन्हें बनाना चाहिए था। मेरे ख्याल से, मैं अभी भी कहता हूं, चाहे वे हमारे वक्त में सेंक्शन हुए, हमने पहली दफा 71 कैंसर इंस्टीट्यूट्स दिए और एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, झज्जर में दिया, जिसका शायद दो-चार महीनों बाद माननीय प्रधान मंत्री जी उद्घाटन करेंगे। 2,500 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है। माननीय डा. मनमोहन सिंह जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था और शायद वह एशिया का सब से आधुनिक और सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट होगा। उसके अलावा देश में कई कैंसर इंस्टीट्यूट्स स्टेट हैडक्वार्टर्स और रीजनल हैडक्वार्टर्स पर बन रहे हैं। उन्हें तुरंत वार-फुटिंग पर बनाने की जरूरत है, बजाय इसके कि बीमा कंपनियों के माध्यम से इलाज कराया जाए। इससे बीमा कंपनियां पैसा बनाएंगी और पेशेंट्स का कोई फायदा नहीं होगा।

उपसभापति महोदय, दो-तीन स्कीमें और हैं। start up, stand up और skill India. स्टार्ट अप अभी शुरू हुई है, लेकिन मंजिल पर अभी एक भी नहीं पहुंची है। स्टेंड अप, ये खड़ी तो हुई हैं, लेकिन बैठने के काबिल नहीं हैं। स्किल इंडिया तो असफल हुई, लेकिन kill India जरूर हुआ। ये तमाम शब्द टेलिविज़न, मीडिया, प्रिंट मीडिया, लिखने और छापने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें दम कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्टंट है।

[श्री गुलाम नबी आजाद]

उपसभापति जी, आज पेपर में निकला है कि केवल 5 परसेंट ग्रामीण बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। जहां पांच परसेंट वोकेशनल ट्रेनिंग रूरल यूथ ले रहा है, तो कहां है आपका स्किल इंडिया?

उपसभापति जी, अब मैं employment generation पर आता हूं। आपने देश के 10 करोड़ बच्चों के साथ वादा किया था कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वह तो हुआ नहीं। वर्ष 2015 में employment generation पहले पांच सालों में सबसे कम थी। वर्ष 2016 में सात सालों का रिकॉर्ड, unemployment में beat किया। वर्ष 2017 में आपने पिछले employment generation का रिकॉर्ड बीट किया, कोई employment ही नहीं दी। इस प्रकार से देखा जाए, तो आप वर्ष 2015, 2016 और वर्ष 2017 में unemployment generation का record आप beat कर रहे हैं।

उपसभापति जी, अब मैं कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं। Terrorist violence in the interiors of Jammu and Kashmir was directly related to the cross-border infiltration. With better coordination, the Army, paramilitary forces and Jammu and Kashmir Police are giving a befitting response to the perpetrators. यह एक ऐसा इश्यू है, जिसमें पूरा भारत आपके साथ रहा। पूरा भारत आपके साथ रहा, पूरी पार्टियां आपके साथ थीं, पूरा विपक्ष आपके साथ था और आपकी सरकार बनने के लिए 50 परसेंट रोल सुरक्षा का भी है, क्योंकि आपके, यानी माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं, देश में 600-700 मीटिंग्स कीं, सभी में आपने उस वक्त के प्रधान मंत्री, उस वक्त के कांग्रेस के मंत्री, उस वक्त के विदेश मंत्री, उस वक्त के रक्षा मंत्री की आलोचना की और उनके खिलाफ बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तब आपने कहा था कि निकम्मी सरकार है, कमजोर सरकार है और आपने यहां तक कहा कि मरो-मरो और डूब मरो, लेकिन हमने ज़ुबान नहीं खोली। आपने यह कहा था कि कमज़ोर सरकार है, आँख से आँख नहीं मिलाती। यह कहा था कि इनके मंत्री बिरयानी खाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। यह कहते हैं कि कोई फॉरेन मिनिस्टर चाइना में ही रहना चाहता है, लेकिन वहाँ बात नहीं कर पाया। आपने कहा कि हमारे एक फौजी की गर्दन काट कर पाकिस्तानी ले गये और ये देखते रहे। माननीय प्रधान मंत्री जी, दो मिनट के लिए मान लिया कि हम कमज़ोर थे, लेकिन आज जम्मू-कश्मीर में जो हालात हैं, उस वक्त के हिसाब से हम कहते हैं कि हम महान हैं और आपकी सरकार सबसे कमज़ोर है, 70 सालों में सबसे कमज़ोर है। 70 सालों में सबसे ज्यादा अगर सीज़फायर वायलेशंस हुए हैं, किसी तीन साल के अरसे में, तो वह आपके वक्त में हुए हैं। चाहे वह इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो, जम्मू, सांबा, कठवा में हो या राजौरी-पुंछ के एलओसी पर हो, सबसे ज्यादा सीज़फायर वायलेशंस हुए हैं। इतने छोटे से समय में वार को छोड़ कर, लड़ाई को छोड़ कर, सबसे ज्यादा फौजी अगर मरे हैं, बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्सेज़ के लोग सबसे ज्यादा मरे हैं, वह इस वक्त मरे हैं। युद्ध के मैदान में छोड़िए, सबसे ज्यादा अगर सिविलियंस मरे हैं, तो इन तीन सालों में मरे हैं, चाहे वह कश्मीर हो या जम्मू हो। चार ही कल मरे, अभी परसों ही कुछ और मरे थे। मेजर मरते हैं, कैप्टन मरते हैं, कर्नल मरते हैं। मान लीजिए, यह सरकार भूल गई।

अभी मैं और अम्बिका सोनी जी जम्मू के कुछ इलाकों में होकर आये। उन लोगों की हालत देखी नहीं जाती। पाकिस्तान की शेलिंग से दो दिन के अंदर हमारे 8 सिविलियंस मारे गये, हमारे पाँच फौजी मारे गये। सैकड़ों घर बर्बाद हुए, हजारों जानवर, भैंसें, गायें, बकरियां बर्बाद हुए। आपके लोगों को, बीजेपी के लोगों को बॉर्डर पर नहीं जाने देते हैं। आपको इत्तिला है या नहीं? वे उनको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि आपने तो उस वक्त विपक्ष के खिलाफ हमारे जज्बात उभारे थे, लेकिन जितना हम पिटे हैं, 70 सालों में कभी किसी भी सरकार के समय में नहीं पिटे हैं। आज जम्मू बॉर्डर पर, अखनूर से लेकर सांबा और कठवा के बॉर्डर तक तथा राजौरी से पुंछ तक जो हालत है, वह कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वह तीन साल से सो नहीं रहा है। कितनी दफा उनको घरों से पलायन करना पड़ता है। हमारे वक्त में कहीं 10 साल में या 15 साल में अगर होता भी है तो एकाध गाँव होता, अभी 15-20 दिन पहले तकरीबन 75,000 लोगों ने बॉर्डर से पलायन किया। उनके लिए, सुरक्षा के लिए जगह नहीं है। उनके खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। वे बेचारे दर-बदर स्कूलों में फिर रहे हैं। उनके पास मवेशी नहीं हैं, घर नहीं है, अनाज नहीं है। हम कब से माँग कर रहे हैं कि उनके लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए। मैं जब मुख्यमंत्री था, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर ही अनाउंस किया था कि हम जम्मू में, सांबा में सुरक्षित जगह पर पाँच मरला जमीन देंगे। मेरे समय में, थाड़ी सी जमीन हमने acquire की थी। इससे पहले कि मैं अपना काम पूरा करता, आपके सहयोगियों ने, जो आज आपके सहयोगी हैं, उन्होंने सपोर्ट विद्ड्रॉ कर ली। ...(**व्यवधान**)... इसलिए की थी कि आप तो बड़े धर्म को मानने वाले हैं। उस तीर्थ स्थान के लिए मैंने जमीन दी थी, इसलिए आपके पार्टनर ने ...(**व्यवधान**)... मैंने अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन दी थी, इसलिए सपोर्ट विद्ड्रॉ हो गयी थी। अब आपकी भी जल्द ही हो जायेगी, आप फिक्र मत करिए। चूहा-बिल्ली का खेल तो वहाँ रोज चल रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू में बॉर्डर पर लोग बहुत तंग हैं, मायूस हैं। वहाँ आज भयंकर हालत है। कश्मीर में तो जितनी गरीबी और जहालत आप डाल सकते थे, ला सकते थे – उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। कभी hot pursuit की बात करते हैं, तो कभी कोई और बात करते हैं। कभी कुछेक लोगों को एनआईए तक अन्दर ठोकते हैं, तो कभी उनके पीछे फिर यहाँ से interlocutor भेजते हैं, बात करने के लिए, ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, hot pursuit तो hot pursuit या बातचीत तो बातचीत। जब हमने शुरू में कहा कि बातचीत कीजिए, तो आपने कहा कि ये तो पाकिस्तानी हैं, मेरे कहने का मतलब गुलाम नबी आज़ाद नहीं, बल्कि जब अपोजिशन वाले कहते थे कि इनको बड़ी सहानुभूति है, इनको बड़ी हमदर्दी है, इनको पाकिस्तान के साथ बड़ा प्यार है और यह जो हुर्रियत वाले हैं, ये बातचीत की बात करते हैं, आप जो मरज़ी, वह करो। अब आप चार साल न बात कर रहे हैं, न आपका hot pursuit चल रहा है, कुछ भी नहीं चलता है और इस बीच में जम्मू-कश्मीर के लोग तबाह और बर्बाद हो गए, यह मैं सदन में आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने कहा, 'Due to successful diplomatic efforts' उस पर हमारे दूसरे साथी, आनन्द शर्मा जी बोलेंगे, लेकिन क्या हुआ? आप अज़हर मसूद का कुछ कर नहीं पाए, चीन ने आपको करने नहीं दिया। Membership

[श्री गुलाम नबी आजाद]

of Nuclear Suppliers Group के संबंध में भी आप कुछ नहीं कर पाए, चीन ने आपको करने ही नहीं दिया। चीन आपको UN Security Council का मेम्बर बनने नहीं देता है, तो आपकी क्या कूटनीति है, कौन-सी कूटनीति है?

महोदय, मैं आखिर में ट्रिपल तलाक पर आना चाहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ट्रिपल तलाक के बारे में कहा गया है। यह माना कि बीजेपी की सरकार ने पहले अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टियों को बांटा, उनको डिवाइड किया। किसी को ईडी से डरा कर, किसी को इनकम टैक्स से डरा कर, किसी को एनआईए से डरा कर बांटा, क्योंकि आज राजनीति ज्यादा हो रही है, आज डराओ वाली राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है। फिक्स करने वाली राजनीति ज्यादा हो रही है। हमने यह राजनीति कभी नहीं देखी। हमारे वक्त में, जब हम राजनीति में छोटे ही थे, तब कहते थे कि यह बीजेपी का financer है, इसको मत छेड़ना। आज तो ढूंढ़ कर कहता कि तुम कहो कि तुम कांग्रेस के हो, तुम समाजवादी के हो, तुम बीएसपी के हो, तुम ममता के हो, तुम उसके समर्थक हो, ताकि तुमको अंदर डालेंगे। कहने का मतलब यह है कि बात भी नहीं करनी है। माननीय प्रधान मंत्री जी, आप समझ नहीं सकते, इतना डर, इतना भय, इतना खौफ है देश में, सत्ता में रह कर ये चीजें नहीं दिखती हैं। यह भय ठीक नहीं है। अगर अफसर काम न करे, तो उसको भय हो, यह बहुत अच्छी बात है। अगर कोई करप्शन करते हुए पकड़ा जाए, तो उसके लिए ऐसा हो। हमने भी इसके लिए सख्त कानून बनाया, शायद दुनिया का पहला कानून हमने जम्मू-कश्मीर में बनाया कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए। उससे डर है, लेकिन यह कि किसी अपोजिशन वाले के घर जाऊं, उससे बात करूं, उससे टेलीफोन पर बात करूं... तो मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तिजारत नहीं कर सकता, institution नहीं चला सकता, माननीय प्रधान मंत्री जी, यह भय देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। Freedom of Speech, freedom of socializing, freedom of business, ये सब तो होने चाहिए। आज हमारे फोन पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि वह फोन टैप हो जाएगा। हमने तो कभी नहीं यह किया। हमने कोई टैप नहीं किया। हमने यह सुना भी नंहीं कि किसी का फोन टैप किया जाए। आज तक तो हमने यह सुना था कि किसी आतंकवादियों का फोन टैप होता है। जब मैं पिछली बार चीफ मिनिस्टर बना, तो हम आतंकवादियों के फोन टैप करते थे, लेकिन लीडरों के फोन टैप नहीं होते थे। कश्मीर जैसे sensitive area में मैं वहां तीन साल रहा, उस दरम्यान किसी ने हमसे यह पूछने की जुर्रत नहीं की कि हम किसी लीडर का फोन टैप करें या करना चाहते हैं, चाहे वह विपक्ष का लीडर हो या कोई और हो या उसके लिंक्स कुछ भी हों except for terrorism. आज तो आपने हमें terrorist बना दिया, international terrorist बना दिया। आपने अपोजिशन को ही terrorist बना दिया। इस तरह के भय, डर और खौफ की बदौलत जीतना हुआ, तो यह क्या जीतना हुआ?

मैंने गुजरात में ही देखा, मैंने अपने भाषण की ज्यादा publicity नहीं ली, लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि यहां कहा जाता है कि एक हजार लोग यहां हैं, इनमें से सात सौ हमारे हैं यानी बीजेपी के हैं और अगर सात सौ से ऊपर वोट आ गए, तो आपने वोट दिया और अगर सात सौ ही रहे, तो इसका

मतलब है कि सिर्फ बीजेपी वाले ने वोट दिया है, आपने नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारी खैर नहीं। यह कौन-सा वोट मांगने का, वोट garner करने का तरीका है, कि आप डराकर, धमकाकर वोट ले लो। डरा-धमकाकर तो हम भी हिन्दुस्तान में 70 साल या उससे आगे, 200 साल तक हुकूमत कर सकते थे। मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसी राजनीति मत करिए। ...(**व्यवधान**)... उस पर आप बहुत रोटियां सेक चुके हैं, दस दफा कह चुके हैं। ...(**व्यवधान**)... ऐसी चीजों की वजह से ही आपकी पहचान हुई, वरना आपको पहचानता ही कौन था? ...(**व्यवधान**)...

महोदय, ट्रिपल तलाक का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक के दो भाग हैं। लॉ मिनिस्टर साहब को मैंने समझाया था कि ट्रिपल तलाक के दो भाग हैं - एक अच्छी भावना से तलाक और दूसरा कम्युनिटी को साफ करने की भावना से तलाक। अच्छी भावना है - Instant Triple Talaq - तलाक, तलाक, तलाक - चाहे आप तलाक-ए-बिद्दत टेलीफोन पर करें, एस.एम.एस. से करें या जुबानी करें - उसके हम खिलाफ हैं, लेकिन उसका दूसरा पार्ट बहुत खतरनाक है - जो आप illegally करते हो, उसे legal बनाकर करना चाहते हो। वह है कि इसे आप Criminal Act में लाकर पति को जेल में डाल दो। जब तक पति वापस आए, उसकी पत्नी कहां रहेगी, उसके बच्चे कहां रहेंगे, वे खाएंगे कहां से, कहां से पाएंगे? पहले आपने शिया-सुन्नी को बांटा और अब पति-पत्नी को बांट रहे हैं। किसी को तो छोड़ दीजिए, कोई घर तो आप छोड़ दीजिए। पहले polarization करके मुझे और आनन्द शर्मा जी को बांट दिया। ...(**व्यवधान**)... मैं यहां धर्म की बात कहता हूं। फिर मुझे और अग्रवाल को बांट दिया। मुझे अपने आपको ही बांट दिया, polarization के ज़रिए दो धर्मों का बंटवारा। Castesism तो पहले से ही था, लेकिन दो धर्मों का बंटवारा इस सरकार में हुआ। फिर शिया-सुन्नी का बंटवारा किया और कहा कि शिया हमारे और सुन्नी दूसरी पार्टियों के। अब सुन्नियों में भी जो मर्द और औरत थे, उनका भी बंटवारा कर दिया - मर्द को जेल में डालो और औरत से कह दिया कि तुम्हारी समस्या का हमने समाधान कर दिया। ...(**व्यवधान**)... यह कौन-सा बंटवारा है? क्यों आप तोड़ रहे हैं? यह minority community पहले ही टूटी है, गरीब है, उनमें डर है, भय है, Lynching से डरी हुई है, ट्रेन से डरती है, कार में घूमने से डरती है। अगर किसी बैंक में एप्लीकेशन देती है तो बैंक लोन उसे मिलता नहीं। पति के साथ रह रही है, उसे भी आप नहीं रहने देंगे, पति को जेल में डालकर, तुम हमें वोट दे दो। खुदा के लिए कोई घर तो छोड़ो, कहीं तो हमें अपना भारत लौटा दो। जो new भारत आपने आज बनाया है, हमें वह new भारत नहीं चाहिए। हमें old भारत चाहिए, हमें गांधी का भारत चाहिए, जहां हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई, वैसे सिख और ईसाई में तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन जहां हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के लिए खून देते थे, वह पुराना भारत था, जिसे आप वोट के लिए, सरकार के लिए polarize कर दिया और बराबर निरंतर करते जा रहे हैं, वह भारत हमें लौटा दो। हमें वह भारत लौटा दो, जिसमें डर नहीं हो, बांट नहीं हो। हमें वह भारत लौटा दो जिसमें दो महीने, तीन महीने या चार महीने की बच्ची के साथ बलात्कार न होता हो। उस भारत की हमें जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो यहां धन्यवाद-प्रस्ताव माननीय अमित शाह जी ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं, जय हिन्द!

[श्री गुलाम नबी आजाद]

†**جناب غلام نبی آزاد** : سر، اسی لئے اب اس یوجنا پر کچھہ زیادہ نہیں کہوں گا، کیوں کہ بہت سارے مدّعے ہیں۔ مدرا یوجنا کے بارے میں بھی بہت باتیں کہیں گئی ہیں۔ یہ 1990 کی اسکیم تھی، جو بعد میں مدرا یوجنا ہو گئی۔ اس کے بارے میں بہت چرچا ہوتی ہے، لیکن مدرا یوجنا میں ان کو جو زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، وہ /-43،000 روپے مل سکتے ہیں۔ ایسا کونسا ویاپار ہے، جو /-43،000 میں ہو سکتا ہے؟ دیش کا کوئی بھی آدمی /-43،000 روپے میں چھوٹے سے چھوٹا بزنس نہیں کر سکتا ہے ...(مداخلت)... اس کے لئے بھی /-43،000 روپے میں شاید آٹا آئے گا، دوسرا سامان آئے گا، لیکن جگہ نہیں آئے گی۔ اب ہم اتنے خوش قسمت تو نہیں ہیں، بی‌جے‌پی۔ کے پاس ایک اسکیم تھی، جہاں 50،000 ہزار میں کچھہ اسی کروڑ بن سکتے ہیں، لیکن وہ ہم سے شیئر نہیں کرتے۔ وہ ہم سے شیئر کرتے، تو دیش کتنا سکھی ہو جاتا۔ ہماری بھی اس /-43،000 میں کام ہوتا، لیکن جو انہوں نے اپنی پارٹی تک ہی محدود رکھا ہے، اس میں میں ونتی کرتا ہوں کہ اس کو سدن کے ساتھہ شیئر کریں۔ ہم بھی اپنی پارٹی میں اس کا اپیوگ کریں، تو شاید ہمارا بھی کچھہ اتّھان ہو۔ دیش کے کروڑوں لوگوں کے ساتھہ بھی شیئر کریں، دس کروڑ بچوں کے ساتھہ، جن کے ساتھہ وعدہ کیا ہے ان کے ساتھہ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کا بھی اتّھان ہو۔

سر، فارمرس کے بارے میں پریزیڈینٹ صاحب کے ایڈریس میں لکھا گیا ہے The highest priority will be given to remove various difficulties faced by farmers and Government is committed to doubling the farmers' income by 2022. سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھہ میں نہیں آتا ہے کہ اتنے سالوں سے جب بھی ہم بجٹ

†Transliteration in Urdu script.

بناتے آئے ہیں، تو 2010، 2011، 2012، 2013 رہتا تھا، مگر یہ پہلی بار ہے کہ بجٹ میں ہر اسکیم میں 2022، تو کیا یہ چار سال کا بجٹ کیسے بن رہا ہے؟ میں مانتے فائنینس منسٹر صاحب کو بتا رہا ہوں کہ اس میں 2022 تک کا لیکھہ ہے۔ مانتے پردھان منتری جی تو چار سال سے کئی چیزوں کو 2022، 2024 بتا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے سالوں سے، اب ہمیں بھی اس سدن میں ایک-آدھہ سال میں چالیس سال ہونے والے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں 2010، 2011، 2012، 2013 لیکن پچھلے ایک-آدھہ سال سے دیکھہ رہے ہیں کہ جو بھی اسکیم بنی ہے، جس کو ٹالنا ہو، جس کا الیکشن سے پہلے جواب نہ دینا ہو، اس کو کہو 2022، پھر 2022 میں دیکھیں گے، تب تو لوگ بھول جائیں گے۔

اسی طرح سے آپ نے فارمرس کے ساتھہ بھی 2014 میں جو وعدہ کیا تھا کہ لاگت پلس پچاس فیصد پروفٹ، وہ تو ابھی تک ہوا نہیں، لیکن ابھی 2022 تک دوسرا لولی پاپ دے دیا۔ ابھی پہلا لولی پاپ تو ملا نہیں، دوسرا لالی پاپ دے دیا کہ آپ کی انکم دوگنی ہو جائے گی۔ اب میں تو کسان ہوں، ہمارے گھر میں بھی زمین، مال مویشی ہیں، لیکن جو سب لوگ بتاتے ہیں، جو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کے ایٹیشنل سکریٹری، ایگریکلچر، شری اشوک دلوائی کی recommendation کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ظاہر ہے سرکار نے کمیٹی بنائی تھی کہ فارمرس کی انکم 2022 تک دوگنی ہونی چاہئے۔ اس کی recommendation ہے کہ Rs. 6.4 lakh crore investment is needed for that. Rs. 6.4

[श्री गुलाम नबी आजाद]

lakh crore! اور ایگریکلچر کی آپ کی جو گروتھ ہونی چاہئیے، وہ دس فیصد سے بارہ فیصد ہونی چاہئیے، then only can you think of it. آپ کی گروتھ بارہ فیصد ہو، آپ اس پر ساڑھے چھ لاکھ کروڑ روپے خرچ کریں، تب یہ سپنا ساکار ہوگا، لیکن آپ کا جو ریکارڈ ہے، چار سالوں میں آپکی جو ایوریج ایگریکلچر گروتھ ہے، وہ 1.9 فیصد ہے۔ یہ ایک دفعہ ایک سال اوپر گیا تھا، لیکن آپ کی ایوریج ایگریکلچر گروتھ 1.9 فیصد ہے۔ اس صدی میں 2021 کے آخر تک یہ گروتھ بارہ فیصد ہونی نہیں ہے، آپ پچاس سال حکومت کریں گے، تو بھی آپ نے چھ لاکھ کروڑ روپے دینے نہیں ہے، تو ان کی انکم ڈبل نہیں ہونی ہے۔ لہذا یہ بہت simple method ہے۔ آپ کیوں ایسے وعدے کرتے ہیں، جن کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے اور جن کے لئے آپ کو پچھتانا بھی پڑتا ہے؟ اس سال کے ایگریکلچر بجٹ میں یہ کتنا بڑھا ہے، 4،845 کروڑ۔ اگر آپ کو اسے آنے والے چار سالوں میں اچیو کرنا تھا، تو اس کے لئے اس دفعہ آپ کو سوا لاکھ کروڑ روپے ایکسٹرا دینے چاہئے تھے، نہ کہ ساڑھے چار ہزار کروڑ۔ ایک دفعہ پھر، اب مجھے یہ کہنا بہت برا لگتا ہے کہ 'جھوٹا وعدہ'، لیکن آپ کسانوں کے ساتھ سچا وعدہ نہیں کر رہے ہیں، جو روز مرتے ہیں، جو روز آتمداہ کرتے ہیں، جو روز خودکشی کرتے ہیں۔ ان کی خودکشی پر مرہم لگانے کے بجائے آپ ان سے غلط وعدہ کرتے ہیں، جو وعدہ آپ کبھی پورا ہی نہیں کر پائیں گے۔ اس پر مجھے گھور آپتّی ہے۔

مانئے، پریزیڈینٹ ایڈریس میں آپ نے لکھا ہے-"To ensure availability of two square meals to every person, effective enforcement of National Food Security Act is necessary." شکر ہے کہ ابھی آپ فوڈ سیکورٹی ایکٹ کا نام بدلنا بھول

گئے ہیں، شاید ایک-آدھ سال میں یہ بدل جائے گا، لیکن میں سپریم کورٹ کو بدھائی دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے پچھلے سال کہا ہے۔ The Supreme Court in July, 2017 has said that the National Food Security Act, 2013 has not been implemented properly and it is a pity that legislation enacted by Parliament for citizen's benefit was kept on the backburner by various States. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کانگریس کا کوئی نیتا نہیں کہہ رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو وقت کا کھانا ensure کریں گے۔ یوپی۔اے۔ گورنمنینٹ تھی اور میں یوپی۔اے۔ گورنمینٹ کے پیچھے سونیا گاندھی جی کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا brainchild تھا کہ فوڈ سیکورٹی ہونی چاہئے۔ دیش میں جو غریب ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو کما نہیں سکتے، جن کے پاس زمین نہیں ہے، ان کے لئے دو روپے / تین روپے فی کلو اناج ہونا چاہئے۔

یہ یوپی۔اے۔ کی سب سے بڑی اپلبدھی رہی ہے اور سپریم کورٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک طرح سے لاگو نہیں کرتے ہیں۔

اگے ہے 'نیشنل ہیلتھ پالیسی'۔ چار دن ٹیلی ویژن پر 'نیشنل ہیلتھ پالیسی' کے بارے پارے میں ڈسکشن چلا۔ اس دفعہ ٹیلی ویژن پر اگر کسی چیز پر سب سے زیادہ ڈسکشن ہوا ہے، تو ہیلتھ پر ہوا ہے۔ لیکن بعد میں بیچارے کسان جاگ گئے کہ یہ تو ایسا ہی تھا، جیسے دس کروڑ نوجوانوں کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ تو جملہ ہی تھا، اسی طرح سے بیچارے ہیلتھ والےبھی پریشان ہیں کہ ہم کو کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن ان کو ملان کچھ نہیں ہے۔ میں پانچ سال اس منسٹری میں رہا اور اس دوران امریکہ کے ہیلتھ منسٹر کے ساتھ کئی میٹنگس ہوئیں۔ پرائم منسٹر ٹونی بلئیر نے چند دیشوں کے

[श्री गुलाम नबी आजाद]

ہیلتھ منسٹرس کو بلایا تھا، ہمیں بھی بلایا کہ اس انشورینس اسکیم کے بارے میں بتائیے۔ دونوں دیشوں نے کہا کہ اس انشورینس اسکیم نے ہم کو لوٹ لیا اور کھا لیا۔ ان انشورینس کمپنیوں نے تو پیسہ بنا لیا، لیکن اس سے لوگوں کا کچھ نہیں بنا۔ پلاننگ کمیشن میں جب چرچا ہوئی تھی، تو میں اتنی ڈھیر ساری کتابیں لے کر گیاتھا۔ آج میرے پاس کتابیں نہیں تھی، لیکن اس وقت منسٹری نے بہت ساری کتابیں دی تھیں۔ منسٹری بھی اچھی چیز ہے، نہ کہوں گے تب بھی کتابیں لائے گی اور ہاں کہوں گے تب بھی کتابیں لائے گی۔ اس وقت انہوں نے یہ کیس لڑنے کے لئے مجھے اتنی ساری کتابیں دی تھیں، جس میں امریکہ، برٹین اور کئی کنٹریز کا الیکھ تھا کہ ہیلتھ انشورینس اسکیمس کے مادھیم سے انشورینس کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو یا پیشینٹس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو میں امیر دیشوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے یہاں جی۔ڈی۔پی۔ کا دس، پندرہ فیصد یا سترہ فیصد خرچ ہوتا ہے۔ ہم تو ابھی ڈیڑھ فیصد سے ہی جوجھ رہے ہیں، تو ہمارا انشورینس کتنا ہوگا اور فائدہ کتنا ہوگا؟

میں مانئےپردھان منتری جی اور مانئے سواستھ منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ یہ اسکیم اٹھے گی ہی نہیں۔ آپ کی پہلے ایک انشورینس اسکمیم تھی، لیکن 16-2015 میں آپ نے ایک روپیہ بھی اس پر خرچ نہیں کیا۔ آپ نے 17-2016 میں 1500 کروڑ روپیہ اس اسکیم میں رکھا تھا، لیکن صرف 724 کروڑ روپیہ ہی خرچ کیا، یعنی آدھے سے بھی کم پیسہ اس پر خرچ کیا گیا اور 776 کروڑ روپیہ unspent رہ گیا۔ آپ نے اس اسکیم کے لئے 18-2017 میں ایک ہزار کروڑ روپے رکھے، لیکن صرف 471 کروڑ روپے ہی خرچ کئے، یعنی صرف 35 فیصد ہی خرچ کئے۔ آپ دو تین سال سے اس اسکیم کے لئے جو پیسہ دے رہے ہیں، وہ آدھا بھی خرچ نہیں ہو رہا، صرف 45-40

فیصد خرچ ہو رہا ہے۔ اب آپ پورے دیش کے لئے دو ہزار کروڑ روپے کی اسکیم بنا رہے ہیں، یہ دو ہزار کروڑ روپے کی اسکیم کب شروع ہوگی؟ یہ کامیاب نہیں ہونی ہے۔ اس کے بجائے، ہم نے اس سمبندھ میں جو قدم اٹھائے تھے، آپ سرکاری اسپتالوں کو آگے بڑھائیے۔ پرائیویٹ اسپتال کے لئے آج جو پانچ لاکھ دیں گے، آپ مجھے بتائیے، دو پرائیویٹ اسپتالوں میں آپ ڈاکٹرس کو دکھائیے، تو شام کو پانچ لاکھ کا بل آ جائے گا، اس لئے ہم یہ سوچتے تھے کہ سرکاری اسپتالوں میں علاج ہونا چاہئے، کیوں کہ جتنا پیسہ ہم انشورینس اسکیم پر لگائیں گے، اگرہم اپنا ہی سرکاری انفرااسٹرکچر مضبوط کرنے کے لئے، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر پر، ریجنل ہیڈکوارٹر پر لگائیں تو زیادہ اچھا رہے گا، آپ نے اپنے بجٹ میں چوبیس میڈیکل کالج رکھے ہیں، لیکن ہم نے اٹھاون میڈیکل کالج دئے تھے۔ شاید ہسٹری میں پہلی دفعہ ہمارے وقت میں ہیلتھ منسٹری، گورنمینٹ آف انڈیا نے میڈیکل کالج بنانے شروع کئے۔ سب سے پہلے تو ان اٹھاون میڈیکل کالجوں کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہئے۔ چالیس میڈیکل کالجوں کو upgrade کرکے AIIMS like institutions بنانے کے لئے پیسہ ریلیز ہوا، sanction کیا گیا، ان کو بنا دینا چاہئے۔

سر، ہم نے نئے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس، سب-ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لگ بھگ چالیس سے پچاس ہزار تک بنائے تھے اور اتنے کا ہی ایکسپینشن ہو رہا تھا، انہیں بنانا چاہئے تھا، میرے خیال میں، میں ابھی بھی کہتا ہوں، چاہے وہ ہمارے وقت میں سینکشن ہوئے، ہم نے پہلی دفعہ 71 کینسر انسٹی ٹیوٹس دئے اور ایک نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ، ججھر میں دیا، جس کا شاید دو چار مہینوں بعد مائنے پردھان منتری جی ادگھاٹن کریں گے۔ 2500 کروڑ روپے کی لاگت سے نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ بن رہا ہے۔ مائنے ڈاکٹر منموہن

[श्री गुलाम नबी आजाद]

سنگھ جی نے اس کا فاننڈیشن اسٹون لے لیا تھا اور شاید وہ ایشیا کا سب سے جدید اور سب سے بڑا کینسر انسٹی ٹیوٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیش میں کئی کینسر انسٹی ٹیوٹس اسٹیٹ ہیڈکوارٹرس اور ریجنل ہیڈکوارٹرس پر بن رہے ہیں۔ انہیں فورا وار-فٹنگ پر بنانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ بیمہ کمپنیوں کے ذریعے سےعلاج کرایا جائے۔ اس سے بیمہ کمپنیاں پیسہ بنائیں گی اور پیشینٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

اپ سبھا پتی مہودے، دو تین اسکیمیں اور ہیں۔ اسٹارٹ-اپ، اسٹینڈ-اپ اور اسکل انڈیا۔ اسٹارٹ-اپ ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن منزل پر ابھی ایک بھی نہیں پہنچی ہے۔ اسٹینڈ-اپ، یہ کھڑی تو ہوئی ہیں، لیکن بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اسکل انڈیا تو ناکام ہوئی، لیکن kill India ضرور ہوا۔ یہ تمام شبد ٹیلی ویژن، میڈیا، پرنٹ میڈیا، لکھنے اور چھاپنے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن ان میں دم کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اسٹنٹ ہی ہے۔

اُپ سبھا پتی، آج پیپر میں نکلا ہے کہ صرف 5 فیصد گرامین بچے ووکیشنل ٹریننگ لے رہے ہیں۔ جہاں پانچ فیصد ووکیشنل ٹریننگ رورل یوتھ لے رہے ہیں، تو کہاں ہے آپ کا اسکل انڈیا؟

اُپ سبھا پتی جی، اب میں ایمپلائمینٹ جنریشن پر آتا ہوں۔ آپ نے دیش کے دس کروڑ بچوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انہیں روزگار دیا جائے گا، لیکن وہ تو ہوا نہیں، سال 2015 میں ایمپلائمینٹ جنریشن پہلے پانچ سالوں میں سب سے کم تھی۔ سال 2016 میں سات سالوں کا ریکارڈ، ان-ایمپلائمینٹ میں بیٹ کیا۔ سال 2017 میں آپ نے پچھلے ایمپلائمینٹ جنریشن کا ریکارڈ بیٹ کیا، کوئی ایمپلائیمنٹ ہی نہیں

دی۔ اس طرح سے دیکھا جائے، تو آپ سال 2015، 2016 اور سال 2017 میں ان-ایمپلائیمنٹ جنریشن کا ریکارڈ آپ بیٹ کر رہے ہیں۔

اپ سبھا پتی جی، اب میں کشمیر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ Terrorist violence in the interiors of Jammu and Kashmir was directly related to the cross-border infiltration. With better coordination, the Army, paramilitary forces and Jammu and Kashmir Police are giving a befitting response to the perpetrators. یہ ایک ایسا ایشو ہے، جس میں پورا بھارت آپ ساتھ رہا۔ پورا بھارت آپ کے ساتھ تھا، پوری پارٹیاں آپ کے ساتھ تھیں، پورا وپکش آپ کے ساتھ تھا اور آپ کی سرکار بننے کے لئے پچاس فیصد رول سرکشا کا بھی ہے، کیوں کہ آپ نے، یعنی پردھان منتری جی نے خود، دیش میں چھ سو، سات سو میٹنگس کیں، سبھی میں آپ نے اس وقت کے پردھان منتری، اس وقت کے کانگریس کے منتری، اس وقت کے ودیش منتری، اس وقت کے رکشا منتری کی آلوچنا کی اور ان کے خلاف بولنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا۔ تب آپ نے کہا تھا کہ نکمی سرکار ہے، کمزور سرکار ہے اور آپ نے یہاں تک کہا کہ مرو-مرو اور ڈوب مرو، لیکن ہم نے زبان نہیں کھولی۔

[श्री गुलाम नबी आजाद]

آپ نے یہ کہا تھا کہ کمزور سرکار ہے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتی۔ یہ کہا تھا کہ ان کے منتری بریانی کھاتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فارین منسٹر چائینا میں ہی رہنا چاہتا ہے، لیکن وہاں بات نہیں کرپایا۔ آپ نے کہا کہ ہمارے ایک فوجی کی گردن کاٹ کر پاکستانی لے گئے اور یہ دیکھتے رہے۔ مانیئے پردھان منتری جی، دو منٹ کے لیے مان لیا کہ ہم کمزور تھے، لیکن آج جموں وکشمیر میں جو حالات ہیں، اس وقت کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مہان ہیں اور آپ کی سرکار سب سے کمزور ہے، ستّر سالوں میں سب سے کمزور ہے۔ ستّر سالوں میں سب سے زیادہ اگر سیز فائر وائلینس ہوئے ہیں، کسی تین سال کے عرصے میں، تو وہ آپ کے وقت میں ہوئی ہیں۔ چاہے وہ انٹرنیشنل بارڈر پر ہو، جموں، سامبا، کٹھوا میں ہو یا راجوری پونچھ کے ایل او سی پر ہو، سب سے زیادہ سیز فائر وائلینس ہوئے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے وقت میں وار کو چھوڑ کر، لڑائی کو چھوڑ کر، سب سے زیادہ فوجی اگر مرے ہیں، بارڈر کے سکیورٹی فورسیز کے لوگ سب سے زیدہ مرے ہیں، وہ اس وقت مرے ہیں۔ جنگ کے میدان میں چھوڑئیے، سب سے زیادہ اگر سویلینس مرے ہیں۔ تو ان تین سالوں میں مرے ہیں، چاہیے وہ کشمیر ہو یا جموں ہو۔ چار ہی کل مرے، ابھی پرسوں ہی کچھ اور مرے

تھے۔ میجر مرتے ہیں، کیپٹن مرتے ہیں، کرنل مرتے ہیں۔ مان لیجئیے، یہ سرکار بھول گئی۔

ابھی میں اور امبیکا سونی جی جموں کے کچھ علاقوں میں ہوکر آئے۔ ان لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ پاکستان کی شیلنگ سے دو دن کے اندر ہمارے آٹھ سِولینس مارے گئے، ہمارے پانچ فوجی مارے گئے۔ سیکڑوں گھر برباد ہوئے، ہزاروں جانور، بھینسیں گائیں، بکریاں برباد ہوئے۔ آپ کے لوگوں کو، بی جے پی کو لوگوں کو بارڈر پر نہیں جانے دیتے ہیں۔ آپ کو اطلاع ہے یا نہیں؟ وہ ان کو نہیں جانے دیتے ہیں، کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اس وقت وپکش کے خلاف ہمارے جذبات ابھارے تھے، لیکن جتنا ہم پٹے ہیں، ستّر سالوں میں کبھی کسی بھی سرکار کے وقت میں نہیں پٹے ہیں۔ آج جموں بارڈر پر، اخنور سے لیکر سامبا اور کٹھوا کے بارڈر تک تتھا راجوری سے پونچھ تک جو حالت ہے، وہ کوئی بھی دھرم کا ویکتی ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، وہ تین سال سے سو نہیں رہا ہے۔ کتنی دفعہ ان کو گھروں سے پلائن کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے وقت میں کہیں دس سال میں یا پندرہ سال میں اگر ہوتا بھی تو ایک آدھ گاؤں ہوتا، ابھی پندرہ بیس دن پہلے تقریباً 75,000 لوگوں نے بارڈر سے پلائن کیا۔ ان کے لیے سرکشا کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ان کے کھانے پینے کی ویوستھا نہیں ہے۔ وہ

[श्री गुलाम नबी आजाद]

بیچارے در بدر اسکولوں میں پھررہے ہیں۔ ان کے پاس مویشی نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، اناج نہیں ہے۔ ہم کب سے مانگ کررہے ہیں کہ ان کے لیئے سرکشت جگہ ہونی چاہئیے۔ میں جب مکھیہ منتری تھا، میں نے سینٹرل گورنمنٹ کے بغیر ہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم جموں میں، سامبا میں سُرکشت جگہ پر پانچ مرلہ زمین دیں گے۔ میرے وقت میں، تھوڑی سی زمین ہم نے ایکوائر کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپن کام پورا کرتا، آپ کے سہیوگیوں نے، جو آج آپ کے سہیوگی ہیں انہوں نے سپورٹ وِڈڑا کرلی۔ ...(مداخلت)... اس لیے کی تھی کہ آپ تو بڑے دھرم کو ماننے والے ہیں۔ اس تیرتھ استھان کے لیے میں نے زمین دی تھی اس لیے آپ کے پارٹنر نے ...(مداخلت)... میں نے امرناتھ یاترا کے لیے زمین دی تھی، اس لیے سپورٹ وِڈ ڈرا ہوگئی تھی۔ اب آپ کی بھی جلد ہی ہوجائگی، آپ فکر مت کیجیئے۔ چوہا بلی کا کھیل تو وہاں روز چل رہا ہے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جموں میں بارڈر پر لوگ بہت تنگ ہیں، مایوس ہیں، وہاں آج بھینکر حالت ہے۔ کشمیر میں تو جتنی غریبی اور جہالت آپ ڈال سکتے تھے، لاسکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کہ اس سرکار کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کبھی hot pursuit کی بات کرتے ہیں، تو کبھی کوئی اور بات

کرتے ہیں۔ کبھی کچھ ایک لوگوں کو این آئی اے تک اندر ٹھوکتے ہیں، تو کبھی ان کے پیچھے پھر یہاں سے interlocutor بھیجتے ہیں، بات کرنے کے لیے۔

یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتیں ہیں، hot pursuit تو hot pursuit یا بات چیت تو بات چیت۔ جب ہم نے شروع میں کہا کہ بات چیت کیجیئے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو پاکستانی ہیں میرے کہنے کا مطلب غلام نبی آزاد نہیں بلکہ جب اپوزیشن والے کہتے تھے کہ ان کو بڑی سہانوبھوتی ہے، ان کو بڑی ہمدردی ہے، ان کو پاکستان کے ساتھ بڑا پیار ہے اور یہ جو حریت والے ہیں، یہ بات چیت کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو ہم چپ بیٹھتے ہیں، ہم کچھ بات نہیں کریں گے، آپ جو مرضی، وہ کرو۔ اب آپ چار سال نہ بات کررہے ہیں، نہ آپ کا hot pursuit چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا ہے اور اس بیچ میں جموں وکشمیر کے لوگ تباہ اور برباد ہوگئے، یہ میں اس سدن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کہا ہے، 'Due to successful diplomatic efforts' اس پر ہمارے دوسرے ساتھی آنند شرما جی بولیں گے، لیکن کیا ہوا؟ آپ اظہرمسعود کا کچھ کرنہیں پائے، چین نے آپ کو کرنے نہیں دیا۔ Membership of Nuclear Suppliers Group کے سمبندھ میں بھی آپ کچھ نہیں کرپائے، چین نے آپ کو کرنے ہی نہیں دیا۔ چین آپ کو Security

[श्री गुलाम नबी आजाद]

Council کا ممبر بننے نہیں دیتا ہے، تو آپ کی کیا کُوٹ نیتی ہے، کون سی کُوٹ نیتی ہے؟

مہودے، میں آخر میں ٹرپل طلاق پر آنا چاہونگا۔ مہامہم راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں ٹرپل طلاق کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ مانا کہ بی جے پی کی سرکار نے پہلے اپوزیشن کی پالیٹیکل پارٹیوں کو بانٹا، ان کو ٹیوائیڈ کیا۔ کسی کو ای ڈی سے ڈرا کر، کسی کو انکم ٹیکس سے ڈرا کر، کسی کو این آئی اے سے ڈرا کر بانٹا، کیوں کہ آج راجنیتی زیادہ ہورہی ہے، آج ڈراؤ والی راجنیتی سب سے زیادہ ہورہی ہے۔ فکس کرنے والی راجنیتی زیادہ ہورہی ہے۔ ہم نے یہ راجنیتی کبھی نہیں دیکھی۔ ہمارے وقت میں، جب ہم راجنیتی میں چھوٹے ہی تھے، تب کہتے تھے کہ یہ بی جے پی کا فائنانسر ہے، اس کو مت چھیڑنا۔ آج تو ڈھونڈ کر کہتا کہ تم کہو کہ تم کانگریس کے ہو، تم سماج وادی کے ہو، تم بی ایس پی کے ہو، تم ممتا کے ہو، تم اس کے سمرتھک ہو، تاکہ تم کو اندر ڈالیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات بھی نہیں کرنی ہے۔ مانیئے پردھان منتری جی، آپ سمجھ نہیں سکتے، اتنا ڈر، اتنا بھئے، اتنا خوف ہے دیش میں۔ سچّا میں رہ کر یہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں۔ یہ بھئے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر افسر کام نہ کرے، تو اس کو بھئے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کرپشن کرتے ہوئے پکڑا جائے، تو اس کے لیے ایسا ہو۔ ہم نے بھی اس کے لیے

سخت قانون بنایا، شاید دنیا کا پہلا قانون ہم نے جموں وکشمیر میں بنایا کہ اس کی پراپرٹی اٹیچ کیا جائے۔ اس سے ڈر ہے لہیکن یہ کہ کسی اپوزیشن والے کے گھر جاؤں، اس سے بات کروں، اس سے ٹیلی فون پر بات کروں۔۔ تو میں کوئی بزنیس نہیں کرسکتا، تجارت نہیں کرسکتا، انسٹی ٹیوشن نہیں چلا سکتا، مانیئے پردھان منتری جی، یہ بھئے دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دیش کے لوک تنتر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ Freedom of speech, freedom of socializing, freedom of business, یہ سب تو ہونے چاہیئے۔ آج ہم سے فون پر کوئی بات نہیں کرتا، کیوں کہ وہ فون ٹیپ ہوجائے گا۔ ہم نے تو کبھی نہیں یہ کیا۔ ہم نے کوئی ٹیپ نہیں کیا۔ ہم نے یہ سنا بھی نہیں کہ کسی کا فون ٹیپ کیا جائے۔ آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ کسی آتنک وادیوں کا فون ٹیپ ہوتا ہے۔ جب میں پہلی بار چیف منسٹر بنا، تو ہم نے آتنک وادیوں کے فون ٹیپ کرتے تھے، لیکن لیڈروں کے فون ٹیپ نہیں ہوتے تھے۔ کشمیر جیسے سینسیٹیو ایریا میں میں وہاں تین سال رہا، اس درمیان کسی نے ہم سے یہ پوچھنے کی جرأت نہیں کی کہ ہم کسی لیڈر کا فون ٹیپ کریں یا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ وپکش کا لیڈر ہو یا کوئی اور ہو یا اس کے لنکس کچھ بھی ہوں، ایکسیپٹ فار ٹیررزم۔ آج توآپ نے ہمیں ٹیررسٹ بنا دیا، انٹرنیشنل ٹیررسٹ بنادیا۔ آپ نے

[श्री गुलाम नबी आजाद]

اپوزیشن کو ہی ٹیررسٹ بنادیا. اس طرح کے بھئے، ڈر اور خوف کی بدولت جیتنا ہوا، تو یہ کیا جیتنا ہوا؟

میں نے گجرات میں ہی دیھا، میں نے اپنے بھاشن کی زیادہ پبلسٹی نہیں لی، لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار لوگ یہاں ہیں، ان میں سے سات سو ہمارے ہیں یعنی بی جے پی کے ہیں اور اگر سات سو سے اوپر ووٹ آگئے، تو آپ نے ووٹ دیا اور اگر سات سو ہی رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف بی جے پی والے نے ووٹ دیا ہے، آپ نے نہیں دیا ہے، اس لیے تمہاری خیر نہیں.

یہ کون سا ووٹ مانگنے کا، ووٹ garner کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ڈراکر، دھمکاکر ووٹ لے لو. ڈرا دھمکاکر تو ہم بھی ہندستان میں ستّر سال یا اس سے آگے، دو سو سال تک حکومت کرسکتے تھے. میں آپ سے وِنتی کرتا ہوں کہ ایسی راجنیتی مت کرئیے ...(مداخلت)... اس پر آپ بہت روٹیا سینک چکے ہیں، دس دفعہ کہہ چکے ہیں ...(مداخلت)... ایسی چیزوں کی وجہ سے ہی آپ کی پہچان ہونی، ورنا آپ کو پہچانتا ہی کون تھا؟ ...(مداخلت)...

مہودے، ٹرپل طلاق کا ہم سمرتھن کرتے ہیں، لیکن ٹرپل طلاق کے دو بھاگ ہیں. لأ منسٹر صاحب کو میں نے سمجھایا تھا کہ ٹرپل طلاق کے دو بھاگ ہیں. ایک

اچھی بھاؤنا سے طلاق اور دوسرا کمیونٹی کو صاف کرنے کی بھاؤنا سے طلاق۔ اچھی بھاؤنا ہے۔ انسٹینٹ ٹرپل طلاق ‘طلاق طلاق طلاق’ چاہے آپ طلاقِ بدعت ٹیلی فون پر کریں، ایس ایم ایس سے کریں یا زبانی کریں۔ اس کے ہم خلاف ہیں، لیکن اس کا دوسرا پارٹ بہت خطرناک ہے۔ جو آپ اِلّیگلی کرتے ہو، اسے لیگل بناکر کرنا چاہتے ہو۔ وہ ہے کہ اسے آپ کریمنل ایکٹ میں لاکر پتی کو جیل میں ڈال دو۔ جب تک پتی واپس آئے، اس کی پتنی کہاں رہیگی، اس کے بچے کہاں رہیں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے، کہاں سے پائیں گے؟ پہلے آپ نے شیعہ سنی کو بانٹا اور اب پتی پتنی کو بانٹ رہے ہیں۔ کسی کو تو چھوڑ دیجیئے، کوئی گھر تو آپ چھوڑ دیجیئے۔ پہلنے پالرازیشن کرکے مجھے اور آنند شرما جی کو بانٹ دیا۔ ...(مداخلت)... میں یہاں دھرم کی بات کرتا ہوں۔ پھر مجھے اور اگروال جی کو بانٹ دیا۔ مجھے اپنے آپ کو ہی بانٹ دیا، پالرائزیشن کے ذریعہ دو دھرموں کا بٹوارہ۔ کاسٹیزم تو پہلے سے ہی تھا، لیکن دو دھرموں کا بٹوارہ اس سرکار میں ہوا۔ پھر شیعہ سنی کا بٹوارہ کیا اور کہا کہ شعیہ ہمارے اور سنی دوسری پارٹیوں کے۔ اب سنیوں مین بھی جو مرد اور عورت تھے، ان کا بھی بٹوارہ کردیا۔ مرد کو جیل میں ڈالو اور عورت سے کہہ دیا کہ تمہاری سمسیا کا ہم نے سمادھان کردیا۔...(مداخلت)۔

یہ کون سا بٹوارہ ہے؟ کیوں آپ توڑ رہے ہیں؟ یہ مائنارٹی کمیونٹی پہلے ہی ٹوٹی ہے، غریب ہے، ان میں ڈر ہے، بھنے ہے۔ لنچنگ سے ڈری ہوئی ہے، ٹرین میں ڈرتی ہے، کار میں گھومنے سے ڈرتی ہے۔ اگر کسی بینک میں اپلی کیشن دیتیہ تو بینک لون اس ملتا نہیں۔ پتی کے ساتھ رہ رہی ہے، اسےبھی آپ نہیں رہنے دیں گے، پتی کو جیل میں ڈالکر، تم ہمیں ووٹ دے دو۔ خدا کے لیے کوئی گھر تو چھوڑو،

[श्री गुलाम नबी आजाद]

کہیں تو معافی دے دو۔ اس طرح کا ٹرپل طلاق لاکر آپ دیش کو بانٹنے کا کام نہ کریں۔ ہمیں اپنا بھارت لوٹا دو۔ جو نیا بھارت آپ نے آج بنایا ہے، ہمیں وہ نیو بھارت نہیں چاہیئے۔ ہمیں اولڈ بھارت چاہیئے، ہمیں گاندھی کا بھارت چاہیئے، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی، ویسے سکھ اور عیسائی میں تو کوئی وِواد نہیں ہے، لیکن جہاں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے خون دیتے تھے، وہ پرانا بھارت تھا، جسے آپ نے ووٹ کے لیے، سرکار کے لیے پالرائز کردیا اور برابر نرنتر کرتے جارہے ہیں، وہ بھارت ہمیں لوٹا دو۔ ہمیں وہ بھارت لوٹا دو، جس میں ڈر نہیں ہو، بانٹ نہیں ہو۔ ہمیں وہ بھارت لوٹا دو جس میں دو مہینے تین مہینے یا چار مہینے کی بچی کے ساتھ بلاتکار نہ ہوتا ہو۔ اس بھارت کی ہمیں ضرورت ہے۔ انہیں شبدون کے ساتھ، مانیئے اُپ سبھاپتی صاحب، میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں اور مہامہم راشٹرپتی جی کے ابھی بھاشن پر جو یہاں دھنیواد پرستاؤ مانیئے امِت شاہ جی نے رکھا ہے، اس کا سمرتھن کرتا ہوں، جے ہند۔

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी, दो योग्य वक्ताओं ने अपनी बात को बड़ी काबिलियत के साथ रखा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ...(**व्यवधान**)... तीन? अच्छा, चलिए सहस्रबुद्धे जी को भी जोड़ लेते हैं। वैसे वे हमारी श्रेणी में हैं। हमने दो योग्य जोड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अपनी स्पीच कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़, जो इस साल के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं, उनमें से एक महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और दूसरा केन्द्रीय बजट, ये दोनों दस्तावेज़ देश के सामने आए। मैं यह करीब-करीब चुनावी वर्ष में समझ रहा हूँ, क्योंकि सात राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। भाजपा जानती है कि उन चुनावों को अगर वह अकेले लड़ ले, तो शायद वह नहीं लड़ पाएगी। मुझे लग रहा है कि इन सात राज्यों के चुनावों के साथ पार्लियामेंट के चुनाव भी होंगे। मैंने सोचा था कि बजट में कुछ छूट मिलेगी, महामहिम राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कुछ बातों को कहेंगे। राष्ट्रपति जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, पहली बार राष्ट्रपति हुए। हम उत्तर प्रदेश के लोग वैसे भी बोलने में राजनैतिक लोग होते हैं और कहने में कहीं संकोच नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी निराशा हुई। हमने यह सोचा ही नहीं था कि आज देश को बीच समुद्र में खड़ा कर दिया जाएगा। हमने यह सोचा ही नहीं था कि देश के सामने यह स्थिति खड़ी होगी। बजट बड़ा जोर-शोर से पेश किया गया, किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला। एकदम छला हुआ! मैं सरकार से इतना और कहना चाहूँगा कि आज अगर सबसे ज्यादा किसी को बदनाम किया जा रहा है, तो हम राजनैतिक व्यक्तियों को बदनाम किया जा रहा है। हमारा चीर-हरण हो रहा है। मीडिया हमारा चीर-हरण कर रही है।

5.00 P.M.

जनता के बीच हमारी छवि बड़ी खराब बनाई जा रही है और रही-सही कर सरकार -- श्रीमन्, ऐसा लगता है कि सिर्फ अपोज़िशन के लोग भ्रष्ट हैं। सीबीआई, ईडी या और भी जो कार्रवाई कर रही हैं, वे सिर्फ विरोधी लोगों पर कर रही हैं और मेरे ख्याल से सबसे ईमानदार लोग सत्ता पक्ष के हैं। ...(**व्यवधान**)... वे दूध के धुले हैं। कल आपके ही राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री घोषित किया गया, जो घनघोर भ्रष्टाचार में हटाए गए। ...(**व्यवधान**)... मैंने कहा न, घनघोर भ्रष्टाचार में हटाए गए, लेकिन चूंकि वे बीजेपी में हैं, इसलिए वे ईमानदार हो गए। ये चीज़ें बन्द कर देनी चाहिए। आईएएस-आईएएस के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करता, जज-जज के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों पर महिलाओं ने आरोप लगाए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब बन्द हो गया। अगर किसी नेता पर आरोप लग गया होता, तो केस में नेता को ऑटोमैटिक बुला लिया गया होता। यह मानकर चलिए कि नेता का चुनाव लड़ना, उसके सामने कुछ मजबूरी होती है। अगर वह थोड़ा भ्रष्ट भी होगा, तो चुनाव में खर्च तो कर देगा। जब वह चुनाव लड़ेगा, तो उसमें खर्च भी होगा, बिना पैसे के कौन चुनाव लड़ेगा? रवि भाई, आप बिना पैसे के बिहार में चुनाव लड़ लीजिए। वहाँ जब आपका लालू जी से मुकाबला होगा, तो वहां के आपके जो मुख्य मंत्री हैं, उनका अता-पता भी नहीं मिल पाएगा, जो बिहार की हालत है। तब पता लगेगा कि चुनाव में किस तरीके से पैसा खर्च होता है। यह तो अच्छा है कि हम उत्तर भारत के लोग इनके साउथ से, हमारे अनंत कुमार जी के यहाँ से बचे हुए हैं। अभी साउथ के एक राज्य में एमएलए का चुनाव हुआ। हमने उनकी पार्टी के लीडर से पूछा कि कितना खर्च हुआ? वे कहने लगे - 80 करोड़ रुपये। आप कहिए, तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूं। मैंने कहा - 80 करोड़ रुपये? वे कहने लगे - प्रति वोट 2,700 रुपये दिया है। हमने पूछा- कैंडिडेट ने कैसे bear कर लिया? इस पर वे कहने लगे - वह हमारे यहाँ पार्टी और सरकार bear करती है।

तमिलनाडु में भी एक चुनाव हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सबको इस चीज का ज्ञान है। अभी उत्तर भारत में बचे हुए हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कि आप नेताओं को कैसे करप्ट मानकर चल रहे हैं। कम से कम इसको तो बंद करिए और अगर बंद नहीं करेंगे तो जग हंसाई हम सब की होगी। मुझे खुशी है कि मैंने एम.पी. सैलेरी का मामला उठाया था। चलिए, आपने एम.पीज. को पहली तारीख से कुछ देने को कहा। मैं कहूंगा कि मीडिया वालों की भी कुछ मदद कर दीजिए। इनके मालिक इनका बहुत शोषण कर रहे हैं। एक कानून इनके लिए भी ला दीजिए, कम से कम वे हमारे साथ तो खड़े हो जाएं। दिन भर दौड़ते हैं हमारे और शाम को निकल लिए। इनकी कांट्रैक्ट सर्विस चल रही है। इनको भी सुरक्षा दे दीजिए, इनकी भी तनख्वाह फिक्स कर दीजिए। हमारे लोक सभा के एक एम.पी. थे, उन्होंने स्पीकर साहब को चिट्ठी लिख दी, हैं तो वे हमारे भतीजे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उसमें बड़ी आदर्शवादिता थी। ऐसा लगा कि हिन्दुस्तान के हर आदमी का स्विटज़रलैंड में एकाउंट है, ऐसा लगता है कि स्विटज़रलैंड में हम सब का एकाउंट है। जो लोग गोल्डन स्पून इन दि माउथ पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबों की हालत नहीं मालूम। आप इनको सिखाइए कि राजनीति में कितना त्याग और तपस्या करके आदमी आता है। परिवार के नाम पर तो बहुत लोग जीत जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जमीन से राजनीति से जुड़े होते हैं। मैंने आज वह भी स्थिति देखी है कि तमाम एम.एल.एज़., तमाम एम.पीज़. चाय की दुकान चला रहे हैं अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए। उनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए। हमारे हरदोई में एक एक्स एम.पी. हैं, उनका बेटा पुताई का काम करता है, मजदूरी का काम करता है।

[श्री नरेश अग्रवाल]

वे दो टर्म्स एम.पी. और 5 टर्म्स एम.एल.ए. रहे थे। उनकी हालत तो देख लीजिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि एक्स एम.पीज़. को भी आप कुछ राहत दे दीजिए, वह ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमसे कहा है कि एक दिन तो सब को एक्स होना है। परमानेंट कौन है? अभी गुलाम नबी जी कह रहे थे कि परमानेंसी कोई मत समझिएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह गए, हो सकता है कि कल आप ही आ जाओ। हो नहीं सकता, आ ही रहे हैं हम। नीचे की जो स्थिति है, वह स्थिति आने वाली है। ...(**व्यवधान**)...

काला धन और उसके नाम पर आपने देश से एकदम भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया और आज स्थिति यह हो गई है कि आप खान मार्केट चले जाइए, कनाट प्लेस चले जाइए, बड़े-बड़े घरों के लड़के फटी पेंट पहन रहे हैं और फटी हुई टीशर्ट पहन रहे हैं। अगर उनकी यह हालत होगी तो गरीबों की क्या हालत होगी? एक जमाने में फटी पेंट बर्तन वाले ले जाते थे। अगर हमारे देश की हालत यह हो गई कि बड़े-बड़े घर के लड़के फटी पेंट पहनने लगे ...(**व्यवधान**)...

महोदय, दिल्ली में सीलिंग के विरोध में तीन दिन से बाजार बंद हैं। आप पार्टी वाले बैठे हुए हैं संजय भाई और दोनों गुप्ता जी, ऐसा लग रहा है कि आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिल रही। आपने मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान से एक महीने बाद कुछ राहत मिलेगी। तब तक दिल्ली का बाजार बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी क्या करेगा? अगर उसके हाथ में कटोरा पकड़ाने की आपकी योजना है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे याद है कि पिछले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री जी आए थे, कहने लगे नरेश जी, इस बिल को अभी पास करा दीजिए, नहीं तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो जाएगा। हम लोगों ने समझा कि बिल पास करा दिया तो दिल्ली ठीक हो गई, लेकिन आज इतनी समस्या है तो उसका समाधान तुरन्त क्यों नहीं करते? यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि देश में किसी के लिए मजबूरी होती है। जो आरएसएस वाले प्रचार करते हैं कि मोदी का विकल्प क्या है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक ज़माने में नेहरू जी का भी विकल्प कोई नहीं था, इंदिरा जी का भी विकल्प कोई नहीं था और राजीव गांधी जी का भी विकल्प कोई नहीं था, लेकिन इस देश में विकल्प बने हैं। इस देश का विकल्प जनता बनाती है। आप यह गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपके संगठन की वजह से आपको वोट मिले हैं। यह मीडिया और इनकी देन है। अम्बिका सोनी जी यहां बैठी हैं, ये सूचना और प्रसारण मंत्री थीं। मैंने सेंट्रल हॉल में इनसे कहा कि अम्बिका जी, यह मीडिया आपके खिलाफ क्या-क्या प्रचार कर रहा है, आप मंत्री हैं, आप इसको रोकिए। इन्होंने कहा, मैं क्या कर सकती हूं? मैंने इनसे कहा कि आप मेरी यूथ की अध्यक्ष रही हैं और आप ऐसी बातें मुझसे कह रही हैं? आप हमें एक हफ्ता बिठा दीजिए और ये मीडिया वाले जो हम कहें, वह लिखते हुए न दिखायी दें तो कहें। आज यह सरकार वही नहीं कर रही है। वह जो चाहती है, मीडिया लिख रहा है और जो वह चाहती है, वही मीडिया कहेगा। दिन भर मीडिया इनकी प्रशंसा करता है। एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में अगर एक बलात्कार हो जाता था या एक लूट की घटना हो जाती थी तो हमारी अक़लियत सरकार के खिलाफ मीडिया इतना चलाता था कि लगता था हिन्दुस्तान में डाला-डोला आ गया, भूकंप आ गया - उसे गांव में डाला-डोला कहते हैं - लेकिन आज क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आज क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट पूरा रुक गया है, उत्तर प्रदेश में

फर्ज़ी encounter हो रहे हैं, एक-एक दिन में 37-37 मुठभेड़ें हो रही हैं, वहां कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कासगंज में खुले-आम तिरंगे झंडे के नाम पर जिस तरह से अराजकता फैलायी गयी, अगर आप उसकी आड़ लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यह गलगफहमी निकाल दीजिए। आपके कुछ नेता कर्नाटक में गए। उन्होंने कह दिया कि हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। ...(**व्यवधान**)... अब हमसे मत कहलाइए। अगर आप इन भाषणों को देश का सोच रहे हों ...(**व्यवधान**)...

श्री तपन कुमार सेन (पश्चिमी बंगाल): आपके अनंत हेगड़े साहब क्या कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री बी.के. हरिप्रसाद: वह अनंत कुमार नहीं, अनंतकुमार हेगड़े ने बोला है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल: लोकतंत्र के चार खंभे हैं। मैं कह रहा था कि अखिलेश जी की सरकार में मीडिया को सब कुछ खराब दिखता था, लेकिन आज वहां रोज रेप और अन्य चीज़ें हो रही हैं लेकिन उन्हें सब अच्छा दिखायी दे रहा है। देश में दो ही लोग चल रहे हैं - मोदी-मोदी और योगी-योगी, बाकी सब बेकार हैं। ऐसा लग रहा है देश में बाकी कुछ रह ही नहीं गया है। ऐसे ही हमारे साथ भी था। जब emergency थी, हम यूथ कांग्रेस में थे, भाई साहब भी थे, सब थे। उस समय बड़ा अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, सब तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस थी और इंदिरा जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हम भी यंग थे, बड़ा अच्छा लगता था, अफसर सलामी देते थे, यूथ के अध्यक्ष थे, जिधर निकलते थे, मंत्री हम लोगों के पीछे होते थे लेकिन 1977 का चुनाव हुआ तो क्या हुआ? राजस्थान ने आपको alarm किया है। यह alarming situation है। आप सोच लीजिए, बहुत दिन नारों और जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। बहुत जुमले हो गए हैं, बहुत नारे हो गए हैं, देश को कुछ चाहिए। जो गुलाम नबी जी ने कहा, हमें वह भारत चाहिए, जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया बैठे, जहां हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक हों, जहां कहीं साम्प्रदायिकता न फैली हो। जहां जिस राम के नाम पर आप वोट ले रहे हैं, वह राम राज्य हमें दिखायी दे - हमें वह भारत चाहिए, हमें साम्प्रदायिकता का भारत नहीं चाहिए। आप अपनी सोच बदल दीजिए। आप गलतफहमी में मत रहिए। हिन्दू कभी सम्प्रदायिक नहीं होता। मैं यहां एक बात आपसे कह देता हूं कि किसी कौम को बहुत दिन डराकर रखना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। मैं हिन्दुस्तान के मुसलमानों को बधाई दूंगा कि सबसे बड़ी आबादी अगर विश्व में मुसलमानों की कहीं है तो हिन्दुस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश अगर कोई है तो वह हिन्दुस्तान है।

श्री आनन्द शर्मा: इंडोनेशिया के बाद दूसरा है।

श्री नरेश अग्रवाल: नहीं। हमारे यहां 25 परसेंट जोड़ दीजिए, हम सबसे बड़े देश हैं, लेकिन यहां मुसलमान मिक्स्ड आबादी में रहता है। हिन्दू-मुसलमान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हम एक दूसरे के घर शादी में जाएं, एक दूसरे के घर ईद में जाएं और वे होली में हमारे यहां आएं। यहां का मुसलमान शांत है। इन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और यह आपको सोचकर चलना चाहिए। प्रजातंत्र के चार खम्भे हैं, आपने media अपनी जेब में कर लिया। जनता ने आपको बहुमत देकर बैठा दिया अब चाहे जिसको आप money bill कर दीजिए और हम लोगों की और राज्य सभा की जरूरत ही नहीं है।

[श्री नरेश अग्रवाल]

संविधान ने अनुच्छेद 110 में Money Bill का अधिकार आपको दे दिया है, जिसको चाहे आप उसको Money Bill कर दीजिए, तो यह लोक सभा और राज्य सभा भी बेकार हो गई, bureaucracy भी आपके कब्जे में है। अब judiciary के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जज खुले-आम आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जज खुले-आम आरोप लगा रहे हैं और फिर उन्होंने मीडिया में कहा और मैं चाहता हूं कि इस सदन में चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वे आरोप क्यों लगाए गए हैं? आखिर वे आरोप क्यों लगाए गए हैं? उन आरोपों का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के दबाव में उन जजों के खिलाफ social media में कहा गया कि वे कांग्रेसी हैं? अब social media में यह भी चल रहा है, "नौकरियों पर पड़ा हथौड़ा, बेचो चाय और तलो पकौड़ा।" यह आजकल social media पर बहुत तेजी से चल रहा है। आप सारे स्तम्भों को कब्जे में करते चले जा रहे हैं तो फिर प्रजातंत्र कहां रह गया है, यह तो तानाशाही का स्वरूप हो गया। Democracy जिंदा रखिए। यदि democracy जिंदा नहीं रखी तो यह बहुत अच्छा नहीं होगा। इस सरकार ने अब तक विज्ञापन पर 3,755 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। गुलाम नबी जी कह रहे थे कि स्वच्छ भारत के ऊपर 550 करोड़ रुपये पब्लिसिटी पर खर्च किए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर भी खर्च किए और योगा में सरकार के 450 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इतने रुपये में तो कोई योजना देश में दे देते उस गरीब का एक तो पिंड छूट जाता। किसान खुदकुशी करके मर रहा है। किसान को आप क्या दे रहे हैं? किसान तो खुदकुशी कर रहा है। अभी मैं किसान पर आगे आऊंगा।

श्रीमन्, बजट आया। इन्होंने कहा कि यह बजट कृषि प्रधान बजट है। हर अखबार में मोटा-मोटा लिखा - चलो गांव की ओर, गांव का बजट। जैसे हमारी Under-19 team ने अभी New Zealand में Australia के खिलाफ जो World Cup जीता है तो एक अखबार ने लिखा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसा लगा कि जैसे क्रिकेट से ही पूरी दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी। यहां राजीव शुक्ल जी बैठे हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया कि सब क्रिकेट में ही कर दिया। इन्होंने देश में बाकी sports खत्म ही कर दिए। ऐसे ही सारे अखबारों ने लिख दिया कि चलो गांव की ओर, गांव वालों को सब दे दिया। आपने गांव वालों को क्या दिया? आज खाद लेनी हो तो अंगूठा लगाएं, बीज लेना हो तो अंगूठा लगाएं, फसल की उचित कीमत नहीं मिलती है। अगर आप डेढ़ गुने की बात करते हो तो गेहूं की MSP 1640 रुपये है। बाज़ार में एक महीने बाद गेहूं पक कर आ जाएगा, आप उसका दाम डेढ़ गुना घोषित कर दीजिए और उसे कार्यान्वित कीजिए। जैसे आपने Health Policy के बारे में कहा है कि यह अभी लागू होगी और फिर आप कहेंगे कि अक्टूबर-नवम्बर में लागू होगी। फिर आपने उसमें कह दिया कि 60% हमारा रहेगा, 40% राज्यों का रहेगा। राज्यों की हालत यह है कि राज्यों का सारा development खत्म हो गया क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के नाम पर प्रदेश का सारा पैसा ही चला गया है। अखिलेश जी ने तो सरकार के पैसे से तमाम सड़कें बनवा दीं। अब उत्तर प्रदेश में कुछ पैसा मिल पाएगा? मैं गुलाम नबी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कुछ निजी insurance कंपनियों को फायदा देने के लिए प्रीमियम दिलवाया जाएगा। मेरी wife बीमार थी, मैं परसों उनको मैक्स अस्पताल से लेकर आया, मैंने डाक्टर से पूछा कि आपका हॉस्पिटल कितने लोगों को insurance की सुविधा देता है, तो उन्होंने कहा कि 1% की भी नहीं देता। हम आज 60 साल की उम्र से ऊपर हैं और हम किसी इंश्योरेंस कम्पनी से अपना हैल्थ बीमा करवाने के लिए कहें, तो इंश्योरेंस कम्पनी हमारा हैल्थ

बीमा नहीं करेगी, क्योंकि हम 60 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं। हर आदमी को मेडिकल की जरूरत तो 60 साल की उम्र के बाद ही पड़ती है, उसके पहले तो वह हृष्ट-पुष्ट घूम ही रहा है, इसलिए उसको आपके हैल्थ बीमा की क्या जरूरत है? उसके पहले तो भगवान ने उसको हट्ट-कट्टा बनाया ही है और वह हट्टा-कट्टा घूम ही रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हैल्थ बीमा किसको दे रहे हैं? आप किसकी हैल्थ ठीक कर रहे हैं? आप 50 करोड़ लोगों को दो हजार करोड़ रुपये में पांच लाख रुपये तक का बीमा दे देंगे कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाएगा, तो उससे वहां पर पांच लाख रुपये तक का बिल नहीं लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप मेरे साथ कपड़े बदल लो और रात में किसी अस्पताल में मेरे साथ चलो। पहले वह इतनी जांच लिख देगा कि उसी में लाख-डेढ़ लाख रुपया चला जाएगा। कोई भी बिल दो-तीन लाख से कम का नहीं होगा और आप उससे कह दीजिए कि इसका पेमेंट बीमा कम्पनी से मिल जाएगा, तो वह आपको बंद कर देगा। आजकल तो अस्पताल वाले बिना पेमेंट लिए डेड बॉडी भी नहीं देते हैं। अब तो अपोलो जैसे अस्पताल डेड बॉडी रख लेते हैं और कहते हैं कि पहले पैसे दो। अब तो ऐसा भी नहीं है कि मरीज बेचारा मर गया, तो उसकी डेड बॉडी को जाने दें।

उपसभापति महोदय, पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब से आप नई पॉलिसी लाए हैं, तब से पेट्रोल के दाम 9 रुपये लीटर और डीजल के दाम 7 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं। एक ज़माना था, जब हम लोग बजट को सुनते थे। हम बजट को इसलिए सुनते थे कि किस चीज़ के कितने दाम हो गए और वे दाम साल भर तक तो रहेंगे। इंदिरा जी के समय में जब बजट आता था, तब यह होता था कि उसके बाद दाम नहीं बढ़ेंगे। अब तो बजट का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। मैं उस दिन अस्पताल में था, अखबारों ने बड़े जोर-शोर से लिखा कि डीजल और पेट्रोल दो रुपये सस्ता हुआ। मैंने कहा कि चलो कुछ तो असर हुआ, लेकिन अगले दिन पढ़ा कि उन्होंने दो रुपये सस्ता कहां किया, उन्होंने 6 परसेंट एक्साइज़ ड्यूटी घटाई और 8 परसेंट सेस लगा दिया, तो उसकी कीमत तो उतनी ही रही। देश में कहां पर पेट्रोल, डीजल सस्ता हुआ है, देश में कौन-सी चीज़ सस्ती हुई है?

आप कहते हैं कि "उज्ज्वला योजना" में हम सबको रसोई गैस दे रहे हैं। आप जरा देख तो लीजिए कि उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है। कोई आदमी मुफ्त में रसोई गैस प्राप्त नहीं कर रहा है। उनको दो सिलेंडर की जगह एक सिलेंडर दिया जाता है और जब सिलेंडर खत्म हो जाता है, तब वह 800 रुपये कहां से लाए कि वह अपने घर में सिलेंडर का इस्तेमाल कर सके। यह वास्तविकता है और आप गांव की वास्तविकता देखिए।

हम कहते हैं कि हम सब पोलिटिकल लोगों को सोचना चाहिए कि क्या यह ब्यूरोक्रेसी सिस्टम इस कंट्री में सही है? जब हमारी योजनाएं ठीक से नीचे लागू नहीं होती हैं, तो सिस्टम को क्यों नहीं बदल दिया जाता है? हम क्यों अंग्रेजी के सिस्टम को रखे हुए हैं? जो आई.ए.एस. कहेगा, वही होगा। वे हमारे सामने आंकड़े इतने बढ़िया बनाकर ले आते हैं। अब डा. हर्षवर्धन जी आ गए हैं, वे भी पर्यावरण को ठीक कर रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण की क्या हालत है? अमेरिका ने अपने यहां नागरिकों को चेतावनी दे दी कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे। यूनाइटेड एयरलाइन्स ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं। श्रीलंका की टीम मास्क पहनकर हमारे देश में खेलती है। इससे हमारी इमेज कितनी खराब हो रही है। हम अपने यहां का प्रदूषण क्यों नहीं ठीक कर सकते? आपने इतना सेस लगाया है, फिर भी पर्यावरण

[श्री नरेश अग्रवाल]

प्रदूषित हो रहा है। एक एन.जी.टी बन गया है। अगर गांव का बेचारा किसान अपने खेत से मिट्टी निकालने जाए, तो शाम को उसको दरोगा बंद कर देगा। जंतर-मंतर पर इसी वजह से प्रदर्शन बंद कर दिए कि तुम्हारी आवाज़ न निकल सके। यह हमारा न्यू इंडिया है। आप पर्यावरण को ठीक करिए, हम सांस में ज़हर ले रहे हैं। डाक्टर कहता है कि सुबह टहलने मत जाना, क्योंकि टहलने से जितना फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा नुकसान होगा। दिल्ली में डॉक्टर ऐसा कहता है। इससे तो हमारे छोटे गांव अच्छे हैं। कम से कम वहां पर प्रदूषण नहीं है और हमें साफ हवा मिल रही है।

हम रोज सुन रहे हैं कि सीमा पर हमारे सैनिक मर रहे हैं। मैं आज़ाद साहब से सहमत हूं कि कश्मीर इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जब जाधव जी का मामला आया था, तब पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा हुआ था। पूरे विपक्ष ने साथ दिया कि आप मजबूती से चलिए। सुषमा जी बोल रही थीं कि आप लोग कुछ comments मत करिए, यह international matter है। उस international matter में क्या हुआ? क्या जाधव की रिहाई हो गयी या पाकिस्तान की जेलों में सैंकड़ों बंद और हिंदुस्तानी, जिनका नाम पता नहीं मालूम, उनकी रिहाई हो गई? पाकिस्तान रोज हमारे सैनिकों को मार रहा है। आपके 4 साल के शासनकाल में अब तक 800 सैनिक शहीद हो चुके हैं। इतने तो युद्ध कर देते, तो भी शहीद नहीं होते और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होता। ...(**व्यवधान**)... surgical strike क्या थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जब तक पाकिस्तान में मिलिट्री से बात नहीं करोगे, वहां के नेताओं से वार्ता करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की सरकार मिलिट्री चलाती है। वहां आप चाहे साड़ी ले जाओ, चाहे बिंदी ले जाओ, उस से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कड़े होइए। चीन हमारा दुश्मन है, नेपाल हम से भागा जा रहा है, रशिया हमारा दोस्त था, लेकिन ट्रम्प के चक्कर में रशिया भी भाग गया वरना रशिया ने तो हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है। जब अमेरिकी बेड़ा आया था, तो रशिया ने अपना बेड़ा हिंदुस्तान की मदद के लिए भेजा था। यू.एन.ओ. में अगर कोई देश हिंदुस्तान के पक्ष में वीटो करता था, तो सिर्फ रशिया करता था। आज चीन पाकिस्तान के पक्ष में वीटो कर रहा है। हम कहते हैं कि यह कह दो कि पाकिस्तान आतंकवादी है, तो चीन वीटो लगाता है कि नहीं ये आतंकवादी नहीं है। आप sanction नहीं लगा सकते। वहां कौन है, जो हमारे लिए वीटो लगाएगा, आप उसका नाम बता दीजिए? आपने कश्मीर में 9 हजार से अधिक पत्थरबाजों को छोड़ दिया। कल एक वीडियो वायरल हुआ है और सेना के जवानों के साथ वहां जो व्यवहार हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर देश की सेना demoralise हो जाएगी, तो देश खत्म हो जाएगा। हमें अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना विश्व की सब से अच्छी सेना है। हिंदुस्तान का कोई वीर सपूत कमजोर नहीं है, देश पर कुर्बान होने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जुमलों में कुर्बानी मत कराइए, जुमलों में बात मत करिए। यह देश एक मजबूत हिंदुस्तान चाहता है। आज चीन जिस तरह विश्व की महाशक्ति बन रहा है, आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी।

आपने एक nation एक election की बात कह दी। हम तैयार हैं, लेकिन योगी बाबा तैयार हैं कि नहीं? आप साल-दो साल बाद चुनाव करा लो - यू.पी. में भी करा लो, गुजरात और हिमाचल के भी करा लो। यह कैसे होगा? जब तक आप Constitution में परिवर्तन नहीं करेंगे कि State Assembly पांच साल तक भंग नहीं होगी, तब तक one nation, one election कभी नहीं हो सकता। अगर

Assembly भंग होगी, तो आगे चुनाव फिर बीच में होने लगेगा। अभी जैसे यहां President rule नहीं होता, वैसे स्टेट में भी कोई President rule नहीं हो। जब पांच साल तक चुनी हुई सरकार चलेगी, तभी आप one nation, one election की बात कर सकते हैं। मुझे याद है, इंदिरा जी के जमाने में मध्य प्रदेश से सेठी जी आते थे, उन्होंने अमेरिकन सिस्टम वाली बात चलायी और वह बहुत जोर से चली कि अमेरिकन सिस्टम पर हिंदुस्तान में चुनाव होने चाहिए यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो, बाकी के न हों।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): वसंत साठे जी ने कहा था।

श्री नरेश अग्रवाल: नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर सेठी जी ने भी यह मुद्दा उठाया था।

श्री डी.पी. त्रिपाठी (महाराष्ट्र): यह बात वसंत साठे जी ने शुरू की थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल: राजीव जी, जब मैं कांग्रेस में adult हो गया था, तब आप कक्षा 5 में पढ़ रहे होंगे।

श्री राजीव शुक्ल: अभी आप ज्यादा adult हो गए हो, कभी-कभी भूल जाते हो।

श्री नरेश अग्रवाल: आपने काले धन की बात कही और नोटबंदी से हमें क्या मिला? आज तक रिजर्व बैंक बता नहीं पा रही है कि नोटबंदी से क्या मिला? उस बारे में फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है क्योंकि रिजर्व बैंक अभी तक कुछ बता नहीं पा रही है कि क्या हुआ? वे 99 परसेंट स्वीकार कर रहे हैं और हमें लगता है कि 101 परसेंट हो गया है क्योंकि नकली नोट कहां हैं? वे तो हैं ही नहीं। अभी कानपुर में 93 करोड़ रुपए पकड़े गए। पता नहीं, देश में ऐसा कितना धन होगा? पता नहीं, नेपाल हमें कितना रुपया देगा? वे नेपाल से उसको white करना चाहते थे। आपने को-ऑपरेटिव बैंक से कितना लिया, अभी आपको पता नहीं है। अभी अमित शाह भी कह रहे थे कि हमने काला धन समाप्त कर दिया, तो कहां था कालाधन, जो सफेद कर दिया? ...(**व्यवधान**)... काला धन स्विटज़रलैंड बैंक में था। काला धन सिंगापुर, पनामा और दुबई में है। आपने विदेशों से काला धन लाने की बात की थी। आजकल सोशल मीडिया पर एक लिस्ट आई थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के सब लोगों के नाम दिए गए थे कि किसके नाम पर कितना काला धन है और किस बैंक में जमा है। आप यह काला धन बंद करिए। आप इस देश को प्लास्टिक मनी से नहीं चला सकते हैं। आप यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैंने बिटकॉइन को तो उठाया था, लेकिन चला नहीं, बैन कर दिया। जिस देश की आबादी तीन परसेंट इनकम टैक्स देती हो, तो आप उस देश को प्लास्टिक मनी पर ले जाना चाहते हैं। आपने 67 हजार और बढ़ा दिए, जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। इस 125 करोड़ के देश में आपने 67 हजार बढ़ा दिए, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? आपने अपने अधिकारियों को जितनी छूट दे रखी है, इसको बंद करिए। कांग्रेस पार्टी के चिदम्बरम जी भी कानून बनाते थे, लेकिन उनके बेटे पर ही वह कानून लग गया। मैं उनको कहता रहा कि यह मत समझो कि हम लोग ही सब कुछ हैं। अब वे कह रहे हैं कि हमारे बेटे पर कानून लग गया और भागे-भागे कोर्ट गए, ऐसे ही आपका हाल है। आप जितने भी फाइनेंस के बिल ला रहे हैं, उनमें किसी में सात साल की सज़ा है, किसी में पांच साल की सज़ा है और किसी में तीन साल की सज़ा है। अब तो आपने अधिकारी तक को सजा के लिए अधिकार दे दिया है कि वह किसी को भी पकड़ कर बंद कर दे। अब भ्रष्टाचार बढ़

[श्री नरेश अग्रवाल]

गया और यह भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया है। आप अपने मन की यह गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, यह तो चार गुना बढ़ गया है। कानपुर में GST कमिश्नर पकड़े गए हैं। आप कितने कमिश्नर पकड़ोगे? आपने सब काम अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया। अरुण जी वकील हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं? हर जगह जेल-जेल, आपने रीयल एस्टेट में भी जेल कर दिया है। हमने तो इसको अपोज़ किया था, लेकिन लोग समझने लगे कि यह रीयल एस्टेट का आदमी है, यह तो बिल्डिंग बनाता है। हमारा सबसे ज्यादा विरोध शैलजा जी कमेटीज़ की मीटिंग्स में करने लगीं, तो हमने इनसे कहा कि हम बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं। आप यह गलतफहमी मत रखिए, लेकिन रीयल एस्टेट ने देश में 12 करोड़ लोगों को नौकरी दे रखी थी। उसने कोई पकौड़े वाली नौकरी नहीं दे रखी थी। अगर कोई एक प्लॉट बेचता था, तो एक साल तक उसके घर का खर्च चलता था। लोग पूछते थे कि क्या काम करते हो? शादी के समय पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है? आप कहेंगे कि लड़का पकौड़ा बेचता है, तो कोई शादी भी नहीं करेगा। यह कोई शादी के समय कहता कि मैं रीयल एस्टेट का काम करता हूं, तो कम से कम उसकी शादी तो हो जाती। आपने तो वह सब भी खत्म कर दिया।

आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हर साल एक लाख महिलाएं kidnap की जाती हैं, लेकिन आपने 67 हजार की फिगर दी है। वे इसलिए kidnap की जाती हैं कि उनकी जबरदस्ती शादी कराई जाती है। सबसे ज्यादा बिहार में जबरदस्ती शादी कराई जाती है। वहां पर तो लड़के की शादी भी जबरदस्ती लट्ठ के जोर पर कराई जाती है और लड़की की शादी भी लट्ठ के जोर पर कराई जाती है। ऐसे दूल्हे को पकड़वा दूल्हा कहा जाता है। लड़की का बाप जबरदस्ती लड़के को उठाता है और लट्ठ के दम पर शादी करवाता है, यह पकड़वा दूल्हा कहलाता है। यहां पर राम कृपाल यादव जी बैठे हैं और हंस रहे हैं। राम कृपाल जी, आप खुद ही इसके गवाह रहे हैं और आपने बहुत सी ऐसी शादियां अटेंड भी की हैं। एक दिन हमें ही बता रहे थे, आज चुप हैं। अरे सत्यता बोलो, सत्यता बोलोगे तो लोग खुश भी होंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि नीरज जी को भी बोलना है, हमारी पार्टी का टाइम सिर्फ 53 मिनट है और अभी 35 मिनट हो गए हैं, इसलिए कितना टाइम बचा हुआ है?

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): अभी आपके 17 मिनट बचे हुए हैं।

श्री नरेश अग्रवाल: इन्हें भी बोलना है। चूंकि अभी बोलना बहुत है और मेरे ख्याल से सभी लोग सुनना भी खूब चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मेघराज जैन (मध्य प्रदेश): आप एक घंटा बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल: चलिए, जैन साहब रिटायर होने से पहले आपने पहली बार हमारी तारीफ तो की। हमने कहा, हमारी तारीफ क्यों नहीं करते हैं? हम तो एवर ग्रीन हैं, हम तो हर वक्त हँसते रहते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, न दौलत छाती पर ले जाओगे, न कोई चीज़ मिलने वाली है। आज जो संस्कार हो गए हैं, उनमें अगर बेटा साल में फोटो पर एक बार माला चढ़ा दे, तो समझ लीजिए कि वह बड़ा लायक हो गया है। बूढ़े-बूढ़ियों का जो हाल इस देश में हो रहा है, उसके लिए अब सोचना बंद कर दो। खैर, प्रमोद जी तो अकेले हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, फ़र्क नहीं

पड़ता। बूढ़े-बूढ़ियों का जो हाल हो रहा है, वृद्ध आश्रमों की जो हालत हो गई है, उस संदर्भ में तो जापान और चीन से ज्यादा बुरी हालत हिंदुस्तान की हो गई है। जब मैंने रेमंड के मालिक के बारे में सुना, तो रेमंड का सामान खरीदना बंद कर दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right.

श्री नरेश अग्रवालः मैं अभी खत्म कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि रेमंड के मालिक ने अपना सब-कुछ बेटे को दे दिया। ऐसा बाप, जिसने बेटे को 8,000 करोड़ रुपये दे दिए हों, उसको घर से निकाल दिया। उसे रहने के लिए मकान ही नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा कानून बनाइए कि अगर लड़का पैदा हुआ है, तो माँ-बाप की देख-रेख करने की उसकी जिम्मेदारी है। घर में चार रोटी हों और पाँच खाने वाले हों, तब अगर कोई भूखा रहेगा, तो माँ भूखी रहेगी, दूसरा कोई भूखा नहीं रहेगा। यह इस देश का कॉंसेप्ट है। आज जो स्थिति हो रही है, उसको देखने के लिए आप वृंदावन चले जाइए, बनारस चले जाइए, वहाँ क्या स्थिति है? अब ऐसा बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी होना शुरू हो गया है। यह जो स्थिति है कि लड़का जब तक कुंवारा अपना और शादी हुई तो जानिए गया, अब यह स्थिति आ गई है। महोदय, आप ऐसा कानून बनाइए, ऐसा बिल लाइए, जिससे देश के उन बुजुर्गों को, जिनकी सीनियर सिटिजन्स की उम्र हो गई है, उनको भी अपनी लाइफ की सिक्युरिटी मिल सके, सेफ्टी मिल सके और हिंदुस्तान जो था, वह फिर से वैसा ही हिंदुस्तान रहे। अगर गलतफहमी के शिकार रहोगे, तो नुकसान होगा, क्योंकि हमने बड़ी-बड़ी सत्ताएँ परिवर्तित होती देखी हैं। हमने चालीस साल के जीवन में उठा-पठक देखी है, जोड़-तोड़ करने में बड़े माहिर हैं हम। इस देश में "नरेश फॉर्मूला" भी चलता था। कल्याण जी की सरकार हमने ही उस समय बनवा दी थी, नहीं तो बनती नहीं, इसलिए आइए, बड़ा दिल करिए और अटल जी, जो कह गए थे, उस संदर्भ में लास्ट में इतना ही कहूंगा कि,

"छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।"

अटल जी ने ये दो लाइनें कही थीं। बीजेपी को अगर जिंदा किया तो अटल जी ने जिंदा किया, आडवाणी जी ने जिंदा किया। कम से कम कहे शब्दों को ही याद कर लीजिए, आपका बहुत भला होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Nareshji and thank you also for injecting a little bit of humour into the debate.

SHRI NARESH AGRAWAL: Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Well, hon. Members, I have to inform you that hon. Chairman has already said that Parties will not be given more time. Parties have to adhere to their time and, therefore, the first speaker should keep in mind that there will be a second speaker or third speaker.

श्री नरेश अग्रवालः उपसभापति जी, मेरी एक आपत्ति है। हम लोग इस चेयर की गरिमा नहीं गिरने देना चाहते हैं। आप बारम्बार कहते हैं कि चेयरमैन साहब ऐसा कह कर गए हैं, इस वजह से ऐसा करना है। आपके पास अधिकार हैं, इस देश में अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जब आपको नियमों में सब अधिकार दिये हैं, तो आप इस्तेमाल कीजिए। आप चेयर हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I only quoted. ...*(Interruptions)*... No, no. I only quoted. ...*(Interruptions)*... I only quoted. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवालः आप हमें अभी बिठा दीजिए, हम सब नियम अभी बदल देंगे। हम तो माहिर हैं नियम बदलने में। आप हमें बिठा दीजिए, हम सभी नियम अभी बदल देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I was quoting the hon. Chairman. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Before that, Sir, I have a point for clarification. It is true that the time has been allocated for this debate and for the Budget. But, now, every time when the discussion is there, there are occasions when many minutes are lost for either Party because of interruptions. Even if that is not Intentional, that happens. So, there is a spill-over effect. The second thing is that the debate will conclude on Wednesday as we have been informed. Now, on behalf of my party and on behalf of our colleagues in the Opposition...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. ...*(Interruptions)*... Please listen. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: We want to make one thing absolutely clear. Last time also it happened that the Government said that the debate would conclude the previous day and on the next day only the Government, the Prime Minister will speak. This will not be acceptable to us. If the reply is on Wednesday then the debate spills over to Wednesday. They will have to listen to some of us and then give the reply. It cannot be otherwise. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's okay. ...*(Interruptions)*... I have no objection to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: I am saying it in all seriousness. आप बताइए, कैसे होगा?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no objection to that.

श्री आनन्द शर्माः आप चेयरमैन साहब को बता दें, वरना हाउस का सेंस ले लें। ...(**व्यवधान**)... ऐसे नहीं होगा। इतनी बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं, उनका जवाब तो देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no objection to that. But, I am only saying that twelve hours is the time allotted. We sit up to 8.00 p.m. today and tomorrow up to 8.00 p.m. By then, twelve hours' time will be over. So, tomorrow by 8.00 p.m., the discussion has to be over because by that time it will be twelve hours.

SHRI ANAND SHARMA: No, no, Sir, we are very clear on that that if the reply is on Wednesday, then, I speak not only for myself but for the Opposition colleagues also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, this is for the Government... *...(Interruptions)...*

SHRI ANAND SHARMA: It has to be then there. The Government is here; the Ministers are here. It has to be a level playing field. We do not want it and I have reasons for that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understood your point. *...(Interruptions)...* I understood your point.

SHRI ANAND SHARMA: I will also be very transparent because the Government always has the advantage. Naturally, the President of the Ruling Party moves the Motion which is his right, very good. So, the message which goes to the people, and even in the media, the space gets restricted for the criticism of the Government. On the final day, it is hundred per cent only of the Government and what others have to say in response, as the debate evolves, that cannot be frozen. And, that will not come. Then, the hundred per cent space goes one way. We will not accept that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; every party will get its due time. Now, Shri A. Navaneethakrishnan.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, I thank the hon. President for having delivered the speech in the Joint Sitting of both the Houses of Parliament. Since, I am hailing from Tamil Nadu, I would like to draw the kind attention of this august House; also of the Central Government and especially, of the hon. President to a burning issue because, now, the young students of Tamil Nadu are preparing for the Plus-II examinations. At the same time, they are worrying about the NEET examination. Now, as per law, NEET has been enforced. I would like to draw the kind attention of the Central Government and also kind attention of the hon. President to this issue.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair]*

At the same time, I thank our senior Member, Shri T.K. Rangarajan who has done a wonderful and a brilliant thing and, that is, writing to the office of the President to know about the status of the Bill passed by the Tamil Nadu Legislature seeking exemption from NEET. For that letter written by our hon. senior Member, Shri T.K. Rangarajan, the President's office has given a reply that the President's Office did not receive the Bill passed by the Tamil Nadu Legislature. Now, I want to raise this issue and I would also like to draw the kind attention of the Parliamentary Affairs Minister to this because this is concerning about the powers in the jurisdiction of the Central Government and also the exclusive jurisdiction and domain of the hon. President. My humble submission would be my reading of Articles 52, 53, 73, 74 and its provisos, Articles 246 & 254 of our Constitution. It is very clear. I am not accusing the Central Government. But I am urging the Central Government to take note of the mental agony of our Tamil Nadu students which they are undergoing. Now from the reply given by the hon. President of India to our colleague, Shri T.K. Rangarajan it is very clear. The Bill passed by the Tamil Nadu Legislature unanimously is the will of the people of Tamil Nadu. The Bill has been passed not without any legislative competency. The Concurrent List empowers the Tamil Nadu Legislature to pass a law on the subject of education. Though the Tamil Nadu Legislature has the jurisdiction, competency to pass a law which is included as one of the subjects in the Concurrent List, of course, that law now passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly is a repugnancy to the law passed by the Indian Parliament, namely, the Indian Medical Council Act, Section 10 (D). To resolve the repugnancy, there is a provision in the Constitution; it is unknown to anybody but it is known to the Central Government. I request the Central Government, and urge the Central Government to kindly go through it. It is my humble request only to save the young students of Tamil Nadu. Last year a bright young girl had committed suicide. It attracted the attention of the whole world because she had secured more marks, in the State Board Exams but she did not secure more marks in NEET. It is a very sensitive matter and involves future of young students.

In the light of my reading of the Indian Constitution, what now appears is the inaction on the part of the Central Government and inaction on the part of the hon. President. It causes violation of the Indian Constitution. How? What is vested with the hon. President is the Executive power of the Union of India. So, the hon. President is the head of the Executive of the Union of India. So, he discharges the Executive powers of the Union of

India under the seal of the President. As per Article 74 the aid and advise of the Council of the Ministers come into the picture only with regard to the matters of Executive powers of the Union. So, for the executive powers of the Union alone the President is bound by the aid and advise of the Council of Ministers headed by the hon. Prime Minister. But this is a matter in which the Tamil Nadu State Legislature has enacted a law. It concerns the subject included In the Concurrent List. So, legislative competence can't be faulted, it has got full competence to enact the law that too unanimously passed.

Now, as per Article 254 "Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States, clause (2) says, "where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to the matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State."

In this connection, I would like to draw the kind attention of the Central Government to clause 2, "Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting any time any law with respect to the same matter including a law adding to amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State." So, my humble submission would be, the power conferred upon the hon. President under article 254 is not within the purview of 'aid and advice of the Council of Ministers headed by the hon. Prime Minister'. It is an independent power vested with the hon. President because the Legislature's power, especially those of the Tamil Nadu Legislature, cannot be exercised by the Central Government. That is very clear. So, the Central Government's power is only executive; it is not judicial or legislative and, there too, the legislative power of the State Government, namely the Government of Tamil Nadu, cannot be taken'over by the Central Government. So, what is being contemplated, according to me, with due respect to the Office of the hon. President, the hon. President has no say here. If the Bill has been reserved for his assent, he must give assent to it. Then, it is up to the Central Government to introduce another law to amend or to do anything else in the Parliament. So, my humble submission would be, the power of the Tamil Nadu Legislative Assembly has been now taken over; it has been bypassed, ignored; and, further, by keeping the Bill that has been reserved for the assent of the President by the Central Government, the Parliament has also been bypassed. So, my submission would be that the Concurrent List is not a mere paper. It doesn't mean that the law passed by the State Legislature can be kept with the

[Shri A. Navaneethakrishnan]

Secretaries of the Central Government without forwarding it even to the President of India. My humble submission is that the entire Concurrent List now stands deleted because even as per Article 254, If there is any repugnancy, then the Central law would prevail. That doesn't mean that you can ignore the entire Concurrent List; by deleting the Concurrent List, you are taking away the powers of the State Governments. This is a very serious issue. You are violating the very basic features of the Constitution. Now, even the Court cannot decide upon a law competently passed by the Legislature or Parliament. Now, the Tamil Nadu Legislature has passed a law seeking exemption from appearing in NEET Examination. If it is repugnant to the Central law, it is permissible under law; wherever repugnancy arises, a Bill must be sent to the President for his assent and the President has to give his assent; only then, it must be taken over by the Central Government to consider whether a Bill could be Introduced to amend, vary or to nullify the Act passed by the Tamil Nadu Legislature. This is the scheme contemplated in our Constitution, but you are bypassing the Parliament, the Tamil Nadu Legislature and also the Office of the President of India. The principle of seeking the aid and advice of Council of Ministers, headed by the hon. Prime Minister is not applicable to the law passed by the Tamil Nadu State Legislature, that too, on a subject that is included in the Concurrent List. So, the repugnancy can be resolved only by the Parliament passing the law, not by withholding the files in Central Government offices. I am not accusing or blaming the Central Government. This is the practice that has been going on since Independence. So, I cannot blame anybody. We have to blame our own fate! So, my submission is that we don't want to witness suicides of young students in this current academic year. Parliament alone can pass the law, not the Central Government or the State Government. So, the Tamil Nadu Legislature has unanimously passed a valid law. It is entitled to pass a law which is repugnant to the Central law. Now, the Tamil Nadu Legislature has passed a law which is repugnant to the Central law. It has legislative jurisdiction and competency. So, having passed a Bill, -- it is only an administrative procedure to forward to Central Government. Even now, I humbly urge the Central Government to forward the Bill to the hon. President, and the hon. President must bound to give the assent, and then only, the Central Government can examine the issue thereafter. Its jurisdiction ends there as soon as the Bill is introduced here, to vary, amend, abrogate or to do anything. Then, it is a matter within the domain or jurisdiction of the Parliament, Parliament alone can say that the Bill passed by the Tamil Nadu Legislature is not valid. The Concurrent List is now deleted by the Central Government which is a basic feature of the Constitution. Without a Concurrent List, our

Constitution cannot exist. The BJP is full of intellectuals. There is no doubt about it. By force of habit, all the files containing Bills or proposals which will be repugnant to the Central Law, are kept aside, without doing anything, or, for which assent is refused. My humble submission would be, it is a very, very serious matter pertaining to the young people of Tamil Nadu. Long back, in our State, the entrance examinations have been abolished by passing an Act. That Act has been upheld by the Supreme Court. Of course, now, the Parliament has enacted Sections 10C, 10D of the Indian Medical Council Act. But, at the same time, I would like to draw your attention to the fact that the Central Government has announced that more colleges would be established in Tamil Nadu, but they are yet to be established. For AIIMS, NEET is not applicable. AIIMS is conducting their own examinations. AIIMS is at a higher level. Students joining the AIIMS are very bright and brilliant. Likewise, NEET is not the deciding test to assess the capability, intelligence, hard work, or, the aptitude for service in the rural areas. Learning process is a continuous one. By one single test, you cannot assess the capability of the student. That is not the right method. One can acquire knowledge slowly. What is the concept of inclusive growth? If a student is very poor, he should not be left to be poor forever! That is not the concept of the inclusive growth. Social justice is being denied to the poor students. The competitive edge is available to the urban students, though, of course, thanks to our Amma, she has protected the poor people, and 69 per cent reservation is in force. So, of course, in spite of the NEET, 69 per cent reservation is in force, is being implemented. But, even in 69 per cent reservation, only the rich, urban people of those respective communities are enjoying the benefits. So, the first generation students hailing from poor, rural background, are not able to reach the medical colleges. That is why, those students who have studied with the help of the Government quota at a lesser cost, as soon as they become doctors, they never go to the rural areas. They confine themselves to the multinational hospitals, corporate hospitals. So, my reading of the constitutional provisions in the Articles is that the hon. President has exclusive domain, jurisdiction to give the assent. Even with due respect to the office of the hon. President, the hon. President is bound to give the assent to the Bill now passed by the Tamil Nadu Assembly because this Bill is to protect the poor rural students. Now, my humble submission would be, don't bypass the Parliament; don't bypass the Tamil Nadu Legislative Assembly; don't delete the Concurrent List from the Constitution. You are violating the principle of the State autonomy, and you are violating the basic features of the Constitution. I am not accusing anybody. I am not blaming anybody. If any law is repugnant to the Central law, it will either be kept under the drawers of the officers or it will not see the light of the day. Or, it

[Shri A. Navaneethakrishnan]

has never seen the light of the day. I have gone through the case law to certain extent. Subject to correction, I would say that the basis of aid and advice given by the Council of Ministers are amenable to the judicial review. The judicial review, which is a basic feature of the Constitution, you are now violating. So, Parliament, the Tamil Nadu Legislative Assembly, the judicial review, the powers of the President, everything is now violated by keeping the files in the drawers of the office of the Central Government.

My humble submission would be, if there is anything on the part of the Government, it is reflected on the President. The President himself, according to me, is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers. It is an independent jurisdiction conferred upon him. This is my humble opinion because what I quoted is a State law which is in the Concurrent List, forwarded under Article 254. Then, the President has to give his assent. The jurisdiction, of course, is vested with the Central Government to introduce a Bill or to deal with that law. Before that, the Central Government can't destroy the Constitution, the legislative powers, the Parliament, the judicial review power as also the office of the President. Now, in Tamil Nadu, young people are agitated because they are not capable of preparing for two examinations simultaneously—one for the NEET and another for the State Board. They are suffering; they are undergoing mental agony.

I very humbly urge the hon. President, through this House, to kindly consider and give his assent as early as possible. Also, I very, very humbly urge upon the Central Government, led by hon. Prime Minister, to consider and give a favourable advice to the President to give assent to the Bill so as to see to it that the law is enforced in Tamil Nadu. Tamil Nadu may please be given an exemption from NEET which is now warranted, which is now necessary.

I thank the President for his Address. I also thank the Central Government for the wonderful schemes they have introduced. Definitely, there will be a New India. There is no doubt about it. ...*(Interruptions)*... I hope, the Bill passed by the Tamil Nadu will be accepted by the Government, I hope, the Central Government will not reverse it.

I thank the Chair and I also thank the hon. Members. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Sukhendu Sekhar Ray.

6.00 P.M.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, although the empty seats are staring at me. ...*(Interruptions)*... My voice is broken.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): There is enough number of Members for the evening session!

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: On my right side, there are empty seats, Sir. Anyway, Sir,

29 जनवरी को संसद के ज्वायंट सेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी ने 20 पन्ने के लिखित भाषण में कम से कम 11 प्रधानमंत्री योजनाओं का उल्लेख किया, जैसे - प्रधान मंत्री उज्जवला योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना, वगैरह-वगैरह। इस तरह उसमें 11 योजनाओं का उल्लेख किया गया। उसमें क्या नहीं है? उसमे टॉयलेट भी है, डिजिटल वॉलेट भी है। उसमें सटार्टअप भी है, स्टैंडअप भी है, लेकिन स्टार्टअप हुआ है क्या?

श्री विजय गोयलः सर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It has already been decided in the Business Advisory Committee meeting that the House will run up to eight o'clock.

श्री सुखेन्दु शेखर रायः सर, मेरा सवाल यह बनता है कि क्या स्टार्टअप हुआ है? आम जनता स्टैंडअप भी कैसे करेगी? क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी के डबल धमाके से जनता की कमर ही टूट गई है, तो वह स्टैंडअप कैसे होगी? इसका कोई तरीका इस अभिभाषण में नहीं बताया गया। जनता न तो यात्रा शुरू कर पायी, न ही खड़ा होने की कोशिश कर सकती है। इस प्रकार से इस अभिभाषण में जो भी बताया गया, वह इस साल कई राज्यों में विधान सभा और अगले साल लोक सभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बताया गया है, इसलिए यह भी एक चुनावी जुमला जैसा है। हालांकि इस अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के मन की बात नहीं कही गई, बल्कि हम हर रविवार को मन की बात सुनते हैं, उसी को इस अभिभाषण में दोहराया गया है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है।

इस अभिभाषण में दो नई चीज़ें बताई गई हैं। पेज संख्या 19 में बताया गया कि simultaneous election होना चाहिए और उसके लिए सदन को विचार करना चाहिए। यह प्रस्ताव कहां से आया? क्या चुनाव आयोग ने कोई ऐसा प्रस्ताव दिया है? क्या Constitution में ऐसा कोई प्रावधान है? संविधान को खोल कर कोई भी हमें दिखा दे कि इसमें इस संबंध में एक भी आर्टिकल है, एक भी प्रोविजन है, जहां पर यह बताया गया हो कि केन्द्र और राज्य का चुनाव एक साथ करना पड़ेगा। यह कहीं नहीं है और सन् 1967 से आज तक शायद ही कभी केन्द्र और राज्य का चुनाव एक साथ हुआ है, तो आप अचानक केन्द्र और राज्य का चुनाव एक साथ कराने के लिए इतना शोर क्यों मचाने लगे? ऐसा इसलिए कि आप संविधान को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण एक

[श्री सुखेन्दु शेखर राय]

नया संविधान बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत खर्च हो रहा है, बहुत समय बर्बाद हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... इसमें समय और खर्च की बात बताई जा रही है। आपने तो डिजिटल इडिया बना दिया, तो आप ऑनलाइन चुनाव करा लीजिए। आप ऑन-लाइन चुनाव करा दीजिए, इससे खर्च बच जाएगा और समय भी बच जाएगा। इसमें महीने भर चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पैरामिलिट्री ट्रूप्स के deployment की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन चुनाव कराइए, डिजिटल इडिया बन गया। ये सारे शोर और नारेबाजी ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं।

अभिभाषण के पेज संख्या 2 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला कि ट्रिपल तलाक बिल संसद में पेश किया गया, यहां भी सुबह बताया गया कि हम लोगों ने उसका विरोध किया। किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, एक भी विरोधी दल ने इसका विरोध नहीं किया। हमारी मांग थी कि इस बिल में कुछ कमियां हैं, इसलिए इसको पहले सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, वहां से scrutiny के बाद उसको यहां वापस लाया जाए, उसके बाद हम इस बिल को पारित करेंगे। यह एक संसदीय प्रणाली है। आप इस संसदीय प्रणाली को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप पहले इसका जवाब दीजिए।

महोदय, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसमें बताया गया कि हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ गया? हमारे पास दो-चार रिपोर्ट्स हैं। UNDP डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के हिसाब से दुनिया के 188 देशों में भारत का स्थान 131वां है। इसका मतलब यह है कि भारत से ज्यादा मानव विकास 130 देशों में हुआ है। हमारे साथ तुलना सिर्फ कांगो, नामीबिया और पड़ोसी पाकिस्तान से किया जा सकती है, दूसरे देशों से नहीं। ऐसा हमारा डेवलपमेंट हुआ है। यहां तक कि हमारे पड़ोसी देश, श्रीलंका और मालदीव भी हमसे आगे है। यह UNDP की रिपोर्ट है, तृणमूल कांग्रेस की नहीं है। World Economic Forum's Inclusive Development Index-2018 हाल ही में निकला है, इसी महीने ही निकाला है। उसके अनुसार six out of ten Indians still live on less than 3.20 dollar per day यानी कि 60 प्रतिशत अर्थात् करीबन 78 करोड़ हिन्दुस्तानी 6 हजार रुपए महीने पर अपना दिन गुजारते हैं। न्यू इंडिया! कौन-से जीडीपी ग्रोथ रेट और एफडीआई की कहानी सुनायी जा रही है?

CIA, हालांकि यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, यह हर साल दुनिया के सारे देशों के बारे में World Fact Report निकालती है। वे तो अमेरिका से बहुत नजदीक हैं, इसलिए उन लोगों को CIA के बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। CIA की रिपोर्ट को लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। CIA की World स्तर की 29 जनवरी, 2018 की रिपोर्ट से पता चलता है कि पहला, संतान पैदा करते समय गर्भवती माताओं की मृत्यु की संख्या के मामले में हिन्दुस्तान दुनिया के 180 देशों में 56वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि मातृत्वकालीन मृत्यु के मामले में हमारे देश की तुलना में दुनिया के लगभग 120 देश हमसे पीछे हैं। हम इतना आगे बढ़ गए हैं। क्या इस तरह हम नारी सशक्तीकरण करना चाहते हैं? दूसरे, बाल मृत्यु के मामले में भारत 133 देशों से आगे है। यहां 35.60 प्रतिशत शिशु, जिनकी उम्र 5

साल से कम है, वे चिन्ताजनक कम वज़न के हैं और कम वज़न वाले शिशुओं की संख्या में भारत का स्थान दूसरा है। वल्लाह, क्या बात है? मैं अल्लाह नहीं बोल रहा हूं, वल्लाह बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

इसके आगे देखिए - Glogal burden of disease published in the medical journal. 'The Lancet' से पता चलता है कि वर्ष 2016 में, भारत में 5 साल से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु संख्या 9 लाख हो गई - क्या यही भारत की प्रगति है? यहां प्रति एक हजार नागरिकों पर एक डॉक्टर की सेवाएं भी नहीं मिलतीं - यह भी CIA की रिपोर्ट है। यहां प्रति एक हजार नागरिकों को अस्पताल में एक भी बैड नहीं मिलता - यह भी CIA की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। भारत में 31 लाख जनता को एच.आई.वी. एड्स है और हम दुनिया में आज तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। CIA रिपोर्ट के मुताबिक 71.5 प्रतिशत ग्रामीण जनता और 37.4 प्रतिशत शहरी जनता को सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलतीं, फिर स्वच्छ भारत का सेस किस आधार पर दे रहे हैं, स्वच्छ भारत का नारा क्यों लगा रहे हैं? इस नारेबाजी करने वाली सरकार को अगले चुनाव में जनता जवाब देगी।

अब मैं थोड़ा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की तरफ आना चाहता हूं। इसके पेज 3 पर कहा गया है- "My Government is committed to doubling of farmers' income by 2022." यही बात बी.जे.पी. के 2014 के इलेक्शन मेनिफेस्टो में भी कही गई है, फिर पिछले चार सालों में किसानों की आमदनी क्यों डबल नहीं हुई- इसका जवाब कौन देगा? इसका कोई जवाब सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया। सिर्फ 2015 में 12,500 से अधिक किसानों ने देश मे आत्महत्या की है। हर रोज़ 35 किसान खुदकुशी करते हैं, on an average. चार साल तक यह सरकार सोती रही और अब जब इसका अंतिम समय आ गया, तो कहते हैं कि हमें 2022 तक का समय दीजिए ताकि हम किसानों की आय डबल कर सकें। अब तक लगभग 40,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यदि इस सरकार को और चार साल की मोहलत मिलती है तो क्या उनकी इनकम दोगुनी हो जाएगी, क्या आप यही कहना चाहते हैं?

महोदय, नीति आयोग के एक वरिष्ठ सदस्य ने इस बारे में क्या कहा है, नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य का वह डाक्यूमेंट मेरे पास है, यदि आप इजाजत दें तो मैं उसे टेबल पर भी रख सकता हूं। यह Economic Times की 31st January, 2018 की बात है, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के दो दिन बाद, नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी का उसमें एक guest column निकला, जिसमें उन्होंने कहा, and I quote "MSP is notified for 23 crops but effectively ensured only for two-three crops." क्या यह फैलेसी नहीं है कि जब 23 फसलों के लिए एम.एस.पी. डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन सिर्फ दो-तीन फसलों के लिए उसे इम्पलिमेंट किया जाता है? किसानों के साथ इससे बड़ी धोखेबाजी की बात क्या हो सकती है? He says, "MSP does not generate reasonable surplus (income) for the farmers." नीति आयोग के एक अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं। He says, "MSP does not generate reasonable surplus (income) for the farmers" नीति आयोग के अधिकारी बोल रहे हैं, "MSP does not generate reasonable surplus (income) for the farmers. Not surpsisingly, farmers have been demanding effective implementation of MSP for all the crops and keeping MSP 50 per cent higher than cost." It was published in the Economic

[श्री सुखेन्दु शेखर राय]

Times. मेरे पास Economic Times है, इसको मैं आपकी इजाज़त से टेबल करना चाहता हूं। सर, इसमें भी jugglery होती है और इसमें fallacy भी है। जैसे कि इसमें एक मैकेनिज्म है। CACP ने जो मैकेनिज्म अपनाया है, उसके नियम के अनुसार, दो तरह से कॉस्ट असेस्मेंट होती है - कॉस्ट ए-2 और कॉस्ट-2, कॉस्ट ए-2 फॉर्मूला के अनुसार, फसल उत्पादन के लिए सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर, केमिकल्स, ह्यूमन लेबर, bullocks, मशीन लेबर, इरिगेशन एक्सपेंसेज़, मेंटनेंस कॉस्ट आदि कॉस्ट ए-2 में आते हैं। अगर एमएसपी, कॉस्ट ए-2 + फैमिली लेबर, यानी किसान के परिवार, जो श्रम देते हैं, उसको भी जोड़ते हैं, तो उसके ऊपर अगर 50 परसेंट एमएसपी रेट रखा जाएगा, तभी वह लाभदायक होगा, नहीं तो वह लाभदायक नहीं होगा। अभी तक यह खुलासा नहीं किया गया है। हमने बजट को सुना और पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं भी यह नहीं बताया गया कि एमएसपी किसके आधार पर तय किया जाएगा, कॉस्ट ए-2 के आधार पर या कॉस्ट-2 के आधार पर अगर कॉस्ट ए-2 है, तो यह भी एक धोखेबाजी है।

सर, अभिभाषण में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का उल्लेख किया गया है। देश भर में, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, हवाई अड्डा हो, सड़क हो, जन-सुविधाएँ हों, हर जगह हम "स्वच्छ भारत" और "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" के विशाल-विशाल बिल बोर्ड्स देखते हैं। इस अभिभाषण में भी बताया गया, लेकिन अच्छे दिन की बात अब नहीं बोली जाती, वह गीत पुराना हो चुका है। हाल में, प्रधान मंत्रीजी Annual Davos World Economic Forum की मीटिंग में गए थे। जब तक प्रधान मंत्री जी वहाँ पहुँचे, तब तक International Rights Group, जिसे Osfam कहा जाता है, उस Oxfam की रिपोर्ट निकली। उसमें जो बताया गया, उसको मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं। उसमें बताया गया - 'India's richest one per cent garner 73 per cent of the total wealth generated in the country in 2017.' सत्ता में इनके आने के तीन साल के बाद हिन्दुस्तान का यह चेहरा है कि 2017 में जो 73 परसेंट वेल्थ जेनरेट हुई, वह एक परसेंट के कब्जे में चली गयी, तो यह "सबका साथ, सबका विकास" नहीं है, बल्कि यह एक परसेंट के साथ एक परसेंट का विकास है।

सर, इस अभिभाषण में काले धन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। किसी नागरिक ने प्रधान मंत्री जी के दफ्तर में एक आरटीआई ऐप्लिकेशन भेजी थी। वे साल भर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास घूमते रहे, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसमें पूछा गया था - यह बताया जाए कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन सरकार के पास आया? एक साल बीत गया, लेकिन उस आरटीआई ऐप्लिकेशन का जवाब आज तक नहीं मिला है। यह भी गैर-कानूनी है, पेनल्टी होनी चाहिए थी। यह किसने बोला था कि अगर हम विदेश से काला धन लाकर गरीब जनता के खाते में 15-15 लाख रुपये नहीं जमा करते हैं और अगर नोटबंदी का शुभ फल छः महीने में नहीं मिलता है, तो हम चौराहे पर खड़ा होने के लिए तैयार हैं? यह किसने बताया था, यह मैं नहीं बोलना चाहता। मैं याद दिलाना चाहता हूं। पहले तो Panama Papers निकला, जिसमें 500 से अधिक हिन्दुस्तानियों का नाम आया, फिर पिछले साल Paradise Papers में 900 से अधिक नाम आए। ये लोग स्वर्गवासी तो नहीं है! Paradise Papers में नाम निकल आया, इसका मतलब ये स्वर्गवासी नहीं हैं, ये भारत में हैं। ये लोग पैराडाइज़ में नहीं रहते हैं। अगर हिम्मत है, तो व्हाइट पेपर निकालिए

और बताइए कि पनामा पेपर्स और पैराडाइज़ पेपर्स में जिन हिन्दुस्तानियों का नाम आया है, हमने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की है। जनता को आप खुलासा कीजिए। हिन्दुस्तान की जनता जानना चाहती है कि सरकार क्यों खामोश है? White Paper निकालिए, हमारी यह मांग है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBNESWAR KALITA): Mr. Sukhendu Sekhar Ray, you have one more speaker.

SHRI SUKHENDU SEHKAR RAY: Don't worry, Sir. We are okay.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Don't worry, Sir.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: You need not worry, Sir. We will adjust among ourselves.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBNESWAR KALITA): Fine.

श्री सुखेन्दु शेखर रायः पी.एस.यू. बैंक के एन.पी.ए. के बारे में इस अभिभाषण में एक भी शब्द नहीं बताया गया। जो कि अब यह एन.पी.ए. 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया होगा। अगर सरकार में हिम्मत है तो willful default को criminal offence ऐलान करे, कानून में बदलाव लाएं, wilful default का मतलब क्या है? मतलब capability है, फिर भी वे बैंकों को पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। According to criminal law, this is a breach of criminal trust and cheating. So, both breach of criminal trust and cheating come under the purview of criminal law. आप आई.पी.सी. को चेंज कीजिए, आप Cr.PC को चेंज कीजिए और उनके खिलाफ criminal proceedings कीजिए, special court बनाइए। अगर हिम्मत है तो आप छू नहीं सकते, क्योंकि यह सरकार crony capitalism की सरकार है, किसानों की, गरीबी की, मजदूरों की सरकार नहीं है।

सर, रोजगार के बारे में बड़े-बड़े शब्द कहे गए हैं, लेकिन survey data of the Centre of Monitoring Indian Economy के अनुसार नोटबंदी के कारण 2017 के पहले चार महीनों में 15 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। This is the report of the survey data of the Centre for Monitoring Indian Economy, 2017. पिछले साल सिर्फ चार महीनों में 15 लाख बेकार। नोटबंदी के कारण अब तक न जाने कितने बेरोजगार हुए होंगे। ऐसा वे बता रहे हैं, हम नहीं। तो यह जुमले का फसाना है। हमने एक पुराना गीत सुना था, मुकेश जी का। "मेरा नाम जोकर" फिल्म के लिए शंकर जयकिशन का धुन और शैलेन्द्र जी ने लिखा था। "कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना"। यह हकीकत से दूर ऐसा एक फसाना है, जो कि जुमला भरा हुआ एक फसाना है। लेकिन देश की जनता इसमें फंसना नहीं चाहती है।

सर, मैं खत्म करने वाला हूं। कल मेरे लीडर देरेक ओब्राइन जी बोलेंगे। सर, आदरणीय वित्त मंत्री जी, जब 2014 में अमृतसर में चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर उन्होंने IT ceiling के बारे में कुछ बोला था, इसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पी.टी.आई. की रिपोर्ट है, अगर चाहते हैं तो मैं उसको टेबल कर सकता हूं। उन्होंने बोला था कि IT ceiling 2 लाख से 5 लाख करनी पड़ेगी। इससे तीन करोड़ जनता

[श्री सुखेन्दु शेखर राय]

को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर IT ceiling नहीं बढ़ती है तो trade or industry बर्बाद हो जाएंगी और इसी कारण चाइना और थाईलैंड भारत से आगे बढ़ गए। हालांकि वहां के चुनाव में आदरणीय वित्त मंत्री जी हार गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने 50 हजार तो सीलिंग बढ़ायी थी, उसके बाद एक पैसा भी नहीं बढ़ाया और इस बार भी नहीं बढ़ाया। यह भी आधी हकीकत, आधा फसाना है। सर, वित्त मंत्री जी ने जो कुछ भी बोला तो बोला। लेकिन अभी देश में cow vigilantism शुरू हो गया, देश में लव जेहाद शुरू हो गया। इस पर एक शब्द भी इस अभिभाषण में नहीं है। हमारे बंगाल के एक मजदूर को राजस्थान में कुठार से मारा गया और उसके बाद उसको जिंदा जलाया गया। उसकी तस्वीर social site पर दिखाई गई। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको सोशल साइट पर नहीं दिखाना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसे social sites पर दिखाया जाए ताकि सारी दुनिया देखे कि हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... क्या यह नया भारत है? गौरक्षा के नाम पर यहां हर रोज हत्याएं हो रही हैं। क्या हम Republic of India में रहते हैं या ...(**व्यवधान**)... Republic of Cow में हैं? क्या हम citizens of Republic of India हैं या citizens of Republic of Cow हैं, यह सवाल उठता है?

सर, अंत में मैं कैफी आज़मी साहब की चंद लाइनें कहना चाहता हूं जिन्हें हेमन्त कुमार ने अपनी धुन में 'अनुपमा' फिल्म में गाया था।

"इक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए।
माना हम तुम्हें कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वह सहने दो।
क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं,
बहते हैं आंसू और बहें, अब इतनी तसल्ली रहने दो,
या दिल की सुनो दुनिया वालो, या मुझको अभी चुप रहने दो।
मैं ग़म को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो।"

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, I rise to thank the President who was kind enough to address both the Houses in the Central Hall. I have some differences with the President's speech on which I have given amendments which I will explain later.

Our President Address contained a lot of statistics about the performance of our Government. The *Economic Times* in its editorial headlines stated, "President Kovind or Economic Survey.' The former Finance Minister — he does not belong to the Opposition; he was a former BJP Finance Minister — Shri Yashwant Sinha gave the opinion earlier that this Government is presenting a "Made to order statistics." I thought Shri Amit Shah would have replied to him. It is a "Made to order statistics." What you presented in the House, it was 'Made to order.' It is not the reality which I don't say. Mr. Yashwant Sinha has gone on record.

While I am leaving these statements for the House to judge, let me bring to the attention of the House how realities are way away from the assertions made in the President's observation.

My friend, the hon. Member, Shri Navaneethakrishnan, spoke on NEET that how Tamil Nadu Government unanimously passed a Resolution. It was sent to the President. Actually, one Minister, the Central Minister, came to Chennai. She assured that 'we will try to get you one year extension.' Then only they passed it in the Assembly. After it was passed, I thought it will go to the President. Then I wrote a letter to the President. The President replied to me, The Home Ministry did not send me the Bill.' See, whether it is NEET or anything else, it is not just Tamil Nadu. Throughout India, the rural population cannot write that examination whether it is Bengal or whether it is Gujarat or whether it is U.P. Tamil Nadu only started expressing that feeling. Sir, take Jallikattu. You treat Tamil Nadu always differently. Again, Jallikattu is a problem. Our hon. Minister went to Madurai and assured the people that Jallikattu will be allowed. Then they said, "You will not be allowed."

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Cooperative Federalism!

SHRI T.K. RANGARAJAN: That is a part of cooperative federalism. So, not just we, even your own allies in the NDA, the Shiv Sena and the Telugu Desam Party, are unhappy with you.

Sir, I would now like to draw your attention to another part of the President's Address where they have talked about doubling the income of farmers by 2022. Shri Amit Shah spoke as if it was only this Government that worried about the *kisan*. No, Sir; before you, Lal Bahadur Shastri was also worried about farmers! He gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan. Successive Governments were also worried about farmers, but nothing was implemented. The number of farmers committing suicide is increasing every year. The President's Address says, 'Wait for four more years'! By then the suicides would have increased manifold. How are we going to find a remedy to this problem?

Sir, the problems of water scarcity and irrigation in Tamil Nadu have been brought to the attention of the Government several times. What Tamil Nadu needs is water from the Cauvery river. Successive Governments have failed to provide legitimate share of the water and till now, the Government has not formed the Cauvery Management Board. Even the Supreme Court had advised them to form the Board, but they did not do so. One Central Minister, Mr. Ananth Kumar, said that they would not give water to Tamil Nadu. It was not just a citizen of Karnataka who said so, but a Central Minister. Sir, ten

[Shri T.K. Rangarajan]

lakhs of acres in Tamil Nadu are in need of water. The water required to irrigate those ten lakh acres is 15 TMC. Already Karnataka was supposed to have given 80 TMC of water to Tamil Nadu. So, what is happening is that instead of economic necessity, political compulsions are deciding the fate of the Cauvery issue. Yesterday, the hon. Prime Minister was speaking at a rally in Karnataka. He should have advised the people to give water to Tamil Nadu; they are our brethren. The Prime Minister's speeches are very popular. He could have advised the Karnataka people in this respect, but he did not do so. So, there are political compulsions. Karnataka is due for polls shortly. So, both the Central Government and the State Government there say, 'no water to Tamil Nadu'. I would like to know whether the Central Government treats Tamil Nadu as a part of India or not. The sufferers are farmers of the delta region of Tamil Nadu. Whatever farmers produce in Tamil Nadu is for the nation, but you deny them what is due to them. The Economic Survey speaks volumes about the impact of the weather on agricultural productivity. In such a situation, how can farmers' income double by 2022? It is a deliberate folly, deceiving the people and nothing more.

Sir, a lot of claims have been made about the employment scenario in the country. According to the report on employment, the Unemployment Survey, 2015-16, nearly half of India's workforce, that is 46.6 per cent, is self-employed. I don't consider self-employment to be bad, but I do not venture to call them 'pakora sellers'. The average annual income of self-employed people is Rs. 60,000. It means Rs. 5,000 per month and less than Rs. 200 per day. Can they survive? Can a family of husband, wife and two-three children survive? Dear, Sir, people become self-employed because there is no regular employment. You can see that autorickshaw drivers are B.A./M.A. today; Arrack sellers are B.A./M.A. Thanks to the neo-liberal policy, there is a type of economic growth which does not produce jobs, except low-paid jobs in the informal sector, and mainly contractual jobs in the organized sector. Even school teacher is on contract today. The economic slowdown and demonetization have killed the job prospects of all round. Shrinking opportunities of rural employment have also aggravated the situation. In such a scenario, the claim of the Government on the employment scenario is far from truth. Our President started his Address mentioning about special dimension of our" *Vasudhaiva Kutumbakam",* that is what we call *Yaadhum Oore Yaavarum Kelir.* But, Sir, the Indian Government pushed back the Rohingyas when they sought refuge in our country. You say *"Vasudhaiva Kutumbakam"* and when somebody comes here you push them back. The biggest democracy in Asia, our country, which ought to have played a role in solving the

Rohingya issue was silent and looked away from the issue. Why? When Pope goes to Dhaka, America sent its Secretary of State; UK and Canadian Ministers go there; Asian countries go. But India refused to go; India refused to intervene. Why? China is here to use that situation. They emerged as the peace keepers. The real thing is that Government of India's stance was negative. Why are they negative? They are so owing to their communal and ideological compulsions because Rohingyas are Muslims. So, you have your own ideological compulsions; you have communal compulsions. When everybody is involved in that, they don't want to involve in that. Sir, it is worthy to note that China played a mediatory role. The Foreign Minister of China went there and he was able to negotiate with the parties, and the Chinese Foreign Minister called it three-phase solution. In short, all of India's actions since the outbreak of this round of violence in Myanmar have negated its position as a regional, sub-continental and Asian leader.

Sir, there is a mention about the benefits of development of the poorest of the poor. But in 2017 one per cent of the Indian population garnered 73 per cent of the additional wealth and the remaining 99 per cent of the population divided among themselves the remaining 27 per cent of the wealth created.

Sir, while the Government is so much lavish in its claim of upward journey in respect of Ease of Doing Business, in many places the President's Address is * silent about India is going down in the rank of Global Hunger Index. He is very silent.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your have one more speaker.

SHRI T.K. RANGARAJAN: I understand. Sir, some 38 per cent of children in India suffer from stunting, where the height is limited by insufficient calorie intake. Citing this 2017 Report "India: Health of the Nation's States", the Economic Survey emphasizes that malnutrition is the most important risk factor for 14.6 per cent of the children that results in disease burden in the country.

Sir, since I come from Tamil Nadu, I wanted to raise two or three points relating to Tamil Nadu. Sir, in Keezhadi, there are 110 acres of land excavated, not even one per cent of work has been done. Permission to continue the excavation in 2018 has not been given by the Central Government. I request the Central Government to issue necessary orders to the Archaeological Department to continue the excavation. When I brought this issue to the notice of the House, as a Special Mention, the entire House supported

*Expunged as ordered by the Chair.

[Shri T.K. Rangarajan]

that, including the Deputy Chairman. The State Government has allotted two acres of land for establishing a museum in Keezhadi to exhibit 5,000-odd artefacts found during the excavation. The Central Government has not even taken over the land up till now. The Central Government has not even started the preliminary work of constructing the museum. The findings of Keezhadi will throw new light about the history of human civilization in India. Hence, I request the Government to pass necessary orders for continuing the invaluable excavation there.

Sir, the fate of livelihood of eight lakh workers engaged in manufacturing of crackers in Sivakasi and Virudhunagar in Tamil Nadu is hanging in balance as there is a case in the Supreme Court for banning the crackers. While the environment needs to be protected, we cannot ignore the lifeline of the eight lakh workers. The Government should come forward to exempt manufacturing of crackers for special occasions from the Environment Protection Act, 1986.

Finally, Sir, very importantly, I request the Government to come forward to adopt Thirukkural, which is the sacred book of Tamil, containing valuable ethics and guidance for the welfare of humanity, as our National Book as we have a National Bird, National Flower. I also request the Government to erect a statue of Thiruvalluvar inside the premises of Parliament. Thank you very much.

SHRI T.G. VENKATESH (Andhra Pradesh): Respected Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks to the Address of the hon. President, on the eve of the commencement of Budget Session of the Parliament, on 29th January, 2018. I feel it as a privilege to express my opinions on behalf of our party, the Telugu Desam Party.

Sir, hon. President, in his Address to the two Houses of Parliament has detailed the programmes being undertaken by Government in the country during the year 2018-19. Initiating the Address, he informed the commitment of the Government towards its flagship programme "Swatchh Bharat" by 2019 under which taking up construction of toilets to the poor with the financial support of the Government. Really, it is a marvelous programme inculcating the health consciousness in the minds of the people of the country. The popularity it gained is very laudable. I request the Government to earmark sufficient funds for completing success of the programme.

Also, the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, to provide LPG connections to poor families, is a praise-worthy programme. The initiation taken by the Government on LPG

subsidy 'Give It Up' campaign is marvelous. The subsidy foregone by the people has, to a great extent, helped the poorest of the poor to get LPG connections. The Jan-Dhan Yojana scheme introduced by the Government has got a great momentum and the poor have opened bank accounts with a view to get financial benefit from the Government. Making the poor people to open bank accounts will not be sufficient unless the Government does something to provide financial benefit to these account holders. I suggest the Government to plan in such a way that every Jan Dhan account holder gets some sort of financial benefit.

Through his Address, hon. President has given all the details about the schemes and commitments made by the Government. But the commitments and promises made to the State of Andhra Pradesh, like funds to construct State capital Amaravati, release of deficit balance, construction of Polavaram National Project, etc., as per the Andhra Pradesh Re-organization Act, 2014, have not been included. I request the Government to include all the promises, along with the Special Financial Package announced by the Government to Andhra Pradesh.

In his speech, hon. President has made no mention of the details of the Polavaram National Project in Andhra Pradesh. Proper funds are not being released to complete the project as scheduled by 2019. As this project is very important for the development of the newly-formed State of Andhra Pradesh, I request the Government to take necessary steps for its early completion without any delay.

While giving the details of the Railway works, hon. President stated that introduction of High Speed Bullet Train between Mumbai and Ahmedabad will be taken up by the Government of India. But there is no mention about the promised Visakhapatnam Railway Zone to the State of Andhra Pradesh. I request the Government to include the same.

Hon. President added that New Metro Rail Policy has been envisaged to lay emphasis on metro connectivity in various parts of the country. As there is no mention of the Metro Rail project announced for Andhra Pradesh, I request the Government to include the same for the development of newly-formed State of Andhra Pradesh and also the steel plant.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, we support that.

SHRI T.G. VENKATESH: You supported the division of the State also.

Sir, hon. President has also informed that the GST has been introduced with a view to achieve economic integration. The introduction of the GST has given rise to many

[Shri T.G. Venkatesh]
problems in its implementation. The recommendations of the State Governments have to be taken into consideration for its proper implementation.

While giving the details of the setting up of Institutes of Eminence in the country, financial assistance of ₹ 10,000 crores and autonomy of IIMs have also been announced. But there is no mention about setting up of the Institutions announced and funds allocated to the State of Andhra Pradesh such as NIT Building, Tribal University, Telugu Academy, etc. I request the Government to include the institutions promised and announced for Andhra Pradesh also in the list.

Hon. President has also informed that the bold decisions taken by this Government like demonetization, implementation of OROP in the Defence field, repeal of obsolete laws, launch of BHIM mobile payment system, Aadhaar payment system, one-nation-one-tax system through GST, sustained global growth, liberalization of FDI policy, facing terrorism, global affairs, global outreach, agreements with foreign countries, are leading to all-round development of the country.

With all the above, I express my profound thanks to the hon. President of India, on behalf of Telugu Desam Party, for taking up all the developmental schemes with a request to honour the commitments made to Andhra Pradesh by releasing sufficient funds for completion of Polavaram National Project, establishment of Visakhapatnam Railway Zone, establishment of steel plant in Rayalaseema, development of Vizag-Chennai Industrial Corridor, rapid road connectivity between proposed State capital Amaravati and Telangana, Amaravati Metro Rail Project, development of Duggarajapatnam Sea Port, along with release of revenue deficit for five years and implementation of Special Financial Package announced in lieu of Special Category Status by the Government for the development of newly-formed backward State of Andhra Pradesh to develop at par with other States.

Sir, once again, I want to make a request. The Telugu-speaking people have been divided by the combined hands. At that time, the Congress Party was ruling the country and BJP was the main Opposition party. By them both together, the Telugu-speaking people of the State have been divided. Congress was in power, but BJP also supported it. Both of them had agreed to give a lot of benefits to the State of Andhra Pradesh because all the investment was in Telangana, Hyderabad and other places. So, Andhra Pradesh became a poor State as compared to any other State.

SHRI T.G. VENKATESH: Sir, if you see the per capita income, it is excellent in Telangana, it is good in Karnataka, it is excellent in Maharashtra. All these States are in a good place and their per capita income is also good. We also should reach that level. Even if you see the recent Budget announcements, importance has been given to all the other States except Andhra Pradesh.

Once again, I request you to please ensure that Andhra Pradesh, which is a newly-born State, is taken care of for the development activities. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you very much. Next speaker is Shri D.P. Tripathi.

SHRI D.P. TRIPATHI: Mr. Vice-Chairman, Sir, with due regard to the President of the Republic, I must say that this is the first Presidential Address, which has neither the dress nor the dressing. Why I say this is that both the form and content are faulty. As the old Sanskrit saying, "गद्यं कवीनां निंकष वदन्ति", 'prose is the litmus test of poets', the prose of this Address is very stale and awful. To use Shri Atal Bihari Vajpayee's metaphor, there is no smile in the speech.

Form becomes very important in expressing the imagination and dreams of people. Before I come to the analysis of the Address, Mr. Vice-Chairman, Sir, I must seek your permission to make a few points, and, I would make only new points; I would not repeat what other hon. Members before me have said.

Before I begin the discussion on the Presidential Address, I must point out the most shocking omission in this Address. There is no mention about the hope and the future of India, the children of India and their rights find no mention in the Address at all. Whereas if you look at the two Presidential Addresses that I want to discuss in comparison to the present one — the first is, the Presidential Address given by Dr. Rajendra Prasad after the first elected Parliament in 1952, and, the second is, the first Presidential Address given during the Prime Ministership of Shri Atal Bihari Vajpayee in 1998 —they all talked about the children. This is the first time that children are not mentioned. Where you talk about Beti Bachao, Beti Padhao, you don't read your own Economic Survey, its social survey, which says that there are not one or two but twenty-one million unwanted girl children in India. I am not saying this,- Economic Survey is saying this.

It is very good that through his maiden speech, the President of the ruling Bhartiya Janata Party, Shri Amit Bhai Shah, initiated the debate. He has made a few points. Before I

[Shri D.P. Tripathi]

come to the Address which he elucidated, explained and enlarged about the achievements of the Modi Government in all sectors of our national life, and, before I analyse a couple of points raised by him, I must ask him a question. If you have made so much progress in the NDA Government led by hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, why is it that India is behind even Pakistan, Bhutan and Nepal in the Happiness Index issued by the United Nations a few months ago?

Why is it so? Kindly read the entire Happiness Index report and you will find it shameful where India is positioned.

The second point, you talked about many achievements and contributions. What I see about your Government is described very well in the ancient text ' शतपथ ब्राह्मण्' which says "वागहि वज्रः वागहि शस्त्रम् वागु सर्वं भेषजम्" -- speech is the *vajra,* speech is the weapon, speech is the medicine for all diseases. So, speeches after speeches, speeches after speeches, without any actions — this is the Government led by Shri Narendra Modi. This Address looks like Prime Minister's election speech without its oratorical skills. Now, Shri Amit Shah talked about the great coalition *dharma* which he is following, how despite majority, after 30 years, they took all other partners along and formed the NDA Government. What is there; how are they running the coalition Government? You just heard Shri Venkatesh of Telugu Desam. He was talking about the step-motherly treatment meted out to the Andhra Government. His leader, Shri Chandrababu Naidu, is reported to have said to his MPs yesterday, which is ideally reported in the media today, ...*(Interruptions)*... not only to put pressure, but disrupt the Parliament, demand for the rights of people of Andhra Pradesh. This is what he has said. The recent statement of Shiv Sena Chief, Shri Uddhav Thackeray, is before all of you. From the Leader of the Opposition to Shri Sukhendu Sekhar Ray, all of them have talked about this doubling of the income of farmers. I will come to that later. But Shri Thackeray says that this promise is baseless. These are his words, not my words. Then, the demand of the Telugu Desam has been supported by our friend, Shri Naresh Gujral, of the Akali Dal. So, the voices of your coalition partners are very great. This coalition seems to be uniquely cohesive where there are all kinds of voices. Prime Minister Narendra Modi last time quoted my friend, Nida Fazli, to the best of my memory, while replying to the Vote of Thanks to the President's Address last year. I think I should also quote Nida Fazli about the kind of coalition that you are running. निदा फाज़ली का शेर है।

"दुश्मनी कितनी भी हो, पर रिश्ता निभाते रहिए,
दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए।"

This is how you are running the coalition.

The next point, I think, I should talk about the two Presidential Addresses and compare this one with the two Addresses. One, of course, is the Address, as I mentioned, in 1952, after the election of the first Parliament of independent India, the Address delivered by Dr. Rajendra Prasad. In many ways, it is unfair on my part to compare that one with the present one. Even then I must request you to read this Address because it gives a vision of new India. You are talking about new India in the concluding para of the Presidential Address. How this new India can be made, for that you should read this Presidential Address of 1952 where Dr. Rajendra Prasad talked about the high destiny of India, its civilisational values, the vision of a new country and wisdom and tolerance of spirit. He talked in detail about this. And you will be surprised to know that in the very first Address after the election of Indian Parliament in 1952, there were six large paragraphs about the foreign policy of India and international relations. How you should build the presence of your nation in the world is described in this. And, of course, all sections of society are mentioned in this. I am saying this because if you read it carefully, you will find that this Address has more emphasis on the Government and much less on the people whereas the Address by Dr. Rajendra Prasad talks about the onward march of the people, the basic essence of the people. लोकतंत्र की परिभाषा अगर संक्षेप में देनी हो, तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र साधारण की असाधारणता है। Extraordinariness of the ordinary is democracy, जो शक्ति जनता में होती है, सामान्य जन में होती है, उसी से लोकतंत्र चलता है। In this Address, people are, more or less, absent. You do not talk about people's endeavours and efforts whereas the Address by Dr. Rajendra Prasad talks about all that.

Now I come to another one from which you have not learnt any lessons and that is the first Presidential Address when Shri Atal Bihari Vajpayee assumes office as Prime Minister of India. It gives a vision. One can agree or disagree with it, but that is beside the point. Kindly read it to know what vision it gives. I will quote a few things from that. First, it says that merely parliamentary arithmetic is not the basis of democracy. Cooperation, conciliation and consensus are essential for democracy. I am quoting it from this Address. Then it says that secularism is integral to Indian tradition. I am quoting the sentence from this Address, not from the manifesto of the Congress Party or the Nationalist Congress Party. It says that secularism is integral to Indian tradition. The Government is unequivocally committed to upholding secular values. This is what is said in this Address. In terms of foreign policy, it talks about Asian solidarity and regional

[Shri D.P. Tripathi]

7.00 P.M.

cooperation, in fact, various groups of regional cooperation. Actually, it has a kind of perspective on foreign policy, a vision on foreign policy. You can agree or disagree with it, but that again is beside the point.

On comparing these two Addresses, especially this one of 1998 which says how you can build a new India, you will find that it gives that vision. It is not surprising that there is no mention of communal harmony in the present Presidential Address. You should not be surprised that there is no mention of it because they have not learnt anything from their own NDA Government led by Shri Atal Bihari Vajpayee. This is what is there. There is paucity of time. I have only 15 minutes and I have to cover other points also. Therefore, I am not quoting all these things in detail. There is a perspective on this. The present Address does not present a vision of India. The vision of India is based on tolerance, diversity and togetherness. And this one sentence in this Address of the President in 1998 is very important for you, the Members of the Treasury Benches, to learn. It talks about the governance that seeks to unify and not to divide the country. This is very important. I am not saying this. This is your President's Address during your own Government.

Now, Shri Amit Shah talked about some new experiments during the BJP Government. All other hon. Members before me, beginning from the Leader of the Opposition, Azad *Saheb* to Shri Sukhendu Sekhar Ray and Comrade Rangarajan have talked about all these issues but I must mention as to what kind of image of India we are showing to the world. It depends on the actions of the Government. What actions are we doing? New experiments that he talked about, I must mention the new experiments. There are two points that I would make.

First is, where BJP, by its political decision, has gone against all values of Indian culture, civilization and Hindu religion. Why I say this and I want the Treasury Benches to answer this. What is the concept of a yogi? The yogi is one who renounces all the material life. Even the yogis who became sanyasi and were born in a royal family like Buddha renounced the rajpaat. यह पहली बार हुआ है। इसका जवाब दीजिएगा। स्वामी विवेकानन्द से लेकर महात्मा गांधी तक, किसी ने राजपाट की चिन्ता नहीं की, योगी से लेकर महात्मा तक। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है कि एक मठ के प्रधान को राजपाट दे दिया, मुख्य मंत्री बना दिया। किसी ने आज तक योगी को मुख्य मंत्री बनाया था? किसी ने नहीं बनाया। यह भारतीय जनता पार्टी की ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. ...*(Interruptions)*... Mr. Tripathi, please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI LA. GANESAN (Madhya Pradesh): Sir, he is talking about a person who is not in this House. ...*(Interruptions)*... How can he comment ...*(Interruptions)*... He should not comment upon him. ...*(Interruptions)*...

SHRI DP. TRIPATHI: It is not on him. ...*(Interruptions)*... I did not take the name. ...*(Interruptions)*... I believe in parliamentary decorum. I have never. ...*(Interruptions)*... I never interrupt. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please do not interrupt. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: I never interrupt. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It is his time. Let him finish. ...*(Interruptions)*... Please conclude, Mr. Tripathi. ...*(Interruptions)*...

श्री डी.पी. त्रिपाठीः मैंने नाम नहीं लिया है। मैंने जो नया प्रयोग आप कर रहे हैं, उसका उदाहरण दिया है। जरा बताइए, भारत में किसी ने किसी योगी को राजपाट दिया हो? **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now. ...*(Interruptions)*...

श्री डी.पी. त्रिपाठीः महोदय, मैं दूसरी बात की भी चर्चा कर दूं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने श्री गुलाम नबी आज़ाद से आपातकाल के बारे में जानना चाहा। खैर, वे कुछ नहीं बोले। सदाशयता के कारण या मर्यादा के कारण वे कुछ नहीं बोले। मैं इस पर आपके विचार के लिए कुछ कहना चाहता हूं। एक तो प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के आपातकाल के बारे में क्षमा मांगी। यह कौन बोल रहा है, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। I do not indulge in self-praise but there is no book on the Emergency right from David Selbourne to Coomi Kapoor to latest by A. Surya Prakash which does not talk about my case and my role during the Emergency's struggle. Therefore, I am saying this. Mrs. Gandhi not merely apologized to the nation. There have been two Presidents of the Congress after that who had no role to play whatever, nothing bad, during the Emergency. And I am not saying this. The Shah Commission said it. The leaders of the Janata Party Government in 1977-78 said this that Shri Rajiv Gandhi and Shrimati Sonia Gandhi had no role to play whatever during the Emergency. I am not saying this. I have quoted who said it.

Now, when BJP talks about that anti-Emergency struggle, I never repeat but today I am repeating for the consideration of Shri Amit Shah that by your actions you have

actually humiliated that heroic struggle against the Emergency. I consider the best period of my life those four months being underground and fourteen months in jail during the Emergency. Being the part of struggle. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: Let me. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have already acceded your Party's time. ...*(Interruptions)*...

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: We all are listening and learning something. ...*(Interruptions)*...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

SHRI D.P. TRIPATHI: By your actions you have humiliated the anti-Emergency struggle. Why? It is because two people, who were indicted by the Shah Commission appointed by the Janata Party Government, were made Ministers by you. One of them was responsible for atrocities. ...*(Interruptions)*... This is according to the Shah Commission, according to all your leaders; he is a Minister now in the Government. There is so much about anti-emergency struggle. Very briefly, I wish to make a few points about doubling of the income of the farmers. Kindly read the Economic Survey, Volume I, Page 95. What does it say? It says that the income of the farmers in the irrigated sector will decline by 15 to 18 per cent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tripathji. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: Sir, I am quoting from Page 95.

श्री उपसभापतिः त्रिपाठी जी, आपका टाइम ओवर हो गया। ...**(व्यवधान)**... Tripathiji, your time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: It is Volume 1, Page 95 of the Economic Survey of India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tripathiji. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: I will be very brief. I will take only three minutes more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; already, you have taken extra four minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: Just three minutes. I am making my last point.

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): सर, इसे 12 घंटे से 14 घंटे कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب جاوید علی خان** : سر، اسے 12 گھنٹے سے 14 گھنٹے کر دیجئے ...(مداخلت)...

SHRI D.P. TRIPATHI: I am leaving the point of foreign policy. There is a lot to be said about the foreign policy.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, give him five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Will you give your party's time? ...*(Interruptions)*... Will you give? ...*(Interruptions)*... You always intervene like this. ...*(Interruptions)*... No, no; Shri Jairam Ramesh, you should not do this. ...*(Interruptions)*... You always do like this. ...*(Interruptions)*... Will you give your party's time? ...*(Interruptions)*... They have already taken extra five minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: I am concluding. Okay; I obey your orders.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute. ...*(Interruptions)*... I have no problem in allowing ten minutes or fifteen minutes but you should decide to sit beyond 8'o clock. ...*(Interruptions)*... That is all. ...*(Interruptions)*... I have no problem. ...*(Interruptions)*... I have no problem but every party is taking more time. What do I do?

SHRI D.P. TRIPATHI: Okay, I will be very brief. I will obey your orders.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Decide here and now. Will you sit up to 9'o clock? ...*(Interruptions)*... I have no problem. ... *(Interruptions)*... Okay, finish in three minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: Let me just conclude. Allow me one minute to conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you are allowed. ...*(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI: So, Sir, just one thing. I said that there will be 15 to 18 per cent decline in the farmers' income in the irrigated sector and 20 to 25 per cent decline in the farmers' income in the unirrigated sector. This is what the Economic Survey says. The second thing is about the nature of growth. And, I will conclude then. If you look at the nature of growth, the Address talks about an impressive growth. What is that growth? What is the nature of that growth? GDP components are manufacturing, consumption and export. According to your Economic Survey, Volume II, Page 7, consumption is 95

†Transliteration in Urdu script.

[Shri D.P. Tripathi]

per cent of your GDP which means your growth stands on a feet of clay. The domestic investment has been going down. It was 30 per cent of the GDP in 1999; 40 per cent in 2010 and 29 per cent now.

SHRI ANAND SHARMA: It is 26.9 per cent.

SHRI D.P. TRIPATHI: That is now, 26.9 per cent. So, this is the position of the domestic investment. How are you going to strengthen your economy?

अब लास्ट में, आपका बिना ज्यादा समय लिए हुए, मैं फिर प्रधान मंत्री जी के प्रिय शायर, मेरे मित्र निदा फज़ली को ही उद्धृत कर देता हूँ। आपकी सरकार जैसे काम करती है, यह शेर उसको बखूबी प्रकट करता है, बता देता है। शेर हैः

"कभी-कभी यूँ ही, हमने जी को बहलाया है।
जिन बातों को खुद न समझे, औरों को समझाया है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Swapan Dasgupta; not present. Sardar Balwinder Singh Bhunder; not present. Shri Tiruchi Siva; not present. Shri D. Raja, yes, he told me. Shri Joy Abraham; not present. Shri Shwait Malik.

श्री श्वेत मलिक (पंजाब)ः ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारी सरकार की स्वर्णिम उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। आज ऑनरेबल लीडर ऑफ दि अपोजिशन ने कुछ बिन्दु उठाए। उन्होंने कुछ स्कीम्स के नाम का चक्कर डाला, तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि स्कीम, जो कागज में रहती है, उसका आम आदमी को क्या लाभ है? जब वह स्कीम लाभार्थी तक नहीं पहुंचे, तो केवल नाम देने का क्या लाभ है? मैं प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को और उनकी सरकार को नमन करूंगा कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चली हैं, हर वर्ग के लिए चली हैं, चाहे वह युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे सीनियर सिटिजन्स हों, चाहे फौजी हों, चाहे किसान हो, वे धरातल तक पहुंची हैं, लाभार्थी तक पहुंची हैं। मैं इनको याद कराऊंगा कि पूर्व प्रधान मंत्री, जिन्होंने एक बार यह accept किया था कि हम बेबस हैं, हम निस्सहाय हैं कि जब हम यहां से जनता की सेवा के लिए एक रुपया भेजते हैं, तो 85 परसेंट दलाल खा जाते हैं और केवल 15 प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचता है, पर उन्होंने इसके ऊपर चिंतन नहीं किया, न चिंता की, बल्कि उसके आगे घुटने टेके और वह निरंतर चलता रहा, देश लुटता रहा, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये वैसी ही स्कीम्स हैं, जिनके नाम ये ले रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं इनको यह बताना चाहता हूंः

"मंजिलें उनको मिलती हैं, जिनके सपने में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।"

ऐसे हैं हमारे मोदी जी, जिन्होंने आकर चिंतन भी किया, चिंता भी की और दलाल जो पैसा खा जाते थे, उसके लिए जन-धन योजना बनाई, जिसके अंतर्गत करोड़ों देशवासियों के zero balance पर

खाते खुले और आज आप देखिए कि जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभार्थियों यानी गरीब जनता के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। अब तो मनरेगा का जो पैसा है, वह भी मजदूर के खाते में जा रहा है। दलाल जो थे, उनके मुंह पर करारी चपत लगी है, भ्रष्टाचार को कड़ी चोट दी है। यह है हमारी सरकार और लगभग 97 हजार करोड़ का जो मिडलमैन कल्चर था, वह आज लाभार्थी की जेब में गया है।

यूपीए सरकार में कैसा प्रशासन था? उस सरकार में भ्रष्टाचार का तांडव था, मानो आम आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। आम आदमी का सरकार से विश्वास ही उठा गया था। ऐसे समय में जहां भ्रष्टचार की बात हुई, 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के केस चले। अभी 2G स्कैम की बात आ रही थी, उस पर सीबीआई investigation भी उसी समय शुरू हो गई थी और वह निर्णय अभी बिल्कुल लोअर स्टेज पर है। मैं तो पूछूंगा कि कोल ब्लॉक्स का क्या हुआ? आपके सहयोगी, जो फॉडर स्कैम में जेल यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? आपके मंत्रिमंडल के जो सदस्यों ने आपकी regime में कई बार जेल यात्रा की, उनका क्या हुआ? एनडीए सरकार को आज चार वर्ष हो चले हैं, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी विलक्षण प्रतिभा, श्री अरुण जेटली जी, जो लीडर ऑफ दि हाउस हैं, वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार पर चोट करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, तो ऐसे समय में आप यह बताइए कि हमारे मंत्रिमंडल में हमारे सांसदों रप एक भी आरोप लगा पाए हों? यह होती है सरकार, ऐसी सरकार होती है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण था कि देश की जनता ने आपको दंड दिया, देश की जनता ने आपको नकार दिया और 2014 में आप निम्नतम संख्या लेकर इस हाउस में आए हैं। इतना ही नहीं, यहां एन.डी.ए. सरकार के, मोदी जी की सरकार की good governance के बारे में कहा गया, उसका भी आगे प्रमाण मिल गया कि आप न्यूनतम से भी न्यूनतम होते गए, एक-के-बाद एक एन.डी.ए. चुनाव जीतता गया, देश की जनता का एन.डी.ए. के फेवर में यही प्रमाण-पत्र है। इस देश की जनता ने आपको स्टेट्स में भी नकार दिया। जैसा यहां बताया गया कि कई ऐसे राज्यों में, जहां आपकी सरकारें लंबे समय से चली आ रही थीं, जैसे असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, वहां भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आप ऐसी पार्टी पर किस तथ्य के आधार पर, सिर्फ जुमलों के आधार पर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि नमो से क्या होता है? मैंने पहले भी कहा है कि इस देश का गरीब मरता रहा और आप लोगों के केस चलते रहे।

इस समय एक युगपुरुष, एक तपस्वी, एक कर्मयोगी के हाथ में लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। देश ने उन पर पूरा विश्वास किया और यह योगी, वह पहले प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने इस संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना और उसे नमन करके यह कहते हुए प्रवेश किया कि यह मेरे लिए मंदिर है। इस लोकतंत्र के स्थान की उन्होंने मंदिर की तरह ही पूजा की। उन्होंने यह संकल्प लिया कि 'मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।' ऐसे प्रधान मंत्री हैं हमारे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश की जनता का आह्वान किया कि विगत चार वर्षों मे देश हमें नित्य नई जिम्मेदारियां दे रहा है, देश को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, देश को हमने बहुत अपेक्षाएं हैं और हमें उन अपेक्षाओं को पूरा करना है। हमें सजग रहना होगा। Modji has a vision for India, and the courage to take risks for the upliftment of the people of India. वे आपकी तरह वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। आप तो आगे

[श्री श्वेत मलिक]

की बात करते हैं। ये हमारे मोदी जी है, जो वोट की चिन्ता नहीं करते, सत्ता की चिन्ता नहीं करते। सत्ता उनके लिए सेवा का माध्यम है। वे देश की चिन्ता करते हैं और 20 वर्ष आगे की सोचते हैं। 20 वर्ष का उनका विज़न है, 20 वर्ष की उनकी योजनाएं हैं। आप यहां 2022 की बात करते हैं, वे तो 2022 से भी आगे 20 वर्ष की सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं कि देश को कैसा बनाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि लगभग 55 वर्ष आप सत्ता मे रहे, लेकिन देश लुटता रहा। देश के शहीदों ने इस देश के लिए जो स्वप्न लिए थे, जिन्हें लेकर हंसते-हंसते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं। तभी आप आज न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं - चाहे केन्द्र हो या प्रदेश हो। आज मोदी जी को जो जनमत मिला है, उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने सिर्फ 'गरीबी हटाओ' का नारा ही नहीं लगाया, बल्कि सही मायने में उन्होंने आम आदमी की सेवा की। जिस भ्रष्टाचार को लेकर आप असहाय हो गए थे, निस्सहाय हो चुके थे, उस भ्रष्टाचार पर उन्होंने technology के माध्यम से नकेल लगाई। जहां तक जन-धन योजना का सवाल है, एस.आई.टी. बनाने का साहस हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया। उसके बाद tax equalization के लिए, भले ही आपके समय में GST के बारे में सोचा गया, यहां बड़े विस्तार से एक माननीय सांसद ने बताया कि आप जनता के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाए, जो आपने वादा किया था, उसे पूरा नहीं कर पाए, सभी प्रदेशों में आप consensus नहीं बना पाए, this was the reason for your failure. जिस GST बिल को आप 10 वर्षों तक पास नहीं करा पाए, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व में, सभी की consensus के बाद, सर्वसम्मति से अब वह पास हुआ। यह ऐसी सरकार है, जिस पर लोगों को भी विश्वास है, जिसने प्रदेशों का भी विश्वास जीता। आज आप भी जानते हैं किं अदर से एक टैक्स एक नए भारत की शुरुआत है, तभी तो आप भी पहले लाए थे, लेकिन आप इसको पास नहीं करा पाए, इसलिए आप इसका विरोध करते हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री टी.के. रंगराजन**) *पीठासीन हुए]*

सो मैं उस प्रधान मंत्री का कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिन्होंने यह नहीं कहा कि हम आरोप लगाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बंद करो यह दौर अब हम जो डेफिशिएंट रह गया, जो लम्बे समय पर यू.पी.ए. सरकार नहीं कर पाई, उसको हम कंपन्सेट करेंगे और उसको 5 वर्ष के कार्यकाल में करेंगे। देश को आजाद होते 85 वर्ष लग गए थे, 1857 से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, न जाने कितने शहीदों के प्राणों की आहुति के बाद 1947 में जाकर हमें आजादी मिली थी। फिर आजादी के बाद 70 वर्ष बीत गए। तो इन्होंने यह संकल्प लिया है कि हम आने वाले 5 वर्षों में जो सोशल ईविल्स हैं, जिन्होंने इस देश को दीमक की तरह चाट लिया है, उससे देश के सवा सौ करोड़ लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, साम्राज्यवाद भारत छोड़ो और एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत बनाने का आह्वाहन किया है। ये ऐसे प्रधान मंत्री हैं। मुझे याद है जब मैं विद्यार्थी था, लगभग 1989 के आसपास, I travelled in the bullet train Shinkansen city, in Japan, a small country. लेकिन यहां की लीडरशिप कभी साहस नहीं कर पाई बुलेट ट्रेन चलाने का, ये ही वे प्रधान मंत्री हैं, जो बुलेट ट्रेन लेकर आए हैं और वह बुलेट ट्रेन चलने वाली है। आज जो उन्नति हुई है हर तरफ, चाहे महिला हो, मातृशक्ति हो, अभी जो ट्रिपल तलाक का मामला आया था, शाहबानो का केस आपने भी देखा था। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, please conclude.

श्री श्वेत मलिकः सर, बस मैं दो मिनट लूंगा। ट्रिपल तलाक के ऊपर सफलता हमारी सरकार ने ली है। आज मातृशक्ति को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक मेटरनिटी लीव दी है, वह हमारी सरकार ने दी है। जो "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का कार्यक्रम है, वह हमारी सरकार ने दिया है। आज मातृशक्ति, मेरी बहनें नेतृत्व कर रही हैं, इस देश का कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, please conclude.

श्री श्वेम मलिकः पेट्रोलियम की योजना के लिए प्रधान मंत्री ने समृद्ध वर्ग से यह कहा है कि आप subsidy सरेंडर करो और उसको कंपन्सेट किया गरीबों के लिए। आज 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दे दिए और उसको बढ़ाकर हमने आने वाले बजट में 8 करोड़ कर दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you. Mr. Shwait Malik, you have exceeded your time by two minutes.

श्री श्वेत मलिकः हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वास्थ्य के लिए जो 50 करोड़ जनता जो जनसंख्या का 40 प्रतिशत बनती है, उसको यह "आयुष्मान भारत" योजना दी है, जिसमें वे सुरक्षित रहेंगे आगे आने वाले समय में।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude.

श्री श्वेत मलिकः सब जानते हैं कि बिजली ग्रोथ इंजन है। आपके समय में 18 हजार गांव अंधेरे में थे। आज देखिए, इस हाउस की बिजली चली जाए तो हमारा क्या बनेगा? आज ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude. I have to call the next speaker.

श्री श्वेत मलिकः आज 16 हजार गांवों को बिजली पहुंच गई है। उसके बाद भी 2022 तक घर-घर बिजली पहुंचाई जाएगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Mr. Shwait Malik, please conclude.

श्री श्वेत मलिकः ऐसी सरकार होती है जिसको सरकार कहा जा सकता है। डिफेंस देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, 6 लाख करोड़ की सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर तक सड़क पहुंच रही है। तो एन.डी.ए. सरकार ऐसी है, केवल योजनाओं से ...(**व्यवधान**)... लीडर ऑफ अपोज़िशन मेरे आदरणीय हैं, केवल नामों से योजनाएं नहीं चलतीं, उनके लिए रक्त देना पड़ता है, तब जाकर आम आदमी तक पहुंचती हैं, धन्यवाद, जय भारत।

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। जब से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है, मैं इसे पढ़ रहा था और पहली बार मैंने देखा कि राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण में जैसे इस सरकार की जीने की इच्छा समाप्त हो गयी हो। अगर मैं इसे एक वर्ड में कहूं तो महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा - डेथ के लिए नहीं कह रहा हूं, लम्बी उम्र की दुआ करता हूं, लेकिन यह इस सरकार का dying declaration है, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने दिया है। आपने स्वीकार कर लिया है कि हम असफल हैं, हमारे पास अब भविष्य की कोई योजना नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे आप क्रिकेट की कमेंटरी कर रहे हैं। यह योजना चल रही है, वह योजना चल रही है। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की परिभाषा तो समझिए। उसमें आपको यह बताना होता है कि इस साल सरकार क्या करने जा रही है।

THE MINISTER OF TEXTILES AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, my only request to Pramodji is, please don't say that it is a dying declaration.

श्री आनन्द शर्मा: ठीक बात है, यह पार्लियामेंटरी है।

श्री प्रमोद तिवारी: एक मिनट। मैं अपनी बात दोहराता हूं। मैं अपनी बात दोहराता हूं कि यह इस सरकार का dying declaration है। मेरे एक साथी कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि साढ़े तीन, चार साल में हम पर भ्रष्टचार का कोई आरोप नहीं लगा। मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूं। मेरे भाई, यह "राफेल" का घोटाला क्या है? 500 करोड़ का 1,500 करोड़ में खरीद रहे हो, इकट्ठा तिगुना मार रहे हो। "व्यापम" क्या है? क्या यह घोटाला नहीं है? 51 लोग मारे गए। यह छत्तीसगढ़ का चावल घोटाला क्या है? राजस्थान में ...(**व्यवधान**)... मैं भाजपा सरकार की बात कर रहा हूं। आपकी छत्रछाया में जो फल-फूल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राजस्थान में 40 हज़ार करोड़ का घोटाला क्या है? आप टेंडर तो करा लेते। दूसरों की माइन तो देख रहे थे, आपने तो अपनी माइन से वह निकलवा दिया, जिसका टेंडर भी नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो महाराष्ट्र के नागपुर का पतंजलि घोटाला हुआ है, वह क्या है? यह चिक्की घोटाला क्या है?

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): वह कुछ नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी: मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने तो अभी कुछ घोटालों का जिक्र किया है। चिक्की घोटाला जो है, वह क्या है?

श्री अमर शंकर साबले: वह कुछ भी नहीं है।

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश): आपके कहने से कुछ नहीं होता।

श्री अमर शंकर साबले: कोर्ट ने कहा है ...(**व्यवधान**)... चिक्की घोटाला कुछ भी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K RANGARAJAN): Please sit down. Let him speak. When your turn comes, you may speak.

श्री प्रमोद तिवारीः गुजरात का पेट्रोलियम घोटाला क्या है? यह कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने घोटाले की परिभाषा ही बदल दी है। आपने तो घोटाले को दक्षिणा मान लिया है, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। मैं तो आपकी कुंडली के कुछ ग्रह पढ़ रहा था, आप सुनिए तो सही। मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मेरा काम ही यही है। मैंने तो अभी कुछ ही बताया है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपकी कुंडली पढ़ी जाएगी, तो हमारे नेता, नेता विरोधी दल माननीय आज़ाद साहब ने एक चीज़ कही थी कि आपको repackaging बड़ी अच्छी आती है और जानते हैं, मैं आपके लिए क्या कहता हूं? आपका घोटाला करने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, तरकीब बहुत अच्छी है - लोग फुटकर में करते हैं, रिटेल में करते हैं, आप होलसेल में मार देते हो, आप यह कर देते हो। अब यह क्या है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से जयराम रमेश जी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे - बजट के बाद शेयर मार्केट में जो गिरावट आयी है, वह क्या है? यह आप करा रहे हो - गिराओगे तो भरोगे। लोग तो सैंकड़ों की बात करते हैं, आप तो लाखों का कर जाते हैं। आप विशाल लोग हो, साठ हज़ार का अस्सी करोड़ बनाते हो, आप तो डकार भी नहीं लेते हो - आप इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो चार साल में आपको जो करना था, उसमें से किया कुछ नहीं, आप बस ध्यान हटाते रहते हो। न आपका 15 लाख का जिक्र है, न आपका रोज़गार का ज़िक्र है। ये आपके आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आपके आंकड़े कह रहे हैं कि हम 70 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, आप तो दो करोड़ की बात ही नहीं कर रहे हो। मैं यह बात कह रहा हूं कि सारे सेक्टर्स में रोज़गार घट रहे हैं। जहां पर, जिन पदों पर बहुत दिनों से नियुक्ति नहीं हुई, आप उन पदों को समाप्त कर रहे हो। तो आपकी सरकार सबसे ज्यादा रोजगार घटाने वाली जानी जाएगी, जो हमने पैदा किया था। दो चीज़ों के लिए यह इल्ज़ाम आपके सिर पर है। पहला इल्ज़ाम यह है कि जो देश का ताना-बाना गांधी जी ने बुना था... आपने हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई की एकता को तोड़ा। दूसरा, आप पर इल्ज़ाम यह रहेगा कि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने जो इस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी थी, उसको आपने नष्ट किया, तोड़ दिया, ये दो इल्ज़ाम आपकी सरकार की चार साल की उपलब्धि में आपके सिर पर हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको बड़ा गुरूर है कि आप चुनाव जीतते चले जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं, अगर मैं राजस्थान का जिक्र करूंगा, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि आप तीनों सीट हार गए। उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है - मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, वहां पर क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? जब आप मणिपुर या गोवा के बारे में कहते हो कि वहां आपका बहुमत आया है, तो मैं छत की तरफ देखने लगता हूं कि कहीं गिर न जाए। आप इतना बड़ा असत्य बोलते हो। आप गोवा में जितने थे, उसके आधे रह गए। आपको राज्यपाल को धन्यवाद देना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि तमिलनाडु में क्या हुआ? पंजाब में जो कुछ हुआ, उसका तो हम जिक्र ही नहीं करना चाहते हैं। अगर गुजरात में जरा भी दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ लो, तो मॉडल वहीं से पैदा हुए थे और वहीं ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट पर आ गए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर तीन जिले उसमें से निकाल दो, तो जिस 49 परसेंट की

[श्री प्रमोद तिवारी]

बात आप कर रहे हो, आप 40 परसेंट के नीचे आ जाओगे। आपने बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद और राजकोट को मैनेज किया। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आजकल खाली रहता हूं, इसलिए पढ़ लेता हूं। आपके पास तो ज्यादा काम है, इसलिए आप भी टाइम निकाल कर पढ़ लीजिए। आप पर इल्ज़ाम है कि हमने जो आपको मजबूत अर्थव्यवस्था दी थी, आपने उसको कमजोर किया, देश के ताने-बाने को तोड़ा, संवैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया, भारत की प्रगति को रोका ...(**व्यवधान**)...

श्री मेघराज जैनः आपने जनता को कितना ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारीः देश को कमजोर किया, सरकार की विश्वसनीयता समाप्त की और आज का अखबार अगर पढ़ सको और आंख में आंसू न हों, तो ग्लिसरीन लगा लो, चार सैनिक आज फिर मारे गए हैं। उनमें एक बहादुर कैप्टन है। आप अगर जोड़ो, तो आपकी सरकार के 44 महीने के अंदर जितने सैनिक मारे गए हैं, मैं उनको शहीद कहूंगा, उतने सैनिक कारगिल युद्ध में भी शहीद नहीं हुए थे। आपको शौक है, आप काबुल से चलोगे, उड़ोगे, बिना बुलाए लाहौर पहुंच जाओगे, चरणों में गिर जाओगे और उसके बाद लौट कर आओगे। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं और आप जरा देखिए कि यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में 500 प्रतिशत ज्यादा युद्ध विराम की सीमा का उल्लंघन हुआ है। मैं आपको फिगर देता हूं कि 44 महीने में 160 बार सीज़फायर का उल्लंघन इसी साल हो गया है और 2,474 आपके चार साल के कार्यकाल का है, जो हमसे 500 प्रतिशत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिक और अर्द्धसैनिक बल के 340 जवान शहीद हुए हैं और 194 सिविलियन्स मारे गए हैं। आपका 56 इंच का सीना कहां गया? एक के बदले दस सिर लाएंगे और आज मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा और तकलीफ हुई है, मैं उस पीड़ा और दुख का इज़हार करना चाहता हूं कि जब आदरणीय अमित शाह जी बोल रहे थे, उनकी मेडन स्पीच थी। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक देश के इतिहास में पहली बार हुई, तो उस समय आप उन सैनिकों का अपमान कर रहे थे, जिन्होंने एक नहीं, दसियों बार सर्जिकल स्ट्राइक की। आप 1971 के युद्ध का अपमान कर रहे थे, जब दुनिया के नक्शे पर, भूगोल बदल कर, बंग्लादेश बनाया गया। ...(**व्यवधान**)... आप वीर सैनिकों का अपमान कर रहे थे ...(**व्यवधान**)... आप वीर सैनिकों का अपमान कर रहे थे, जिन्होंने शहादत दी, परन्तु फर्क इतना है कि हम देश के लिए जीते हैं, आप दल के लिए जीते हो। ...(**व्यवधान**)... पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, हम उसका जिक्र नहीं करते थे और अब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो आप उसका पोलिटिकल फायदा उठाते हो, क्योंकि आपको दल प्यारा है, हमको हिन्दुस्तान प्यारा है। यही आपमें और हममें फर्क है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने अपमान किया ...(**व्यवधान**)... आपने अपमान किया। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K RANGARAJAN): Please conclude. Time is over.

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मुझे एक या दो मिनट का समय दे दीजिए, तो ठीक है, वरना मैं कन्क्लूड करता हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं कन्क्लूड करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर शंकर साबलेः सर, इन्होंने प्रधान मंत्री जी का अपमान किया है। प्रधान मंत्री जी किसी के चरणों पर जा रहे हैं, यह कहकर ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K RANGARAJAN): You speak in your turn. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am on a point of order. Interruptions' time should be deducted and ample time should be given to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K RANGARAJAN): No, no; the disruption was only after his ten minutes. He started speaking only after his ten minutes. He did not disturb. Please conclude Tiwari Ji.

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। सर, इन्होंने इस देश के किसानों के साथ क्रूर मजाक किया है। इन्होंने कहा कि हमने एम.एस.पी. का 50 परसेंट बढ़ा दिया, लेकिन जो लागत थी उसे कम कर दिया है। इस तरह से तो बाज़ीगर भी हाथ की सफाई नहीं दिखाता जिस तरह हाथ की सफाई आपने दिखायी है। आपने उसे ड्योढ़ा किया, लेकिन जिसे ड्योढ़ा किया, उस की लागत को कम कर दिया। अगर यही सही है और यही पैमाना है, तो आपके राज्य में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इस बात का हमें जवाब चाहिए। आप के राज में पलायन क्यों हो रहा है, हमें इस का जवाब चाहिए।

दूसरे, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप आम आदमी की जेब पर डाका डालना बंद कर दें। आज का दो-तीन घंटे पहले का पेट्रोल का रेट रुपए 67 point something है और आपने आज पेट्रोल 73.08 रुपए के रेट पर बेचा है। अब 73 रुपए पेट्रोल है और 64 रुपए डीज़ल है। ...(**व्यवधान**)... इन्हें डीज़ल के रेट का पता नहीं है क्योंकि इन्हें किसान की हालत का पता नहीं है। ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है। इन्हें मालूम नहीं है कि डीज़ल सिंचाई में इस्तेमाल होता है, डीज़ल इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर में, डीज़ल फसल में मढ़ाई में इस्तेमाल होता है। इस तरह आप सब से ज्यादा डाका किसानों की जेब पर डाल रहे हैं।

महोदय, मैं अपनी बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि मैं इसे dying declaration नहीं कहूंगा, यह सरकार का मृत्यु पूर्व दिया गया बयान है।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब)ः माननीय वाइस-चेयरमैन साहब, माननीय प्रेसीडेंट साहब ने 29 फरवरी, 2018 को जो एड्रेस दिया है, मैं उसमें वर्ष 2018-19 में सरकार के विज़न का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज पर जो सब से ज्यादा thrust है, वह डा. अम्बेडकर जी के विज़न में दर्शाया गया है। The architect of our Constitution, Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar used to say that political democracy cannot survive without social and economic democracy. यही main trust है और demand भी है। जब हमारे बुजुर्ग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका नारा भी यही था।

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

अभी माननीय सदस्य और बी.जे.पी. के प्रधान ने बहुत बातें कही हैं, लेकिन मैं दो-तीन priroties पर बात कहूंगा। इस में major बात upliftment of weaker section है और जो सबसे बड़ी बात है, वह "जय जवान, जय किसान" के जय जवान के लिए कही गयी है। यह उनकी 70 साल पुरानी demand थी और जिस बात पर सब से ज्यादा thrust है, वह third page पर सब से front में दिया गया है। हम सब लोग यहां सदन में बैठे हैं, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि achievements के आने में तो time लगेगा और मैं इस पर गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो सही है कि farmer की बात तो कभी front page पर कभी नहीं आयी थी। इसलिए सोशल सेक्टर में जो किया है, वह तो मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य भी बोले हैं। अगर हम गरीबों के लिए कहें तो, 'जन-धन योजना' है, टॉयलेट योजना है, गैस सिलेंडर की योजना है, हाउसेज़ की है, बीमा योजना है, पेंशन योजना है, इलैक्ट्रिसिटी की योजना है। इसी प्रकार "जय जवान" के लिए वन रैंक वन पेंशन कर दी है, लेकिन जो किसान का प्वाइंट है, उसके लिए जो वायदा किया गया है कि 1.5 करेंगे, तो जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक हम 2002 करेंगे। इसके लिए प्रेज़ीडेंट साहब और इस सरकार का बहुत धन्यवाद। मैं अकेले फारमर्स पर ही ज्यादा ट्रस्ट करूंगा, लेकिन हमारे कंट्री के सामने प्रॉब्लम क्या है? मैं सभी से विनती करता हूं कि हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। आप कीचड़ तो तब उछालिए अगर एक ही पार्टी राज करती है। एक पार्टी ने 55 साल राज किया, जिसमें 40 साल अकेले एक पार्टी ने राज किया और दस साल यूपीए की सरकार ने राज किया। बीजेपी एंड एलाइन्स पार्टी ने 8 साल पहले राज किया और अब इसको तीन साल हो गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो दोनों ही साइड पर बैठे लोग हैं, ये राज करने वाले हैं। ये एलाइड में भी आ जाते हैं और यूपीए में भी आ जाते हैं। आप प्रॉब्लम को तो समझिए कि देश के सामने क्या प्रॉब्लम है। अगर यहां पर नारे लगाते रहेंगे और बाहर बहुत खुश होते रहेंगे, तो आप इनकी तरफ भी तो देखिए। देश की मुख्य प्रॉब्लम अन-इम्प्लायमेंट है। जो सेकंड प्रॉब्लम है, वह देश की पॉपुलेशन है। जो तीसरी प्राब्लम है और जिसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं, वह फारमर सेक्टर है। जो 4th प्रॉब्लम है, वह मल्टीपल इलैक्शन्स की है और 5th प्रॉब्लम इन सब चीजों को खत्म करने वाला करप्शन है। मैं इन सभी को शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगर अकेले फारमिंग सेक्टर को ले लें, तो अगर अब यह आबादी 50 per cent है, तो पहले हमारी 80 per cent आबादी फारमिंग सेक्टर में थी, इस देश को किसानों का देश कहा जाता है। हम इंडस्ट्री पर और व्यापार में भी इतना आगे नहीं बढ़ सके। मैं फारमिंग सेक्टर पर कहना चाहता हूं और एक रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं। The Report of the National Commission on Farmers (NCF), submitted to the previous United Progressive Alliance in October, 2006, had found a minimum fifty per cent profit formula for fixing MSPs by stating that the net take-home income of farmers should be comparable to those of civil servants. But in actual, please listen, शर्मा जी, मैं आपसे कह रहा हूं। यह आपकी रिपोर्ट है, but, in actual, the net take-home income of farmers is not even equal to class-IV employee of Government, whose monthly gross salary is between ₹ 25,000 to ₹ 40,000, depending upon the length of service rendered by him. आपको आंकड़ा देने के लिए, इसका आगे सुबूत क्या है, But farm income had increased merely

by 3.6 per cent, between 2000-01 and 2012-13. The Economic Survey of 2013 had pointed out that the average income of farmer was ₹ 20,000 in seventeen States. * "Per month income of farmers in 17 states is given in the survey of India of the year 2016. Earlier the commission set up by you had said that the earnings of a farmer are equivalent to a class 4 employee. These are not my words but fact stated by the commission in it's report. This fact is true because even PhD students are not interested in farming because a son of a farmer doesn't want to be a Class 4 employee. But this fact has been stated by the survey report. Whose fault is this i.e of those who have been ruling for four years or those who have ruled for 70 years.

Today in the country the crime is rapidly rising and robberies are taking place. What is the reason for this rise in crime. Is it due to overpopulation, unemployment or due to frustration amongst the youth. How will you solve these problems?"

मेरी विनती है। चेयरमैन साहब, मैं किसी को कहने की बजाय कोशिश करूंगा, कुछ सजेशन्स देना चाहूंगा कि जो प्राइसेज हैं, यह जो कहा गया है कि हम डेढ़ गुना दे चुके हैं, now, I come to the thrust points of the Price Policy of Rabi, 2017-18. मैं यह पीएयू की रिपोर्ट पढ़ रहा है। जो कमीशन कह रहा है, मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं कि, the Minimum Support Price of Rabi crops for 2017-18 is calculated on three basis. First is parity with the Wholesale Price Index. According to this, price of wheat becomes ₹ 1910/- per quintal. Second is parity with Input Index. According to that, the price becomes ₹ 1,988/- per quintal. And, third is the cost of cultivation per hectare. On the basis of various agricultural inputs such as fertilizer, seed, pesticides, labour charges, irrigation charges, machine charges and land rent, etc., used for crop production, the price becomes ₹ 2,180/- per quintal. The suggested price of wheat for 2017-18 by PAU or ICAR is more than this. The suggested wheat price is ₹ 2,180/- per quintal and the support price is ₹ 1,735/-. यह तो जो सजेस्ट किया गया, वह भी नहीं मिल रहा है, *"how will they give 1.5 times the price" तब यह बराबर किस प्रकार से हैं? यही तो suicide का रीज़न है। *First I will discuss the rabi crop because it is not being purchased and second is the kharif crop," "क्योंकि परचेज़ नहीं हो रही है।

महोदय, सेकंड बिन्दु खरीफ है। खरीफ में फॉर्मूला सेम है। मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, इस पर टाइम नहीं ज़ाया करूंगा, लेकिन the support price of paddy for 2017-18 is ₹ 1,590/- per quintal, जो हम दे रहे हैं, is ₹ 1,590/- है और जो सजेस्ट किया है, PAU ने, is ₹ 2,490/- *"This is the price difference of the paddy." The support price of cotton for 2017-18 is between ₹ 4,020 and ₹ 4,320/-. The suggested price according to this formula is ₹ 6,745/-. This is

*English translation of the original speech delivered in Punjabi.

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

the price gap. This is the reason for committing suicide. ...*(Time-bell rings)*... सर, मैं ऑफ दि सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलूंगा, मैं छोटे-छोटे, एक-एक प्वाइंट पर बोल रहा हूं। Now, I come to production of pulses, जो 22140.00 हज़ार टन है। हम इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं? यह 5420.25 हज़ार टन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि pulses, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, मैं आपसे 2015-16 की फिगर कह रहा हूं, मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स नहीं हैं, हम 22,300 करोड़ पर-ईयर pulses इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमने 2016-17 में 70,000 करोड़ ऑयल सीड्स इम्पोर्ट की हैं। मैं इनमें से यह कहना चाहता हूं कि अगर इतना पैसा इम्पोर्ट में जा रहा है, तो क्या इस देश में pulses नहीं हो सकती हैं, ऑयल सीड्स नहीं हो सकती हैं? यह सब-कुछ हो सकता है, अगर हम उनको एक्चुअल प्राइस दें और उसको परचेज करें। यह कितना बड़ा लॉस है? फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, जिससे देश में और गरीबी बढ़ रही है। हमारे फार्मर का पैसा वह फार्मर लेकर जा रहा है।

ऑनरेबल उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ सजेशन्स पर पाँच-छह लाइनें कहना चाहता हूं। मेरा यह सजेशन है कि अगर यह प्रॉब्लम हल करनी है, अगर उनको 1.5 गुना की फिगर देनी है, तो आपको प्राइस इंडेक्स ठीक करना पड़ेगा। जो प्राइस युनिवर्सिटी सजेस्ट करती है, आपको उसके मुताबिक प्राइस देना पड़ेगा। जो एक्चुअल प्राइस है, जो स्वामीनाथन फार्मूले के सी-2 फार्मूले के अनुसार है, ए-टू फॉर्मूले के अनुसर नहीं, बल्कि सी-टू फॉर्मूले के अनुसार जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसको देखना होगा।

महोदय, सैकंड प्वाइंट यह है कि स्टोरेज में 21 लाख मीट्रिक टन की अभी भी कमी है। सेकंड, जो परचेज़ वाली क्रॉप है, स्टेट्स करते हैं, ऑनली 6 परसेंट करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः सर, मैं एक या दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude. Please conclude.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः एक-एक लाइन में अपनी बात कहूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): No, no. You have exceeded your time. You have already taken two minutes extra.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः सर, जो क्रॉप परचेज़ हो रही है, वह सिर्फ स्टेट्स कर रही हैं, लेकिन उसका एफसीआई पूरा रेट नहीं दे रही। But until the entire cost is borne by Centre, the promise of procuring all crops will remain empty slogan, जो इसमें से रह जाएगा। तीसरा, जीएसटी जो है....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): So, I have to call the next Member.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः सर, तीसरा जीएसटी जो है, वह अभी भी किसान को ...(**व्यवधान**)... इसे खत्म करना चाहिए। जो आप ओपन ग्रीन मिशन लाए हैं, उसमें 500 करोड़ बहुत कम है, इसे कम से कम 2000 करोड़ करना चाहिए। जो इंश्योरेंस योजना है, उसमें पंजाब तो कवर होता ही नहीं है, जो फार्मुला है, उसका फार्मुला चेन्ज करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Okay. Please conclude. Please conclude. Bhunder Singhji, please conclude.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः सर, मैं एक-एक वर्ड में कहूंगा, तीन-चार प्वॉइंट ही रह गए हैं। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इसको 20 की जगह 30 और पंजाब में एग्रीकल्चर, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, ये तीन हमें पंजाब में देने चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude. You have taken a lot of time. Please.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः सर, मैं आपके जरिए यही कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छा एड्रेस पेश किया है, हर मसले को सामने लाया है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और गवर्नमेंट से विनती करते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन सही हो जाए, तो देश का भला हो जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you. The next speaker is Shri Ramkumar Verma.

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, जो 29 जनवरी, 2018 को संसद के संयुक्त सत्र में उनके द्वारा दिया गया, बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश के प्रधान मंत्री, जिनको मैं कहूंगा कि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के अंदर भी एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, उनके पास एक मिशन है, देश के प्रति और देश के करोड़ों-करोड़ लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने जो पिछले साढ़े तीन वर्षों में काम किए हैं, उन उपलब्धियों के साथ इसके अंदर यह भी बताया गया है कि भविष्य की हमारी क्या प्रतिबद्धता होंगी? अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और हमारे सम्माननीय पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने, डा. विनय सहस्रबुद्धे जी ने, मलिक जी ने बहुत विस्तृत रूप से बताया है और हर पहलू को टच किया है। उपसभाध्यक्ष जी, मेरे लिए कितना टाइम होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): You have ten minutes. You have consumed one minute. You still have nine minutes.

श्री राम कुमार वर्माः तो मैं डिटेल में न जाकर अपनी बात कहना चाहूंगा कि 70 वर्ष की आज़ादी के बाद आज हमारे देश में जब तक ऐसे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में निश्चित कार्य भी हुए हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की प्रारंभिक पंक्तियों में भी यह बताया

[श्री राम कुमार वर्मा]

गया है और जैसा हमारे माननीय विपक्ष के नेताओं, अनुभवी नेताओं ने कहा कि अमित शाह साहब ने कुछ नाम नहीं लिए, लेकिन, मैं नाम लेना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने डा. बी.आर. अम्बेडकर जी का नाम लिया।

(**श्री उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

उपसभापति जी, इसी के साथ मैं यह कहूंगा कि उनका नाम तो लिया और उसके साथ कहा गया कि देश के अंदर उन्होंने कहा था कि राजनैतिक लोकतंत्र के साथ में आर्थिक और सामाजिक, अगर लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र नहीं हुआ, तो यह देश के लिए ठीक नहीं होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने विपक्ष के बहुत सीनियर सदस्यों से, जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको देश की जनता ने नकारा है, उनको देश की जनता ने ignore कर दिया है। निश्चित है कि उनके अन्दर हताशा होगी। पूरे भारत के अन्दर माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रण किया था कि आने वाले समय में जब हम सत्ता में आएँगे, तो देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। साथ में जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो युवा निराशा में डूब रहे हैं, जो किसान हैं, महिलाएँ हैं, उनके उत्थान के लिए हम योजनाएँ लाएँगे, जिनसे वास्तविकता में उनका उत्थान हो। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब उस वर्ग की बात की जा रही है, उस वर्ग की केवल बात ही नहीं की जा रही है, बल्कि उस वर्ग के कार्य और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। जिस पार्टी ने 55 वर्ष तक शासन किया हो, आज जब इस देश से उसका पूरा का पूरा जो एकछत्र राज्य था, वह खत्म होने को है, तो स्वाभाविक है कि इससे उसकी तड़पन, उसका frustration प्रकट होता है। आज उन्होंने यह प्रयास किया कि अगर हम एक झूठ को सौ बार बोलें, तो सौ बार एक झूठ को बोलने से वह सत्य लगेगा और अगर हम इस तरह की बातें कहें, तो शायद भारत की जनता फिर गुमराह हो जाए। उसी को आधार बना कर उन्होंने वर्षों तक यही कहा। उन्होंने गरीबों के लिए यह सोचा कि गरीब को गरीब रहने दीजिए, भूखे को इतनी रोटी दीजिए कि वह अपना जीवनयापन कर ले, लेकिन उनको इतना साधन संपन्न न करें, जिससे आने वाले समय में वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के साथ-साथ शिक्षा के बल पर आगे आ जाएँ और उनको अपने अच्छे-बुरे की पहचान हो जाए।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किए हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। अभी जन-धन योजना की बात हो रही थी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, डा. बी.आर. अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उस गरीब के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। जन-धन योजना के द्वारा 32 करोड़ लोगों को खाते से जोड़ा गया और उनके अन्दर 73 हजार करोड़ उन गरीबों का पैसा बचत के रूप में आया। आज उनके अन्दर उनकी मेहनत की मजदूरी आती है। उस समय जब यह सरकार नहीं थी, देश के अन्दर त्राहि-त्राहि थी। यह त्राहि इतनी थी कि वे मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, चाहे मनरेगा के माध्यम से करें, चाहे भारत सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना के माध्यम से करें, लेकिन उनका पैसा दलाल और बिचौलियों के द्वारा उनको नहीं मिलता था। आज उन गरीबों के लिए इस देश का सौभाग्य है। आज नरेन्द्र मोदी जी के लिए मैं कहूंगा कि इस देश में बातें तो बहुत की

8.00 P.M.

गई थीं, लेकिन एक मसीहा के रूप में गरीबों के उत्थान के बारे में मैं कहूंगा कि उन्होंने जन-धन योजना के माध्यम से उनके आत्मसम्मान को बढ़ाया है। उन्होंने न सिर्फ उनको देश की बैंकिंग व्यवस्था, अर्थतंत्र से जोड़ा है, बल्कि उनकी मजदूरी का, मेहनत का जो पैसा है, जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जो वृद्ध जन हैं, उनके साथ-साथ हमारी विधवा माताएँ और बहनें हैं, उनकी पेंशन का पैसा भी उनको मिल रहा है। मैं उन लोगों से, जो आज कुछ ऐसा कहते हैं कि यह सरकार बातों से काम ले रही है, यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह महात्मा गाँधी जी का सपना, डा. बी.आर. अम्बेडकर जी का सपना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना नहीं था? ये आँकड़े हैं। मैं प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। यह चिंतन करने की बात है कि 3 करोड़ 20 लाख लोगों को गैस के चूल्हे दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 55 वर्ष के अपने कार्यकाल में आपने 3 करोड़ 20 लाख तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप किसी गाँव का आँकड़ा बता देंगे कि हमने तीन आदमियों को गैस के चूल्हे दिए हों, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा? साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जिस धुएँ में उस गरीब की माँ और बहन कार्य करती थीं, उससे उनका स्वास्थ्य खराब होता था, उनका आत्मसम्मान गिरा हुआ था। लेकिन आज इस देश के अंदर तीन करोड़ बीस लाख लोग, महिलाएँ और माताएँ ऐसी हैं, जिनको चूल्हे मिले हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; you can continue later on. ...*(Interruptions)*...

श्री रामकुमार वर्मा: इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मदद मिली है। अब टार्गेट रखा गया है कि और आठ करोड़ लोगों को ये दिए जाएंगे।

अगर हम प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की बात करें, दिव्यांग जनों की बात करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात करें, तो ये योजनाएं लागू हैं। एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। ...(**समय की घंटी**)... ऐसी बहुत सारी बाते हैं, जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा, मैं आपका अधिक टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको निराश किया, so, within my time I will complete my speech. ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have you concluded your speech? क्या आपकी स्पीच खत्म हो गई है?

SHRI RAMKUMAR VERMA: I will take only one minute. मैं कहना चाहूंगा कि आज वह समय आ गया है, जब विपक्ष के लोगों को भी सोचना चाहिए। वे मिलकर, सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करें और भारत सरकार ने जिस तरह की नीतियां बनाई हैं और जो निर्णय लिए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: क्या आपकी बात खत्म हो गई? अब आठ बज गए हैं।

श्री रामकुमार वर्मा: चाहे नोटबंदी का निर्णय हो, चाहे जीएसटी का निर्णय हो, चाहे one rank-one pension का निर्णय हो, उनके साथ सहयोग करते हुए, उस गरीब को उसका हक दिलवाने में अपना सहयोग दें न कि झूठे-सच्चे प्रचार करते हुए, उनको गुमराह करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आठ बज गए हैं, अब बैठ जाइए। Time is over.

श्री रामकुमार वर्मा: समाज आज समझ गया है, उसमें विवेक आ गया है, धन्यवाद।

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, there are four or five Special Mentions. If the House agrees, I will take up the Special Mentions.

Demand to take strict measures to protect the identity of whistleblowers in the country

SHRI CHUNIBHAI KANJIBHAI GOHEL (Gujarat): Sir, nowadays we are hearing a lot about the issue of protection of whistleblowers, especially in view of many incidents coming to light about victimization of such persons. It may be noted that in cases where the information is being provided by the RTI activists or other civilians about corruption in various Government establishments/entities, the said Departments are not taking appropriate action (by maintaining secrecy) on such specific cases and are merely forwarding the same to the concerned department/authority for clarification/comments. This not only gives a word of caution to the corrupt and facilitates them in escaping from being caught with proof but in certain cases results in identification and victimization of the whistleblower.

I am given to understand that the CVC has already issued a circular to protect interests of the whistleblowers and to maintain strict confidentiality thereof. However, as stated above, the Government Departments/entities are not following the spirit of the CVC circular.

Accordingly, in view of the above, I request DoPT to take cognizance of this all important issue and take appropriate action. Thank you.

Demand to declare potato as the National Vegetable and increase its Minimum Support Price

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): महोदय, जब भी देश में शाकाहारी भोजन का नाम आता है तो हर डाइनिंग पर सबसे पहले जिस सब्जी का वजूद दिखाई देता है उसका नाम आलू होता है,